



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 350]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 30, 2018/कार्तिक 8, 1940

No. 350]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 30, 2018/KARTIKA 8, 1940

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2018

**अंतिम जांच परिणाम**

**(मामला संख्या : ओ आई. 36/2017)**

**विषय :** इंडोनेशिया, थाइलैंड और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए 'अनकोटेड कॉपियर पेपर' के आयातों से संबंध में पाटनरोधी शुल्क संबंधी जांच।

**फा. सं. 6/32/2017- डीजीएडी.**—समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए :

- यतः, मै. जेके पेपर लिमिटेड, दि वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लि., तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड और बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड/बिल्ट ग्राफिक पेपर प्रोडक्ट्स लि. (जिन्हें आगे 'याचिकाकर्ता' या 'आवेदक' भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष संगत सूचना के साथ याचिका (जिसे आगे याचिका भी कहा गया है) दायर की है जिसमें इंडोनेशिया, थाइलैंड और सिंगापुर (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित अनकोटेड कॉपियर पेपर (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

2. और यत : प्राधिकारी ने याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अधिसूचना सं 6/32/2017-डीजीएडी दिनांक 2 नवम्बर, 2017 द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया, ताकि द्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

#### क. प्रक्रिया

3. संबद्ध जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है :

- (क) प्राधिकारी के संबंधित नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार जाँच की शुरुआत करने से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को सूचित किया।
- (ख) प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 2 नवम्बर, 2017 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
- (ग) प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादक/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग तथा अन्य घरेलू उत्पादकों को जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की प्रतियां भेजीं और उनसे जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना के 40 दिनों के भीतर लिखित में उनके विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।
- (घ) प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुरूप आवेदन के अगोपनीय अंश की एक-एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावासों को उपलब्ध कराई थी।
- (ङ) भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। संबद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पतों के साथ भेजी गई थी।
- (च) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्यातक की प्रश्नावली भेजी:-

#### थाईलैंड

- (i) डबल ए (पूर्व में एडवांस एग्रो)
- (ii) पंजापोल पल्प उद्योग
- (iii) फीनिक्स पल्प एंड पेपर
- (iv) एससीजी पेपर
- (v) ओजी पेपर थाईलैंड
- (vi) एनवायरमेंट पल्प एंड पेपर

#### सिंगापुर

- (vii) एएचएफ इंडस्ट्रीज
- (viii) एंडोमन ट्रेडिंग एंड शिपिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
- (ix) सेलमार्क एशिया पीटी लिमिटेड
- (x) एशिया पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड
- (xi) अलायंस पेपर एंड बोर्ड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
- (xii) एपीपीए (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड
- (xiii) चुआन एन पेपर प्रोडक्ट्स

#### इंडोनेशिया

- (xiv) पी.टी. पिंडो-डेली पल्प एंड पेपर मिल्स ("पीडी")

- (xv) इंदहा किआट पल्प और पेपर पीटी
- (Xvi) पीटी. पेब्रिकेरेटास जिवि किमिया टीबीके
- (Xvii) पीटी. इंदहा किआट पल्प एंड पेपर टीबीके।
- (Xviii) पीटी. लॉटर पापीरस पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री ("लॉटर")
- (Xix) पीटी. पुरीनुसा एकापरसाडा ("पुरीनुसा")
- (Xx) पीटी. रिया अंडालन पल्प एंड पेपर
- (छ) प्रत्युत्तर में, निम्नलिखित देशों के निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने निर्धारित प्रारूप में निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया:
- (i) पीटी रियाउ अंडलानकर्त्स, इंडोनेशिया
- (ii) पीटी अनुग्रह कर्टस यूटामा, इंडोनेशिया
- (iii) पीटी सटेरी विस्कोस इंटरनेशनल
- (iv) अप्रैल फाइन पेपर ट्रेडिंग पीटी लिमिटेड, सिंगापुर
- (v) अप्रैल इंटरनेशनल एंटरप्राइज पीटी लिमिटेड, सिंगापुर
- (vi) अप्रैल फाइन पेपर मकाओ वाणिज्यिक ऑफशोर लिमिटेड, मकाऊ
- (vii) पीटी इंदहा किआट पल्प एंड पेपर टीबीके, इंडोनेशिया
- (viii) पीटी पिंडो दिल्ली पल्प और पेपर मिल्स, इंडोनेशिया और
- (ix) पीटी पब्लीकर्टस जीवी किमिया टीबीके, इंडोनेशिया
- (x) डबल ए डबल ए (1991) पब्लिक कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
- (xi) एडवांस पेपर मिल 3 सह लिमिटेड, थाईलैंड
- (xii) फीनिक्स पल्प एंड पेपर पब्लिक कं, लिमिटेड, थाईलैंड
- (ज) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना के मंगाने हुए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावलियां भेजीं :
- (i) एलायड स्पेशियलिटी पेपर्स (इंडिया) प्रा. लिमिटेड
- (ii) भगवती एंटरप्राइज़
- (iii) एक्सेल एंटरप्राइज़
- (iv) के.सी. एक्जिम (पी) लिमिटेड
- (v) नरसिंहदास एंड कंपनी (पी) लिमिटेड
- (vi) न्यूटेक प्रिंट सर्विसेज- भारत
- (vii) पारस पेपर्स
- (viii) प्लस मार्केटिंग
- (ix) शाह देवजी शिविजी एंड कंपनी
- (x) शेथ ब्रदर्स
- (xi) श्री बालाजी उद्योग
- (xii) श्री चामुंडा एंटरप्राइजेज
- (xiii) मानक पेपर एंड बोर्ड इंडिया प्रा. लिमिटेड
- (xiv) सिकेम

(xv) टेनी जोस एंड एसोसिएट्स लिमिटेड

(xvi) यूनिक बिक्री निगम

(xvii) वाइट एरो ग्रुप आफ कंपनीज

(झ) प्रत्युत्तर में किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने उत्तर नहीं दिया और न ही प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया।

(ज) ऊपर उल्लिखित प्रतिवादी निर्यातकों और आयातकों के अलावा, जांच की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित पक्षों की ओर से कुछ विधिक अनुरोध प्राप्त हुए हैं। तथापि, निम्नलिखित पक्षों द्वारा आयातक/निर्यातक प्रश्नावली का कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

(i) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर

(ii) मदन पेपर प्रोडक्ट्स, बेंगलोर

(iii) एवरेस्ट मार्केटिंग, मदुरै

(iv) वीरा प्रिंटर, चेन्नई

(v) ग्लोबिनेट कंप्यूटर, हरूर

(vi) कोबस्टर ई-शॉप प्रा. लिमिटेड, चेन्नई

(vii) ओ-क्लॉक सॉफ्टवेयर प्रा. लिमिटेड, चेन्नई

(viii) आनंद विकतान प्रकाशक प्रा. लिमिटेड, चेन्नई

(ix) ताज पेपर मार्ट, चेन्नई

(x) बी. एस. एल. एंड कं, बेंगलोर

(xi) मैसर्स रोशन एंटरप्राइजेज, सलाम

(xii) रेशमा एजेंसिस, हनककोंडा

(xiii) हैम्स्टर ग्लोबल, त्रिशूर

(xiv) मैसर्स आरके एंटरप्राइजेज, सेलम

(xv) दीया डिस्ट्रीब्यूटर्स, चालाकुडी

(xvi) उदय इंटरनेशनल, हैदराबाद

(xvii) बिजकार्ड प्रिंट, मदुरै

(xviii) पलानीप्पा कॉटेज इंडस्ट्रीज, चेन्नई

(xix) स्वास्तिक पेपर कंपनी, चेन्नई

(xx) सत्य ट्रेडर्स, चेन्नई

(xxi) केटाकी इंजीनियरिंग प्रा. लिमिटेड, चेन्नई

(xxii) भावर पेपर एजेंसी, बेंगलोर

(xxiii) हिंदुस्तान एजेंसीज, गांधीनगर

(xxiv) कमलसरी पेपर्स, विजयवाड़ा

(xxv) कावेरी इंटरनेशनल, बेंगलोर

(xxvi) इश्वरी पेपर, विधूरुनगर

(xxvii) साई शक्ति, चेन्नई

(xxviii) जैनइम्पैक्स, हैदराबाद

(xxix) श्री दुर्गा पेपर स्टोर, त्रिची

- (xxx) मीनू पेपर मार्ट, शिवकाशी
- (xxxi) श्री बालाजी पेपर एंड स्टेशनरी, बैंगलोर
- (xxxii) श्री वेंकटेश ओवरसीज, हैदराबाद
- (xxxiii) यूनाइटेड पेपर मार्ट, करूर
- (xxxiv) धनलक्ष्मी पेपर ट्रेडर्स, कोविलपट्टी
- (xxxv) गोल्डन पेपर मार्ट, पठानमथिट्टा
- (xxxvi) जेएम एक्सिम, हैदराबाद
- (xxxvii) वर्धमान पेपर प्रोडक्ट्स, विजयवाड़ा
- (xxxviii) पेरिस पेपर एंड स्टेशनरी, चेन्नई
- (xxxix) संजय पेपर कंपनी, चेन्नई
- (xl) एएस पेपर, हैदराबाद
- (xli) सेंचुरी ट्रेडिंग कंपनी, कालीकट
- (xlii) शिवगिरी पेपर एंड स्टेशनरी, बैंगलोर
- (xliii) विजय ट्रेडर्स, विल्लुपुरम
- (xliv) एके ट्रेडर्स, चेन्नई
- (xlv) माइक्रो पेपर प्रोडक्ट्स, बैंगलोर
- (xlii) गणेश पेपर एजेंसियां, बैंगलोर
- (xlvi) वीएस और कंपनी, गुंटूर
- (xlviii) शालिमा पेपर मार्ट, कन्नूर
- (xlix) महाराष्ट्र पेपर कंपनी, पुणे
- (i) रमानी पेपर स्टोर, मुंबई
- (ii) डीएमएस निगम, मुंबई
- (iii) रूपम पेपर मार्ट, मुंबई
- (liii) एक्सेल पेपर, ठाणे
- (liv) प्रो मीडिया, चेन्नई
- (lv) बिमल पेपर, दिल्ली
- (lvi) तुलसी एंटरप्राइजेज, अहमदाबाद
- (lvii) सुदर्शन पेपर और बोर्ड प्रा. लिमिटेड, कोलकाता
- (lviii) शाह देवजी शिविजी एंड कं, मुंबई
- (lix) श्री चामुंडा मल्टीमैक्स, अहमदाबाद

- (ट) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंशों को हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण के लिए सार्वजनिक फाईल के रूप में उपलब्ध कराया था।
- (ठ) प्राधिकारी ने वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से जाँच अवधि समेत विगत तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के सौदा-वार व्योरे की जानकारी देने का अनुरोध किया था जो प्राधिकारी को प्राप्त हुए। प्राधिकारी ने सौदों की आवश्यक जाँच के बाद आयातों की मात्रा और अपेक्षित विश्लेषण की गणना के लिए डीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- (ड) सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में

संबद्ध वस्तु के उत्पादन की ईष्टतम लागत और उसे बनाने और बेचने की लागत और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार क्षति रहित कीमत (एनआईपी) ज्ञात की गई ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

- (ढ) इस प्राधिकारी द्वारा आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना का मौके पर सत्यापन के माध्यम से आवश्यक समझी गई सीमा तक भौतिक सत्यापन किया गया था। आवश्यक संशोधन के साथ केवल ऐसी सत्यापित सूचना जहां भी लागू हो, पर वर्तमान अधिसूचना के उद्देश्य से विश्वास किया गया है।
- (ण) वर्तमान पाटनरोधी जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि (पी ओ आई) 1 अप्रैल, 2016 से 31 जून, 2017 (15 महीने) तक है। हालांकि, क्षति की जांच की अवधि पर विचार 2013-14, 2014-15, 2015-16 और जांच की अवधि के रूप में किया गया है।
- (त) पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार प्राधिकारी ने 23 मार्च 2018 को हुई मौखिक सुनवाई में सभी हितबद्ध पक्षों को मौखिक रूप से विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी पक्षों से मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। पक्षकारों से विरोधी पक्षों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की प्रतियां लेने और उनके खंडन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।
- (थ) हितबद्ध पक्षों से प्राप्त लिखित अनुरोध/खंडन में दिए गए तर्कों पर वर्तमान अधिसूचना में विचार किया गया है।
- (द) इस जाँच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोधों को जहां वे संगत पाये गये, प्राधिकारी द्वारा इस अधिसूचना में समाधान किया गया है।
- (ध) गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच उनके गोपनीयता के दावे के पर्याप्त होने के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर इस प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय भाग उपलब्ध करायें।
- (न) जहां भी किसी हितबद्ध पक्ष ने वर्तमान जाँच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना जुटाने से मना किया अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराया या जांच में अत्यधिक बाधा डाली तो प्राधिकारी ने ऐसे पक्षों को असहयोगी माना है और "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर जाँच परिणामों को दर्ज किया है।
- (प) प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये विवरण के संबंध में प्राप्त सभी टिप्पणियों का भी उपयुक्त रूप से समाधान इस जांच परिणाम में किया गया है।
- (फ) संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनायी गई विनियम दर **1 अमरीकी डॉलर = 67.45** रुपये के रूप में लिया गया है।
- (ब) एक निर्यातक ने प्राधिकारी के प्रकटन विवरण में प्रस्तुत कुछ तथ्यों के संबंध में 20.07.2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 23.10.2018 के आदेश में विशेष रूप से प्रकटन विवरण के पैरा 40 के संबंध में लिखित में संगत अनुरोध, जो भी वह समझे, करने के लिए याचिकाकर्ता को दूसरा अवसर देते हुए शिकायत का समाधान किया। याचिकाकर्ता को यह अवसर प्रदान करने में माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के उस उत्तर में अनुरोध करने के लिए उत्तरदाता-शिकायतों की अनुमति भी दी। माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि यह पूरी प्रक्रिया तेजी से यथाशीघ्र पांच दिन के भीतर पूरी की जानी चाहिए और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम दे दिए जाने चाहिए।

## **ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**

### **ख.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

4. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:
- (क) वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद अनुमत सीमाओं के साथ निम्नलिखित आकारों की आयताकार शीटों में अन्कोटेड पेपर है (क) 210 x 297 मिमी. जिसे ए4 आकार के रूप में भी जाना जाता है, (ख) 297 x 420 मिमी. जिसे ए3 आकार के रूप में भी जाना जाता है, (ग) 215 x 345 मिमी. जिसे एफएस या कानूनी आकार के रूप में भी जाना जाता है। यह सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 4802 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। चार-अंकीय एचएसकोड को विचाराधीन उत्पाद के आयातों की पहचान के प्रयोजनार्थ प्रयोग किया गया है और उसका किसी भी तरह से यह अर्थ नहीं है कि याचिकाकर्ता ने चार-अंकीय स्तर पर आने वाले उत्पादों पर शुल्क लगाने की मांग की है।

- (ख) रीलों और बड़े आकार की शीटों में लिखने, मुद्रण या अन्य ग्राफिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किस्म के सभी प्रकार के कोटेड और अनकोटेड पेपर विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।

## **ख.2 अन्य हितबद्धपक्षों द्वारा किए गए अनुरोध**

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:
- (क) विचाराधीन उत्पाद काफी व्यापक है। 4 अंकों के एचएस कोड का संदर्भ असामान्य है। यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि क्या एचएस कोड 4802 के तहत सभी उत्पादन को या केवल निर्दिष्ट उत्पादों को पीयूसी के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।
- (ख) हितबद्ध पार्टियों ने स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध किया है कि क्या जंबो रोल्स / रीलों के रूप में आयातित अनकोटेड कापियर पेपर पीयूसी का हिस्सा है या नहीं।
- (ग) कोटेड कागज पीयूसी का हिस्सा नहीं है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए सौदा वार आयात आकड़ों से पता चलता है कि पीयूसी के कुल आयात का आकलन करते समय याचिकाकर्ताओं ने इन उत्पादों को भी शामिल किया है।

## **ख.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

6. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा बताए गए विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है। विचाराधीन उत्पाद के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि :
- (क) वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद अनुमत सीमाओं के साथ निम्नलिखित आकारों की आयताकार शीटों में अनकोटेड पेपर है (क) 210 x 297 मिमी. जिसे ए4 आकार के रूप में भी जाना जाता है, (ख) 297 x 420 मिमी. जिसे ए3 आकार के रूप में भी जाना जाता है, (ग) 215 x 345 मिमी. जिसे एफएस या कानूनी आकार के रूप में भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद का व्यावहारिक अर्थ सही आकार का अनकोटेड कापियर पेपर है।
- (ख) विचाराधीन उत्पाद को सामान्यतया (परंतु अनन्य रूप से नहीं) फोटोकॉपी या कापी पेपर के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसलिए उसे 'कापी पेपर', 'कापियर पेपर', 'फोटोकापी पेपर', 'मल्टीपर्पस पेपर', 'अनकोटेड कापियर पेपर', ए4 आकार के पेपर, ए3 आकार के पेपर या एफएस आकार के पेपर के रूप में आम तौर पर जाना जाता है। यह तैयार शीटों के रूप में होता है, जिसका भार अलग-अलग जीएसएम में होता है। यह सफेद कागज या एक पंच्ड पेपर हो सकता है और सतह की अलग-अलग रूप वाला होता है।
- (ग) पीयूसी के संबंध में प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क, यदि लागू किया जाए, तो रोलों, रीलों और बड़े आकार की शीटों का आयात किए जाने और भारत में उसे अपेक्षित आकार में काटने द्वारा संभावित परिवर्तन की गुंजाइश की जाँच की है। घरेलू उद्योग और निर्यातकों ने सूचित किया कि यह व्यवहार्य नहीं है क्योंकि कापियर पेपर को अपेक्षित आकार में और पैकड शीटों में खरीदा-बेचा जाता है। कटे और साइज के पैकों में बेचे गए और आयातित रोलों के पेपर के बीच लागत का अंतर काफी कम है, जिससे कोई कटिंग या पैकिंग प्रचालन वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य हो जाता है। इस प्रकार, विचाराधीन उत्पाद के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर रखे गए उत्पाद लेखन, मुद्रण या अन्य ग्राफिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त रीलों या बड़े आकार की शीटों के रूप में प्रयुक्त (अर्थात् ऊपर विनिर्दिष्ट आकारों से इतर) प्रकार का अनकोटेड पेपर है।
- (घ) विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क शीर्ष 4802 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और उत्पाद के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

## **ग. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति**

### **ग.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

7. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में जांच की प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :
- क) यह आवेदन मै. जेके पेपर लिमिटेड, मै. वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लि., मै. तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड और मै. बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो अपनी सहायक कंपनी बीजीपीपीएल में संबद्ध वस्तु का उत्पादन करती है, द्वारा दायर किया गया है।
- ख) आवेदकों ने न तो विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और न ही वे संबद्ध वस्तु के भारत में किसी आयातक या संबद्ध देश में किसी निर्यातक से संबंधित हैं और उन्होंने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

- ग) इंडियन पेपर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईपीएमए) आईपीएमए सदस्यों के साथ-साथ गैर-सदस्यों द्वारा उत्पादन के रिकॉर्ड बनाए रखता है। आईपीएमए द्वारा बनाए गए आंकड़ों के आधार पर अन्य भारतीय उत्पादकों के उत्पादन आंकड़े निर्धारित किए गए हैं।
- घ) याचिकाकर्ताओं ने अनजाने में याचिका के साथ टीएनपीएल के प्राधिकरण पत्र की अनदेखी कर दी है। टीएनपीएल की अनुपस्थिति में भी घरेलू उद्योग का हिस्सा 44% होगा, जिसे प्रमुख हिस्सा माना जाना चाहिए।
- ङ) यदि प्राधिकारी बीआईएलटी को ध्यान में नहीं रखते हैं, फिर भी घरेलू उद्योग के पास योग्यता है और यह देखा जाएगा कि घरेलू उद्योग में क्षति हो रही है।

## ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षों के अनुरोध

8. अन्य हितबद्ध पक्षों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :
- क) घरेलू उद्योग के संघटक अद्यतन जानकारी में दिए गए के समान नहीं हैं। अद्यतन याचिका याचिकाकर्ता कंपनी के नाम के रूप में बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बजाय बिल्ट ग्राफिक पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ("बीजीपीपीएल") (बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक) का नाम प्रदान करती है।
- ख) याचिका में सूचीबद्ध उत्पादकों के अलावा भारत में अनकोटेड पेपर के कई अन्य उत्पादक हैं। इन उत्पादकों के नाम सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं। घरेलू उद्योग ने इन उत्पादकों को नाम से नहीं पहचाना है और यह स्पष्ट नहीं है कि उत्पाद के कुल उत्पादन को निर्धारित करते समय इन उत्पादकों का उत्पादन पर विचार किया गया है।
- ग) याचिका में वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड और जेके पेपर लिमिटेड से प्राधिकरण और घोषणा शामिल थी। तमिलनाडु न्यूजप्रिंट और पेपर लिमिटेड और बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड से कोई प्राधिकरण पत्र नहीं था। आयात की अनुपस्थिति, भारत में पीयूसी के संबंधित आयातक की अनुपस्थिति, टीएनपीएल और बीआईएलटी के संबद्ध देशों में पीयूसी के संबंधित निर्यातक की अनुपस्थिति के बारे में कोई प्रमाणीकरण नहीं था।
- घ) पीओआई - अप्रैल 2017 से जून 2017 की अंतिम तिमाही के लिए अद्यतन पीओआई के लिए आयात की अनुपस्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग के किसी भी घटक से कोई प्रमाणीकरण नहीं है।
- ङ.) अन्य उत्पादकों के नामों के प्रकटीकरण नहीं किए जाने के कारण जांच समाप्त कर दी जानी चाहिए।

## ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

9. नियम 2 (ख) (में निम्नानुसार व्यवस्था है :-

*"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।*

10. वर्तमान आवेदन मै. जेके पेपर लिमिटेड, मै. वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लि., मै. तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड और बिल्ट ग्राफिक पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (बीजीपीपीएल) (बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लि. की सहायक कंपनी) द्वारा दायर किया गया है।
11. प्राधिकारी ने नोट किया कि बीजीपीपीएल अपने आंतरिक कारणों से पीओआई के एक बड़े हिस्से के लिए विषय वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहा था। इसलिए, वर्तमान जांच में मूल्यांकन के लिए घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में बीजीपीपीएल पर विचार करना उचित नहीं होगा। तदनुसार, प्राधिकारी मैसर्स जेके पेपर लिमिटेड, मैसर्स वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड और मैसर्स तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड को वर्तमान जांच के लिए घरेलू उद्योग के घटक के रूप में मानते हैं। उनमें से किसी ने भी पीओआई के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु आयात नहीं किया है और वे संबंधित उत्पाद के किसी निर्यातक या आयातक से भी संबंधित नहीं हैं।
12. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा भारत में कुल उत्पादन और घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन के संबंध में जमा की गई जानकारी की पुष्टि की है। घरेलू उद्योग के समान उत्पादन के कुल उत्पादन में 53% हिस्सेदारी है। भारत में अन्य घरेलू उत्पादकों में से किसी ने भी घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन का विरोध नहीं किया है।
13. इसलिए, प्राधिकारी का मानना है कि याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा रखता है। इस जांच के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता नियम 5 (3) के संदर्भ में योग्यता संबंधी अपेक्षा को पूरा करते हैं और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के संदर्भ में घरेलू उद्योग का गठन करते हैं।



**घ. गोपनीयता से संबंधित मुद्दे****घ.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध**

14. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के मुद्दों के लिए निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क) प्रतिवादी निर्यातकों / उत्पादकों के उत्तर में उनके प्रश्नावली के सार्वजनिक संस्करण में सार्थक जानकारी प्रदान न करके अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है।
- ख) याचिकाकर्ताओं ने ऐसी जानकारी गोपनीय के रूप में दावा की है, जिसकी गोपनीयता नियमों के तहत और प्राधिकारी की सतत परिपाटी के अनुसार अनुमति दी गई है।
- ग) याचिकाकर्ताओं ने आवेदन के अगोपनीय संस्करण को पर्याप्त विस्तार प्रदान किया है। कोई हितबद्ध पक्ष ऐसी जानकारी का कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं ला पाया है जिसके गोपनीय और गोपनीयता के रूप में दावा किया गया है, जो एडी नियमों के अनुसार उचित नहीं है।

**घ.2 हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध**

15. गोपनीयता के मुद्दों के लिए अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क) घरेलू उद्योग के प्रत्येक घटक के उत्पादन आंकड़े की गोपनीयता का दावा किया गया है।
- ख) याचिकाकर्ता ने कुल मांग और बाजार हिस्सेदारी के लिए वास्तविक आंकड़े भी उपलब्ध नहीं कराए हैं। ये आंकड़े समग्र हैं और इसलिए गोपनीय नहीं माना जा सकता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए सभी अंतिम जांच परिणामों में मांग और बाजार हिस्सेदारी के वास्तविक आंकड़े प्रकट किए गए हैं।
- ग) जहां भी संभव हो, लागत की जानकारी का अगोपनीय सारांश भी खुलासा किया जाना चाहिए। गोपनीयता के लिए दावा की गई जानकारी के पूर्ण मूल्यांकन के बिना स्वचालित रूप से दिया गया है।

**घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

16. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

17. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा सार्वजनिक फाइल के माध्यम से विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अगोपनीय संस्करण को नियम 6 (7) के अनुसार निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय संस्करण वाले अगोपनीय संस्करण उपलब्ध कराए।

18. घरेलू उद्योग और अन्य विरोधी हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध को प्रासंगिक मानी गई सीमा तक गोपनीयता के संबंध में प्राधिकारी द्वारा जांच की गई और तदनुसार संबोधित किया गया। गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता दावों को स्वीकार कर लिया है, जहां भी वांछित है और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षों को इसका खुलासा नहीं किया गया है। जहां भी संभव हो, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षों को गोपनीय आधार पर दायर की गई जानकारी के पर्याप्त अगोपनीय संस्करण प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया था। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय संस्करण को उपलब्ध कराया। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षों ने अपने व्यापार से संबंधित संवेदनशील जानकारी को गोपनीय माना है।

## इ. विविध अनुरोध

### इ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

19. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- क) अमेरिकी प्राधिकारियों ने पाया है कि इंडोनेशिया में सब्सिडी बनाए रखी जाती है। याचिकाकर्ताओं ने प्राधिकारी को उत्पादन की लागत के निर्धारण के संदर्भ में इन सब्सिडी पर विचार करने का अनुरोध किया है और क्या लागत संबंधी दावे विचाराधीन वस्तु के उत्पादन और बिक्री से जुड़ी लागत को उचित रूप से प्रतिबिंबित करते हैं।
- ख) प्राधिकारी को प्रतिकूल लाभप्रदता पर घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निर्यात के कारणों की जांच करनी चाहिए। घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में माल बेचने में असमर्थता के कारण ही विचाराधीन उत्पाद को निर्यात किया है।

### इ.2 अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध

20. अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- क) घरेलू उद्योग ने कहा है कि आईपीएमए पेपर उत्पादकों के उत्पादन आकड़ों का रख-रखाव करता है लेकिन घरेलू उद्योग ने अन्य उत्पादकों के बिक्री आकड़ों के स्रोत का खुलासा नहीं किया है।
- ख) नकद प्रवाह, उत्पादकता, मजदूरी, ब्याज पूर्व लाभ और कर (पीबीआईटी), मूल्यहास लागत और ब्याज लागत के संबंध में याचिका में कोई जानकारी नहीं है। उत्पादकता, नकदी प्रवाह, मजदूरी पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 11 के पैरा (iv) में निर्दिष्ट क्षति के अनिवार्य मापदंड हैं।
- ग) घरेलू उद्योग की क्षमता क्षति की जांच अवधि के दौरान निरंतर एकसमान रही है। मांग में वृद्धि के बावजूद क्षमता में इस तरह की स्थिरता का कारण यह है कि भारत में प्राथमिक कच्चे माल लकड़ी की लुगदी की कमी है। घरेलू उद्योग के घटकों में से एक, बीआईएलटी को हटाकर मांग और आपूर्ति के बीच अंतर बनाया गया था। इससे संबद्ध देशों से आयात में वृद्धि हुई। मांग और आपूर्ति के बीच अंतर अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ क्योंकि वे पहले से ही इष्टतम क्षमता पर परिचालन कर रहे थे और क्षमता के आगे विस्तार की कोई संभावना नहीं थी।
- घ) पाटनरोधी शुल्क को लागू करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा। यह शिक्षा को बढ़ावा देने और नोटबुक और अन्य शिक्षा सामग्री तक आसान पहुंच देने के लिए भारत सरकार की पहल के विरुद्ध होगा। इससे कागज की कीमत में वृद्धि होगी। इससे भारत सरकार के 'सर्व शिक्षा अभियान' (सभी के लिए शिक्षा की पहल) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो शैक्षिक सामग्री, किताबों आदि की आसान उपलब्धता सुनिश्चित कराना चाहता है। संबद्ध उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव छोटे पैमाने पर फोटोकॉपियर्स की आजीविका को प्रभावित करेगा जो कापियर पेपर की सस्ती कीमत पर निर्भर हैं।
- ङ) पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने पर उपयोगकर्ता उद्योग विपरीत शुल्क संरचना का सामना करेगा। किताबों, ब्रोशर जैसे डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर आयात शुल्क नहीं लगता है।
- च) विचाराधीन उत्पाद डाउनस्ट्रीम उत्पाद के लिए 60% लागत का गठन करता है। परिणामस्वरूप, पाटनरोधी शुल्क से न केवल उपयोगकर्ताओं के मार्जिन पर ही बल्कि अंतिम उपभोक्ता के लिए कीमतों पर भी प्रत्यक्ष परिणामी प्रभाव पड़ेगा।

### इ. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

21. विविध मुद्दों के संबंध में हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माने गए विभिन्न अनुरोधों पर निम्नानुसार विचार किया गया है:

- क) इंडोनेशिया सरकार द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी के मुद्दे के संबंध में, यह नोट किया गया है कि वर्तमान जांच एक पाटनरोधी जांच है और इसलिए, इंडोनेशिया सरकार द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी के संबंध में जांच नहीं की जाएगी।
- ख) इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी को हानिकर निर्यात के कारणों की जांच करनी चाहिए, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी को इस मुद्दे की जांच करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह घरेलू उद्योग द्वारा लगाए गए व्यावसायिक निर्णय के बारे में अनुमान नहीं लगा सकते हैं। यह भी नोट किया जाता है कि घाटे पर निर्यात करने के लिए कारण घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति अथवा कारणात्मक संबंध के आकलन के लिए प्रासंगिक मानदंड नहीं है।

**च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण**

22. धारा 9 क(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है :

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

**च.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

23. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क) याचिकाकर्ताओं ने संबद्ध देशों में उत्पादन लागत की सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर संबद्ध देशों में सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर याचिका में खपत मानक और कच्चे माल की कीमतें, परिवर्तन लागत और एसजीए निर्धारित किया गया है।
- ख) उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा दायर प्रश्नावली का उत्तर बिल्कुल अधूरा है और उन्होंने विभिन्न तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है और अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- ग) इंडोनेशिया में उत्पादक सरकार से विभिन्न सब्सिडियां प्राप्त कर रहे हैं। प्राधिकारी को सामान्य मूल्य निर्धारित करते समय सब्सिडी पर विधिवत रूप से विचार करना चाहिए और इंडोनेशियाई उत्पादकों के उत्पादन की लागत में संशोधन करना चाहिए।
- घ) याचिकाकर्ताओं ने निर्यात मूल्य निर्धारित करने के लिए डीजीसीआई एंड एस द्वारा प्रदान किए गए आयात आकड़ों पर भरोसा किया है। याचिकाकर्ताओं ने कारखाना-द्वार के निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय माल ढुलाई, पत्तन खर्च और बैंक शुल्क के लिए निर्यात कीमत को समायोजित किया है।

**च.2 अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध**

24. अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क) सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन का निर्धारण संबद्ध देशों से निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित होना चाहिए।
- ख) संबद्ध देशों में कीमत की जानकारी या साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थता के कारण याचिकाकर्ताओं ने इंडोनेशियाई उत्पादकों के सामान्य मूल्य का परिकलन उत्पादन लागत, खपत मानदंडों और घरेलू उद्योग की कच्चे माल की कीमतों का आकलन करके किया है।
- ग) सामान्य मूल्य के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई धारणाएं स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि इस तरह की धारणा इंडोनेशिया में तथ्यात्मक स्थितियों के कारण प्रतिनिधि नहीं होगी। इंडोनेशिया की कंपनियां सार्वजनिक कंपनियां हैं और उनके वित्तीय आकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।

**च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

25. धारा 9 (1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- क. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- ख. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(i) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ii) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

- ग प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी, उन्हें सलाह दी कि वे निर्धारित ढंग और तरीके से जानकारी प्रदान करें। हालांकि, निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों को छोड़कर, संबद्ध देशों के अन्य उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित प्रश्नावली का उत्तर देकर इस जांच में सहयोग नहीं किया है:

- (i) पीटी रियाउ अंडलानकर्त्स, इंडोनेशिया
- (ii) पीटी अनुग्रह कर्टस यूटामा, इंडोनेशिया
- (iii) पीटी एशिया प्रशांत रेयन (पूर्व में सैटरी विस्कोस इंटरनेशनल के रूप में जाना जाता है) इंडोनेशिया
- (iv) अप्रैल फाइन पेपर ट्रेडिंग पीटी लिमिटेड, सिंगापुर
- (v) अप्रैल इंटरनेशनल एंटरप्राइज पीटी लिमिटेड, सिंगापुर
- (vi) अप्रैल फाइन पेपर मकाओ कमर्शियल ऑफशोर लिमिटेड, मकाऊ
- (vii) पीटी इंदहा किआट पल्प एंड पेपर टीबीके, इंडोनेशिया
- (viii) पीटी पिंडो दिल्ली पल्प एंड पेपर मिल्स, इंडोनेशिया और
- (ix) पीटी पब्लीकर्टस जीवी किमिया टीबीके, इंडोनेशिया
- (x) डबल ए डबल ए (1991) पब्लिक कंपनी लिमिटेड
- (xi) एडवांस पेपर मिल 3 कंपनी लिमिटेड
- (xii) फीनिक्स पल्प एंड पेपर पब्लिक कंपनी लिमिटेड

#### च.4 इंडोनेशिया, सिंगापुर और थाइलैंड में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण

##### सामान्य मूल्य ज्ञात करने की सामान्य पद्धति

26. प्राधिकारी द्वारा सर्वप्रथम यह निर्धारित किया गया था कि क्या इन संबद्ध देशों में उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु की कुल घरेलू बिक्री भारत के संबद्ध वस्तु के निर्यात की तुलना में प्रतिनिधि थी।
27. इसके बाद, यह जांच की गई कि पाटन रोधी नियमों में अनुबंध 1 के पैरा 2 के संदर्भ में उनकी बिक्री व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के अधीन है या नहीं। जहां भी निर्माता / निर्यातकों ने घरेलू बाजार में किए गए विक्रय के लिए आवश्यक लेन-देन के विवरण प्रदान किए हैं और प्राधिकारी द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया है, वहां उनके घरेलू बाजार में बेची जाने वाली संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य को निर्धारित करने के लिए उक्त सूचना पर भरोसा किया गया है।
28. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया की जांच के लिए, संबंधित उत्पाद के उत्पादन की लागत की जांच उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के संदर्भ में और घरेलू बिक्री कीमत की तुलना में यह निर्धारित करने के लिए की गई थी कि घरेलू बिक्री व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में थी या नहीं। प्राधिकारी ने सहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी लेनदेनों पर विचार किया है, जहां लाभ बनाने के लेनदेन 80% से अधिक हैं और ऐसे मामलों में, जहां लाभदायक लेनदेन 80% से कम है, केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया गया है।

29. जहां भी कोई घरेलू बिक्री या संबद्ध वस्तु की कोई लाभदायक घरेलू बिक्री नहीं थी, तब सामान्य मूल्य का परिकलन प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत और लाभ के लिए उचित वृद्धि के साथ उत्पादन लागत के आधार पर किया गया था।
30. चूंकि उपर्युक्त उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है, इसलिए प्राधिकारी ने इन कंपनियों के संबंध में अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है जहां उत्तर स्वीकार किया गया है। संबद्ध देशों में गैर-सहयोगी निर्यातकों के मामले में, प्राधिकारी ने करार के अनुच्छेद 6.8 के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है।

### **इंडोनेशिया**

#### **पीटी रियाउ अंडलानकर्ट्स, पीटी अनुग्रहहर्टसटामा और पीटी एशिया प्रशांत रेयन, इंडोनेशिया, ("उत्पादक") ("अप्रैल समूह") के लिए सामान्य मूल्य**

31. अप्रैल समूह अर्थात् पीटी रियाउ अंडलान कर्ट्स ("आरएके"), पीटी अनुग्रहहर्टसटामा ("एकेयू") और पीटी एशिया पेसिफिक रेयन ("एपीआर") में उत्पादकों द्वारा दायर उत्तर से, प्राधिकारी ने नोट किया कि पीओआई के दौरान सभी कंपनियों ने घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री की है। तथापि, पीओआई के दौरान केवल आरएके और एकेयू द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद को भारत में निर्यात किया गया है। एपीआर ने पीओआई के बाद अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। पीओआई के दौरान घरेलू बाजार में एपीआर द्वारा बेचा जाने वाला उत्पाद परीक्षण उत्पादन से बाहर था। चूंकि, एपीआर ने पीओआई के बाद वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया, इसलिए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य निर्धारण के प्रयोजनार्थ एपीआर की घरेलू बिक्री पर विचार नहीं किया है।
32. यह नोट किया गया है कि आरएके ने \*\*\* अमरीकी डालर मूल्य के \*\*\* एमटी और एकेयू ने \*\*\* अमरीकी डालर मूल्य के \*\*\* एमटी की बिक्री घरेलू बाजार में की है। प्राधिकारी ने आरएके और एकेयू द्वारा की गई घरेलू बिक्री की जांच की है और नोट किया कि भारत के विचाराधीन उत्पाद के निर्यात की तुलना में घरेलू बाजार में बिक्री प्रतिनिधि है।
33. अतः, प्राधिकारी ने आरएके और एकेयू की घरेलू बिक्री के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने का निर्णय लिया है। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की लागत के संदर्भ में घरेलू बिक्री लेनदेन के लाभ को निर्धारित करने के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया। यदि लाभ बनाने के लेनदेन 80% से अधिक हैं तो प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी लेनदेनों पर विचार किया है और यदि लाभदायक लेनदेन 80% से कम है, तो सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री को ध्यान में रखा जाता है।
34. इस मामले में, व्यापार की सामान्य प्रक्रिया जांच के आधार पर, सभी घरेलू बिक्रियां सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए ली गई हैं, क्योंकि लाभदायक बिक्री 80% से अधिक थी। आरएके और एकेयू ने अंतर्देशीय परिवहन, हैंडलिंग और अन्य खर्चों, समुद्री भाड़ा (एक द्वीप से दूसरा), बीमा, क्रेडिट लागत, विज्ञापन, एफओसी पेपर/रीबेट/छूट और जकार्ता कार्यालय के खर्चों के लिए समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा इसकी अनुमति दी गई है। हालांकि, विज्ञापन खर्चों और जकार्ता कार्यालय के खर्चों के समायोजन को सीधे घरेलू बिक्री से संबंधित नहीं होने के कारण प्राधिकारी ने स्वीकार नहीं किया है। तदनुसार, भागीदार उत्पादकों के लिए कारखाना-द्वार स्तर पर सामान्य मूल्य आरएके और यूएसडी के लिए प्रति मीट्रिक टन \*\*\* अमरीकी डालर एकेयू के लिए \*\*\* अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन के रूप में निर्धारित किया गया है। एपीआरआईएल समूह के लिए भारित औसत सामान्य मूल्य \*\*\* अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन है।

#### **पीटी रियाउ अंडलानकर्ट्स, पीटी अनुग्रहहर्टसटामा और पीटी एशिया प्रशांत रेयन, इंडोनेशिया, ("उत्पादक") और उनके संबंधित निर्यातकों अप्रैल फाइन पेपर ट्रेडिंग पीटी लिमिटेड, सिंगापुर, अप्रैल इंटरनेशनल एंटरप्राइज पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर, अप्रैल फाइन पेपर मकाओ कमर्शियल ऑफशोर लिमिटेड, मकाऊ ("निर्यातक") के लिए निर्यात कीमत**

35. एपीआरआईएल समूह में उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा दायर उत्तर से, प्राधिकारी ने नोट किया है कि अप्रैल फाइन पेपर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (एएफपीटी) और अप्रैल इंटरनेशनल एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड (एआईई) ने पीटी रिया अंडलान कर्ट्स (आरएके) द्वारा भारत में उत्पादित विचाराधीन उत्पाद को प्राप्त किया है। पीओआई के दौरान अप्रैल फाइन पेपर मकाओ कमर्शियल ऑफशोर लिमिटेड, मकाऊ (एएफपीएम) ने भारत में पीटी अनुग्रहहर्टसटामा (एकेयू) द्वारा निर्मित उत्पाद को निर्यात किया है। भारत में सभी निर्यात असंबद्ध ग्राहकों के लिए किए गए हैं।
36. यह उल्लेखनीय था कि आरएके और एकेयू उपर्युक्त निर्यातकों के माध्यम से उनके द्वारा उत्पादित उत्पाद और अन्य सभी उत्पादों को उत्पादित कर रहे हैं। यह भी नोट किया गया कि कुछ मामलों में, विचाराधीन उत्पाद सिंगापुर को बार्जी पर निर्यात किया जाता है और फिर इसे भारत और अन्य देशों के निर्यात के लिए सिंगापुर में उतार दिया जाता है और लोड किया जाता है।

37. तदनुसार, प्राधिकरण ने कारखाना-द्वारा निर्यात कीमत को असंबंधित भारतीय ग्राहकों की कीमत पर विचार करते हुए ज्ञात किया है और इंडोनेशिया में अंतर्देशीय भाड़ा, पत्तन हैंडलिंग शुल्क, क्रेडिट लागत, छूट, समुद्री माल ढुलाई, बार्जिंग लागत, सिंगापुर में हैंडलिंग व्यय, एसजीए व्यय और संबंधित निर्यातकों का लाभ, बैंक शुल्क, और भारतीय कार्यालय के जी एंड ए खर्च के लिए समायोजन किए गए हैं। निर्यात कीमत आरएके के लिए \*\*\* अम.डा. प्रति मीट्रिक टन और एकेयू के लिए \*\*\* अम.डा. प्रति मीट्रिक टन के रूप में निर्धारित की गई है। एपीआरआईएल समूह के लिए भारित औसत कारखाना-द्वारा निर्यात \*\*\* अमरीकी डालर प्रति एमटी पर निर्धारित किया जाता है।

**मैसर्स पीटी इंदहा किएट पल्प एंड पेपर टीबीके, इंडोनेशिया, पीटी पिंडो दिल्ली पल्प एंड पेपर मिल्स, इंडोनेशिया और पीटी पब्रीकर्टस जीवी किमिया टीबीके, इंडोनेशिया ("उत्पादक") ("एपीपी ग्रुप") के लिए सामान्य मूल्य**

38. एपीपी ग्रुप में उत्पादकों अर्थात्, मैसर्स पीटी इंदहा किएट पल्प एंड पेपर टीबीके, पीटी पिंडो दिल्ली पल्प एंड पेपर मिल्स और पीटी पब्रीकर्टस जीवी किमिया टीबीके, इंडोनेशिया, द्वारा दायर उत्तर से, प्राधिकारी ने नोट किया कि सभी कंपनियों ने पीओआई के दौरान घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री की है।
39. तथापि, निर्यात कीमत निर्धारण में उल्लिखित कारणों से, प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया है कि एपीपी समूह द्वारा दायर प्रतिक्रिया को स्वीकार न किया जाए और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाए।

**मैसर्स पीटी इंदहा किएट पल्प एंड पेपर टीबीके, इंडोनेशिया, पीटी पिंडो दिल्ली पल्प एंड पेपर मिल्स, इंडोनेशिया और पीटी पब्रीकर्टस जीवी किमिया टीबीके, इंडोनेशिया ("एपीपी ग्रुप") के लिए निर्यात कीमत**

40. एपीपी समूह अर्थात् मै. पीटी इंदहा किएट पल्प एंड पेपर टीबीके, (आईके) पीटी पिंडो दिल्ली पल्प एंड पेपर मिल्स (पीडी) और पीटी पब्रीकर्टस जीवी किमिया टीबीके, (टीके) इंडोनेशिया में उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर उत्तर से, प्राधिकारी ने नोट किया है कि पीओआई के दौरान सभी कंपनियों ने सीधे तथा असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से भारत को उत्पाद का निर्यात किया है। आईके ने या तो सीधे या चीन या हांगकांग और सिंगापुर में असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से \*\*\* अम.डा. मूल्य के \*\*\* मीट्रिक टन का निर्यात किया है। इसी प्रकार, पीडी ने \*\*\* अम.डा. मूल्य के \*\*\* एमटी का निर्यात किया था और टीके ने \*\*\* अम.डा. मूल्य के \*\*\* एमटी का निर्यात किया था। जैसा कि उत्पादक द्वारा सूचित किया गया है, चीन और हांगकांग के निर्यातकों ने वस्तुओं को मैसर्स लीकोनफील्ड, सिंगापुर को बेच दिया, जो एक असंबंधित निर्यातक है। इन निर्यातकों के माध्यम से भारत में निर्यात आईके के लिए लगभग 39%, पीडी के लिए 43% और टीके के लिए 32% है। इन असंबद्ध निर्यातकों में से एक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है और प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है। यह देखते हुए कि इन असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से निर्यात काफी अधिक है, प्राधिकारी ने एपीपी समूह द्वारा प्रस्तुत उत्तर को अस्वीकार करने का निर्णय लिया है और इसके बजाय उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित करते हैं।

**इंडोनेशिया से असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य**

41. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि इंडोनेशिया के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है इसलिए इंडोनेशिया में सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने निम्न निर्यात कीमत को \*\*\* अम.डा./एमटी के रूप में निर्धारित किया है, जबकि संगत सामान्य मूल्य \*\*\* अम.डा./मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है।

**थाईलैंड**

**डबल ए के लिए सामान्य मूल्य**

42. डबल ए ग्रुप अर्थात् डबल ए (1991) पब्लिक कंपनी लिमिटेड ('डबल ए') और एडवांस पेपर मिल 3 कंपनी ('एपीएम 3') थाईलैंड में उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर से, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एपीएम 3 केवल पीयूसी का विनिर्माता है और उसने घरेलू बाजार में बिक्री के लिए अपने सभी उत्पादों को डबल ए को बेच दिया और डबल ए के नाम पर निर्यात किया है। "व्यापार की सामान्य प्रक्रिया (ओसीटी)" जांच के प्रयोजनार्थ उत्पादक एपीएम 3 के उत्पादन की लागत पर डबल ए ग्रुप की भारित औसत लागत की गणना के लिए विचार किया गया है। यह देखा जाता है कि मैसर्स डबल ए ने पीओआई के दौरान घरेलू बाजार में \*\*\* टीएचबी मूल्य की \*\*\* एमटी मात्रा बेची है। तथापि, यह भी नोट किया जाता है कि डबल ए ने \*\*\* टीएचबी मूल्य की \*\*\* एमटी (लगभग 11%) मात्रा को अपने संबंधित व्यापारियों के माध्यम से और \*\*\* टीएचबी मूल्य की \*\*\* एमटी को असंबद्ध ग्राहकों को बेचा है। तथापि, इन संबंधित पक्षकारों की बिक्री के लिए पहले स्वतंत्र ग्राहक को पुनर्विक्रय कीमत निर्यातक द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसलिए, उपर्युक्त जानकारी के अभाव में प्राधिकारी इस समूह के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने में असमर्थ है।
43. तदनुसार, प्राधिकारी ने डबल ए समूह द्वारा प्रस्तुत उत्तर को स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

**डबल ए समूह के लिए निर्यात कीमत**

44. उपर्युक्त कारणों से, प्राधिकारी ने डबल ए समूह के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया है।

**फीनिक्स पल्प और पेपर पब्लिक कं, लिमिटेड, थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य**

45. उत्पादक मै. फीनिक्स पल्प एंड पेपर पब्लिक कंपनी लिमिटेड ("पीपीपीपीसी") थाईलैंड द्वारा दायर उत्तर से प्राधिकारी ने नोट किया कि पीपीपीपीसी केवल पीयूसी का उत्पादक है और समस्त बिक्री इसकी संबंधित कंपनी थाई पेपर कं, लिमिटेड (टीपीसी) को की गई थी। टीपीसी घरेलू और निर्यात बाजार में पीयूसी बेचता है। यह भी नोट किया जाता है कि पीपीपीपीसी द्वारा दायर उत्तर अधूरा है और परिशिष्ट -4, 5, 6, 7 और 9 जमा नहीं किया गया है। इसके अलावा, टीपीसी द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अलावा, सत्यापन के लिए प्राधिकारी द्वारा अनुरोध किए गए कुछ सहायक दस्तावेजों पर दावा किया गया है कि वे प्राधिकारी को भेजे गए हैं, लेकिन वे कभी नहीं पहुंचे। तदनुसार, प्राधिकारी पीपीपीपीसी द्वारा दायर उत्तर को स्वीकार न करने का निर्णय लिया है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।

**फीनिक्स पल्प एंड पेपर पब्लिक कं, लिमिटेड, थाईलैंड के लिए निर्यात कीमत**

46. उपर्युक्त कारणों से, प्राधिकारी ने पीपीपीपीसी के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया है।

**थाईलैंड से असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य**

47. प्राधिकारी ने नोट किया कि चूंकि थाईलैंड के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातकों ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। थाईलैंड में सभी असहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि सामान्य मूल्य \*\*\* अमरीकी डालर/ मीट्रिक टन है और निवल निर्यात कीमत \*\*\* अमरीकी डालर/एमटी के अनुरूप है।

**सिंगापुर**

48. रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी से, प्राधिकारी ने नोट किया कि सिंगापुर में विचाराधीन उत्पाद का कोई उत्पादक नहीं है। इंडोनेशिया में निर्मित उत्पाद को कभी-कभी सिंगापुर में उतार दिया जाता है और फिर सिंगापुर से भारत में निर्यात किया जाता है। सिंगापुर में निर्यातकों ने इस जांच में उत्तर दिया है और इंडोनेशिया के उत्पादकों के साथ सिंगापुर के इन निर्यातकों के लिए पहले ही अलग पाटन मार्जिन निर्धारित कर दिया गया है। इसलिए, प्राधिकारी सिंगापुर से निर्यातकों के लिए कोई अलग पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं कर रहे हैं।

**च.5 पाटन मार्जिन तालिका**

49. संबंधित संबद्ध देशों के सभी निर्यातकों/ उत्पादकों के लिए पीओआई के दौरान पाटन मार्जिन को नीचे दी गई तालिका में यथा निर्धारित किया गया है:

क्र. सं.	उत्पादक देश	उत्पादक	सामान्य मूल्य अम.डा./एमटी	निर्यात कीमत अम.डा./एमटी	पाटन मार्जिन अम.डा./एमटी	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज %
1.	इंडोनेशिया	1. पीटी रियाउ अंडलनकेरटास, 2. पीटी अनुग्रहकेरटास यूटामा 3. पीटी एशिया पेसिफिक रेयान	***	***	***	***	25-35
2.	इंडोनेशिया	सभी अन्य	***	***	***	***	50-60
3.	थाईलैंड	सभी निर्यातक	***	***	***	***	0-10

**ख. क्षति आकलन और कारणात्मक संबंध****ख.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन**

50. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- i) बी आई एल टी/ बी जी पी पी एल अन्य तथ्यों के कारण क्षति झेल रहे हैं किंतु पाटित आयातों ने कंपनी की क्षति को गहन किया गया है और अधिक क्षति की आशंका भी उत्पन्न की है।
- ii) बी आई एल टी/ बी जी पी पी एल के बिना भी घरेलू उद्योग का निष्पादन दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने क्षति का सामना किया है जैसा कि बी आई एल टी/ बी जी पी पी एल को निकालकर बिना घरेलू उद्योग की क्षति सूचना से देखा जा सकता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी यह स्थापित करने के लिए बी आई एल टी/ बी जी पी पी एल को सम्मिलित न कर घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच कर सकते हैं कि क्या घरेलू उद्योग का निष्पादन बी आई एल टी/ बी जी पी पी एल के बिना भी पाटन के ह्रास दर्शाता है।
- iii) पाटित आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन उचित है क्योंकि एक से अधिक देशों से निर्यातक पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध – II (iii) के अनुसरण में संबद्ध उत्पादन का पाटन कर रहे हैं।
- iv) क्षति अवधि में संबद्ध वस्तुओं की मांग बढ़ी है। संबद्ध देशों से आयात कुल रूप में और सापेक्ष रूप में बढ़े हैं और पी ओ आई के दौरान उल्लेखनीय रूप से उच्च रहे हैं।
- v) बी आई एल टी/ बी जी पी पी एल द्वारा छोड़े गए बाजार को आयातों द्वारा अपनाया गया है। पी ओ आई में आयातों में पिछले वर्ष की तुलना में 748 आधार बिंदुओं की वृद्धि हुई है। जबकि घरेलू उत्पादकों की अन्य बिक्रियों में तदनुसूची अवधि के दौरान केवल 14 आधार बिंदुओं की वृद्धि हुई है।
- vi) पी ओ आई में संबद्ध देशों से आयात कीमत में लागतों में तदनुसूची गिरावट के बिना तीव्र गिरावट आई है। मांग- आपूर्ति अंतर को उचित कीमतों पर आयातों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। निकट भविष्य में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों पर आयातों का ह्रास और न्यूनीकरण प्रभाव पड़ने की संभावना है।
- vii) आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। 2014-15 के अतिरिक्त, पूरी क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमतें घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूलियों से कम रही हैं। आयातों की पहुंच कीमत भी घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से निम्न है।
- viii) घरेलू उद्योग पर घरेलू बाजार में पर्याप्त मांग के बावजूद वित्तीय हानि उठाकर निर्यात करने का दबाव है।
- ix) घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बाजार हिस्से और बिक्रियों में 2015-16 तक वृद्धि हुई है और उसके पश्चात पी ओ आई में इसमें गिरावट आई। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में 2014-15 में आधार वर्ष से गिरावट आई है, तत्पश्चात 2015-16 में इसमें वृद्धि आई और पी ओ आई में एक बार फिर गिरावट आई।
- x) संबद्ध देशों से आयातों का बाजार हिस्सा, जो आधार वर्ष में केवल 1.19% था, पी ओ आई में बढ़कर 10.53% हो गया।
- xi) घरेलू उद्योग आधार वर्ष और 2014-15 में वित्तीय हानियों का सामना कर रहा था। घरेलू उद्योग ने 2015-16 के बाद से लाभ अर्जित करना आरंभ कर दिया। नकदी प्रवाह ने भी समान प्रवृत्ति का अनुसरण किया है। घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभों में वृद्धि कच्ची सामग्री लागत में कमी और एग्री फार्मिंग में निवेश करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रयासों के कारण है। घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त किए गए लाभ अभी भी बहुत सांकेतिक है। आर ओ आई देश में औसत बैंक दरों से काफी नीचे है। विदेशी उत्पादकों द्वारा अर्जित लाभों का स्तर, जो उल्लेखनीय रूप से उच्च है, पर बेंचमार्क के रूप में विचार किया जा सकता है।
- xii) पी ओ आई में घरेलू उद्योग के पास माल सूची में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उचित लाभ के न होने पर पूंजी जुटाने की क्षमता में कमी हुई है। नियोजनकर्ताओं की संख्या में मामूली गिरावट आई है और अदा किए गए वेतनों में वृद्धि हुई है।
- xiii) घरेलू उद्योग कीमतों के लिए उत्तरदायी एकमात्र कारक आयात कीमतें और घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत हैं। संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन उल्लेखनीय है।
- xiv) घरेलू उद्योग को क्षति का जोखिम है। 2015-16 की तुलना में पी ओ आई में आयात लगभग 370% बढ़े हैं। संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के प्रमुख उत्पादकों के पास उल्लेखनीय उत्पादन क्षमता है। यू. एस. ने चीन जन. गण. से आयातों पर समकक्ष शुल्क लागू किया है, जो निकट भविष्य में भारत में आयातों में वृद्धि का सुझाव देता है। निर्यातक देशों से उत्पादक कीमतों के रूप में भारतीय बाजार को अत्यंत आकर्षक पा रहे हैं।
- xv) एसियान देशों के साथ हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौते के परिणामस्वरूप आयातों में वृद्धि हुई है। यह कल्पना करना भी उचित है कि संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास उल्लेखनीय क्षमता उपलब्ध है। संबद्ध देशों में उत्पादक निर्यातों उन्मुखी हैं। "ग्लोबल आउटलुक फॉर कट-साइज अनकोटिड फ्रेश शीट पेपर मार्केट, 2015" अध्ययन इंडोनेशियाई उत्पादकों के उच्च व्यापार उन्मुखीकरण को दर्शाता है। थाइलैंड के उत्पादक भी



अत्यधिक निर्यात उन्मुखी हैं क्योंकि कुल अनकोटिड लकड़ी मुक्त उत्पादन का एक तिहाई भाग निर्यातों के लिए अभिप्रेरित है। पूरे विश्व में उल्लेखनीय अधिशेष सामग्री मौजूद है जो इन देशों को कम कीमतों पर निर्यात करने के लिए विवश करती है।

- xvi) घरेलू उद्योग के आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है। विचाराधीन उत्पादन, व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियां, अन्य घरेलू उत्पादकों के निष्पादन आदि के खपत के पैटर्न में महत्वपूर्ण परिवर्तन जैसे कोई अन्य कारक विद्यमान नहीं है। निम्न कीमतों पर आयातों में वृद्धि, जो घरेलू उद्योगों की लागत से निम्न है, आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करती है।
- xvii) लाभ में वृद्धि, कृषि आधारभूत संरचना में निवेश के द्वारा इसकी लागत को कम करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा अपनाए गए बहुत से आयातों के परिणामस्वरूप है।
- xviii) प्रतिवादी निर्यातक एशियाई मांग का 45% स्थापित करते हैं और संबद्ध वस्तुओं की कीमत निर्धारित करने में सक्षम है।

## छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निवेदन

51. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं-

- i) थाइलैंड से आयातित संबद्ध वस्तुएं, थाईलैंड में उत्पादकों द्वारा बेचे गए बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद के कारण अन्य संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा नहीं करतीं।
- ii) संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि का उचित संदर्भ में विश्लेषण किए जाने की जरूरत है आयातों की मात्रा में वृद्धि वास्तव में महत्वपूर्ण क्षति के निर्धारण को लागू अथवा उसका समर्थन नहीं करती।
- iii) आयातों के संबंध में किसी भी दावे के प्रत्येक सौदे के आयात आंकड़ों द्वारा समर्थित किए जाने की आवश्यकता है। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए सौदा दर सौदा संबंधी आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं क्योंकि इनमें गैर पीयूसी उत्पाद भी शामिल हैं।
- iv) अद्यतन याचिका के प्रोफार्मा IV ख में उपलब्ध कराई गई कीमत कटौती की संगणना गलत है। संबद्ध देशों से आयातों के लिए पहुंच मूल्य निर्धारणीय कीमत की तुलना में निम्न है। किसी भी स्थिति में, पहुंच मूल्य निर्धारणीय मूल्य से कम नहीं हो सकता।
- v) सही परिकलन करने के पश्चात परिकलित कीमत कटौती या तो ऋणात्मक होगी अथवा न्यूनतम होगी।
- vi) कीमत कटौती से संबंधित दावा असंगत है क्योंकि पीओआई में आयात कुल मांग का केवल 8% अधिग्रहित करते हैं और कुल मांग का 92% धारित करने वाले घरेलू उत्पादकों के समान घरेलू उत्पाद पर कोई कीमत दबाव नहीं डालते।
- vii) घरेलू उद्योग ने याचिका में स्वीकार किया है कि आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में हास या न्यूनीकरण नहीं कर रहे हैं। घरेलू उद्योग पी ओ आई में अपनी बिक्री कीमत को 2013-14 में 100 से बढ़ाकर 108 करने में सक्षम है जबकि समान अवधि के दौरान बिक्रियों की लागत 100 से मामूली रूप से कम होकर 99 हो गई। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि किसी प्रकार का कोई कीमत हास अथवा न्यूनीकरण नहीं है।
- viii) आयात वितरक स्तर पर किए जाते हैं जबकि घरेलू बिक्रियां डीलर स्तर पर की जाती हैं। इसलिए, कीमत कटौती का निर्धारण बाजार के विभिन्न स्तरों पर किया गया है।
- ix) क्षति के आकलन से संबंधित प्रावधान में विशेष रूप से यह जरूरी है कि बिक्रियां, लाभ आउटपुट, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेशों पर आय अथवा क्षमता के उपयोग में "गिरावट" दर्शाई जानी चाहिए।
- x) संगत आर्थिक पैरामीटरों के मूल्यांकन के आधार पर घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। घरेलू उत्पादन के बाजार हिस्से, बिक्रियों, उत्पादन और क्षमता उपयोग में बी आई एल टी/ बी जी पी पी एल के निष्पादन को शामिल न किए जाने से कोई गिरावट नहीं आई है। क्षति अवधि के दौरान लाभ और क्षमता में समग्र रूप से वृद्धि हुई है।
- xi) नकदी प्रवाह, वृद्धि और पूंजी जुटाने की क्षमता ने भी सुधार दर्शाया है। रोजगार और वेतनों से संबंधित आंकड़ों ने भी पाटन का कोई विपरीत प्रभाव नहीं दर्शाया है।
- xii) घरेलू उद्योग के अन्य सभी घटकों, बी आई एल टी/ बी जी पी पी एल के अतिरिक्त, के निष्पादन में सुधार हुआ है। जे के पेपर लिमिटेड, वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड, तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट और पेपर लिमिटेड के बिक्री राजस्व, कर पूर्व लाभ, बिक्री की मात्रा में क्षति जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। ओरिएंट पेपर और इंडस्ट्रीज

लिमिटेड, सेंचुरी टेक्सटाइल्स और इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेतिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्वांटम पेपर्स लिमिटेड, रुचिरा पेपर्स लिमिटेड जैसे अन्य पेपर उत्पादकों के बिक्री राजस्व और लाभ में भी क्षति जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

- xiii) पाटन रोधी शुल्क घरेलू उत्पादकों के लाभों, आर ओ आई आदि में "अपेक्षित स्तर" तथा वृद्धि करने का उपकरण नहीं है।
- xiv) घरेलू उद्योग को आयातों और परिणामस्वरूप क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। पी ओ आई में उत्पादन, बाजार हिस्से, क्षमता उपयोग, बिक्रियों में गिरावट पूरी तरह से बी आई एल टी/ बी जी पी पी एल द्वारा उत्पादन में गिरावट के कारण है। इन आर्थिक पैरामीटरों में कोई गिरावट नहीं होती यदि बी आई एल टी/ बी जी पी पी एल उत्पादन में कटौती नहीं करते। बी आई एल टी/ बी जी पी पी एल को शामिल ना करने के बाद, इन पैरामीटर के निष्पादन वास्तव में वृद्धि दर्शाते हैं। अन्य उत्पादकों के उत्पादन में वृद्धि घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट के अनुरूप आती है। यदि आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे थे, तो ऐसे क्षतिकारक आयात का प्रभाव अन्य भारतीय उत्पादकों के निष्पादन में भी दिखाई देता है।
- xv) बी आई एल टी/ बी जी पी पी एल की निष्पादन में गिरावट स्पष्ट रूप से इसकी विदेशी सत्ता एस एफ आई, मलेशिया द्वारा सामना की जा रही वित्तीय बाध्यताओं, कच्ची सामग्री बाध्यताओं और हानि के कारण है। बी आई एल टी/ बी जी पी पी एल की वार्षिक रिपोर्ट स्पष्ट रूप से क्षति के इन अन्य कारणों को स्वीकार करती है।
- xvi) कच्ची सामग्री लागत का 40-50% के बीच अंशदान करती है। कच्ची सामग्री की उच्च कीमतों और भारतीय उत्पादकों के बीच प्रबल प्रतिस्पर्धा ने याचिकाकर्ताओं को प्रभावित किया है।
- xvii) क्षति मार्जिन यह निर्धारित करने के लिए संगत नहीं है कि क्या याचिकाकर्ताओं को क्षति हुई है अथवा नहीं। क्षति मार्जिन केवल शुल्क की मात्रा निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक हैं जो क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xviii) आयातों में वृद्धि और घरेलू उद्योग के निष्पादन के बीच कोई संबंध नहीं है। घरेलू उद्योग के लाभों में उस समय सुधार हुआ जब आयातों में वृद्धि हुई थी। साथ ही, घरेलू उद्योग को भारी हानि हुई थी जब आयात लगभग नगण्य थे। घरेलू उद्योग की आयात कीमत और बिक्री कीमत के बीच भी कोई सह-संबंध नहीं है। घरेलू उद्योग ने आयातों की पहुंच कीमत की तुलना में बिल्कुल विपरीत प्रवृत्ति दर्शाई है जिसका स्पष्ट अर्थ है कि यहां कारणात्मक संबंध अनुपस्थित है।
- xix) घरेलू उद्योग को क्षति की कोई आशंका नहीं है। क्षति के जोखिम के आकलन के लिए, ए डी नियमावली के अनुबंध II के पैरा 3(vii) में क्षमता में वृद्धि अथवा मुक्त रूप से निस्तारणीय क्षमता के संबंध में साक्ष्य के लिए व्यवस्था की गई है और यह कि ऐसी क्षमता "सन्निकट" और "महत्वपूर्ण" है। तथापि, घरेलू उद्योग द्वारा ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है।
- xx) याचिकाकर्ता ने संबद्ध देशों में संचयी माल सूचियों की विद्यमानता की कल्पना की है। प्राधिकारी सत्यापित कर सकता है कि निर्यातकों द्वारा माल सूचियों में कोई वृद्धि नहीं की गई है।
- xxi) वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए घरेलू उत्पादकों की अद्यतन वित्तीय रिपोर्ट लाभ में और वृद्धि को दर्शाती है। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को क्षति का खतरा नहीं है।
- xxii) घरेलू उद्योग का बिक्री अनुपात के लिए उत्पादन लगभग 100% बना रहा है। घरेलू उद्योग अपने संपूर्ण उत्पादन की बिक्री करने में समर्थ है। इस प्रकार, यदि घरेलू उद्योग अधिक उत्पादन कर सकता है तो यह अधिक बिक्री भी कर सकता है।
- xxiii) जनवरी-जून, 2018 की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों में गिरावट हुई है।
- xxiv) टी एन पी पी एल के उत्पादन को पी ओ आई के दौरान तमिलनाडु क्षेत्र में पानी की कमी के कारण क्षति झेलनी पड़ी है।

### छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

- 52. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों पर ध्यान दिया है और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों पर भली-भांति विचार करने के पश्चात पाटन रोधी नियमों के अनुसरण में विभिन्न पैरामीटरों की जांच की है।

**संचयी आकलन**

53. पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में व्यवस्था की गई है कि यदि जहां एक से अधिक देशों से उत्पाद का आयात एक ही समय पाटन रोधी जांच के अधीन हो तो प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करेगा, यदि वह यह निर्धारित करता है कि:-
- क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशतांक के रूप के रूप में 2% से अधिक अभिव्यक्त किया गया है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तुओं के आयात की 3 (या अधिक) प्रतिशत है अथवा जहां अलग-अलग देश का निर्यात 3% से कम है। आयात, संचित रूप, से समान वस्तु के आयात के सात से अधिक प्रतिशत ठहरता है; और
- ख) आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थिति को देखते हुए उचित है।
54. प्राधिकारी ने नोट किया है कि:-
- क) संबद्ध देशों से भारत में संबंध वस्तुओं को पाटित किया जा रहा है। संबद्ध देशों में प्रत्येक से पाटन का मार्जिन नियमों के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।
- ख) संबद्ध देशों से प्रत्येक से आयातों की मात्रा पृथक-पृथक आयातों की कुल मात्रा के 3% से अधिक है।
- ग) आयातों के प्रभावों का संचयी आकलन उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात प्रत्यक्ष रूप से न केवल आपस में बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित समान वस्तु के साथ भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।
55. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने विचार किया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के निर्यातों से घरेलू उद्योग को हुई संचयी क्षति का आकलन करना उचित होगा।
56. अनुबंध-II के साथ पठित पाटन रोधी नियमावली के नियम 11 में व्यवस्था की गई है कि क्षति निर्धारण में ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग की क्षति की ओर संकेत करते हैं, “.....पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार उत्पादकों पर ऐसे आयातों का परिणामी प्रभाव.....”। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का विचार करने के दौरान, यह जांच करना अनिवार्य समझा गया कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना किए जाने पर पाटित आयातों द्वारा उल्लेखनीय कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा रूप से महत्वपूर्ण रूप से कीमतों में हास करता है अथवा कीमतों में वृद्धि को रोकता है, जो अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक घटित हुई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए आंकड़ों का उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ा है जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसरण में विचार किया गया है।
57. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए और जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग और अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों की जांच की गई और निम्नानुसार उनका उल्लेख किया गया।
58. प्राधिकारी ने उल्लेख किया है कि बी जी पी पी एल अपने आंतरिक कारणों की वजह से पी ओ आई के अधिकतर समय संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर रहा था। इसलिए, वर्तमान जांच में क्षति आकलन के लिए घरेलू उद्योग के भाग के रूप में बी जी पी पी एल पर विचार करना उचित नहीं होगा। तदनुसार, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में क्षति आकलन के लिए घरेलू उद्योग के संघटक के रूप में मै. जे के पेपर लि., मै. वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लि. और मै. तमिलनाडु न्यूज प्रिंट और पेपर्स लि. के संबंध में विचार किया है।

**ख.4. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव****(क) मांग/स्पष्ट खपत का आकलन**

59. प्राधिकारी ने भारतीय उत्पादकों और सभी स्रोतों से आयातों की घरेलू बिक्री के जोड़ के रूप में भारत में उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ ध्यान में रखा है। इस प्रकार आकलित मांग दर्शाती है कि क्षति जांच अवधि के दौरान इन में वृद्धि हुई है। आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2014-15 में इसमें मामूली गिरावट आई है किंतु 2015-16 और पी ओ आई (वा.) में इसमें वृद्धि हुई है।

विवरण	इकाई	2013-14	2014-15	2015-16	पीओआई (वार्षिकी)
घरेलू उद्योग बिक्रियां	मी.ट.	2,57,973	2,83,712	3,06,872	3,00,878
बी आई एल टी / बी जी पी पी एल सहित अन्य उत्पादकों की बिक्रियां	मी.ट.	3,93,294	3,55,264	3,62,171	3,24,977
संबद्ध आयात	मी.ट.	7,785	15,604	15,692	73,897
अन्य आयात	मी.ट.	1,288	109	757	1438
मांग / खपत	मी.ट.	6,60,341	6,54,690	6,85,491	7,01,191

**(ख) संबद्ध देशों से आयात मात्रा**

60. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा यह विचार किया जाना जरूरी है कि क्या संबद्ध देशों से पाटित आयातों में या तो कुल रूप में या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

विवरण	इकाई	2013-14	2014-15	2015-16	पीओआई (वार्षिकी)
इंडोनेशिया	मी.ट.	7,470	12,288	13,091	48,522
सिंगापुर	मी.ट.	298	2,997	2,369	4,259
थाईलैंड	मी.ट.	17	320	232	21,116
<b>संबद्ध देश</b>	मी.ट.	<b>7,785</b>	<b>15,604</b>	<b>15,692</b>	<b>73,897</b>
अन्य देश	मी.ट.	1,288	109	757	1438
कुल आयात	मी.ट.	9,073	15,713	16,449	75,335

61. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों में पी ओ आई (वा.) के दौरान कुल रूप में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि, हितबद्ध पक्षकारों ने स्वीकार किया है कि पी ओ आई (वा.) के दौरान आयातों के वृद्धि बी जी पी पी एल के उत्पादन में गिरावट द्वारा सृजित अंतर के कारण थी। प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे से सहमत हैं कि पी ओ आई (वा.) के दौरान बी जी पी पी एल के उत्पादन में गिरावट के कारण आयातों में वृद्धि जरूरी थी। तथापि, प्राधिकारी ने अवलोकन किया है कि पी ओ आई के दौरान आयातों की मात्रा में लगातार वृद्धि हुई है।

**(ग) सापेक्ष रूप में संबद्ध देशों से आयात**

विवरण	इकाई	2013-14	2014-15	2015-16	पीओआई (वार्षिकी)
उत्पादन के संबंध में संबद्ध देश आयात	%	1.14%	2.26%	2.14%	10.80%
मांग के संबंध में संबद्ध देश आयात	%	1.18%	2.38%	2.29%	10.54%

62. यह देखा गया है कि पी ओ आई में आधार वर्ष और पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन और मांग के संबंध में संबद्ध आयातों में वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2015-16 में उत्पादन और मांग के संबंध में आयातों में मामूली गिरावट आई है।

**(घ) मांग में बाजार का हिस्सा**

63. विभिन्न स्रोतों से आयातों और घरेलू उद्योग की बिक्रियों को ध्यान में रखते हुए मांग में संबद्ध आयातों के बाजार के हिस्से की जांच की गई थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध आयातों के बाजार के हिस्से में अत्यधिक वृद्धि हुई है। जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार के हिस्से में गिरावट आई है। जांच अवधि (वार्षिकीकृत) के दौरान अन्य भारतीय उत्पादकों के बाजार के हिस्से में अत्यधिक गिरावट आई है। इसका मुख्य कारण बीजीपीएल के उत्पादन/बिक्रियों में गिरावट आना है। अन्य भारतीय उत्पादकों के बाजार के हिस्से में गिरावट को संबद्ध देशों से आयातों द्वारा अधिग्रहीत कर लिया गया है।

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच अवधि (वार्षिकीकृत)
घरेलू उद्योग	%	39%	43%	45%	43%
अन्य भारतीय उत्पादक	%	60%	54%	53%	46%
सभी घरेलू उत्पादकों का कुल बाजार का हिस्सा	%	99%	98%	98%	89%
संबद्ध आयात	%	1.18%	2.38%	2.29%	10.54%
अन्य आयात	%	0.20%	0.02%	0.11%	0.21%
कुल	%	100 %	100 %	100 %	100 %

### छ.5 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के कीमत प्रभाव

64. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि क्या भारत में समान उत्पादकों के साथ तुलना करने पर आरोपित पाटित आयातों द्वारा कीमत में अत्यधिक कटौती की जा रही है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव, अन्यथा कीमतों में हास करते अथवा कीमतों में वृद्धि को रोकते, जो कि सामान्य स्थिति में हो गई होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच, कीमत में कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत हास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हुआ है, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत, निबल बिक्री वसूली) एनएसआर (और घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत) एनआईपी (की तुलना, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की भारित औसत पहुंच कीमत के साथ की गई है।

#### (क) कीमत कटौती

65. कीमत कटौती का विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की निबल बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। घरेलू उद्योग की निबल बिक्री कीमत का परिकलन करते समय सभी करों, छूटों, डिस्काउंट्स और कमीशन को घटाया गया है और कारखाना-गत स्तर पर बिक्रियों की वसूली का निर्धारण पाटित आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना करने के लिए किया गया है। तदनुसार, संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कीमत कटौती के प्रभाव का आकलन किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:-

विवरण	मापन का यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच अवधि (वार्षिकीकृत)
<b>इंडोनेशिया</b>					
आयातों की पहुंच कीमत	रुपए/मी.टन	50,807	52,185	48,816	49,178
निबल बिक्री कीमत	रुपए/मी.टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	रुपए/मी.टन	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
सीमा		0-10%	0-10%	10-20%	10-20%
<b>थाईलैंड</b>					
आयातों की पहुंच कीमत	रुपए/मी.टन	55,131	61,389	55,919	55,659
निबल बिक्री कीमत	रुपए/मी.टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	रुपए/मी.टन	***	***	***	***
	%	***	***	***	***

विवरण	मापन का यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच अवधि (वार्षिकीकृत)
सीमा		(10)-0%	(15)-(5)%	(10)-0%	0-10%
<b>सिंगापुर</b>					
आयातों की पहुंच कीमत	रुपए/मी.टन	57,700	46,372	53,947	40,217
निबल बिक्री कीमत	रुपए/मी.टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	रुपए/मी.टन	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
सीमा		(10)-0%	10-20%	(10)-0%	30-40%
<b>संबद्ध देश</b>					
आयातों की पहुंच कीमत	रुपए/मी.टन	50,988	53,834	49,964	46,991
निबल बिक्री कीमत	रुपए/मी.टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	रुपए/मी.टन	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
सीमा		0-10%	0-10%	10-20%	10-20%

66. उपरोक्त तालिकाओं से यह देखा जा सकता है कि क्षति अवधि के साथ-साथ जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से कीमत में सकारात्मक कटौती हुई है।

**(ख) कीमत ह्रास और न्यूनीकरण**

67. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में ह्रास कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों के प्रभाव अत्यधिक सीमा तक कीमतों में ह्रास कर रहे हैं अथवा कीमतों में वृद्धि को रोक रहे हैं, जो कि सामान्य स्थिति में अन्यथा हो सकती थी, क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की तुलना की गई है, जो कि निम्नानुसार है:-

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच अवधि (वार्षिकीकृत)
उत्पादन की लागत	रुपए/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	102	94	94
बिक्री कीमत	रुपए/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	99	99	102
पहुंच मूल्य	रुपए/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	106	98	92

68. उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि पाटित आयात न तो घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास कर रहे हैं और न ही इनके कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कीमत ह्रास का कोई प्रभाव पड़ा है। जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत को, घरेलू उद्योग की लागतों में हुई वृद्धि से भी अधिक बढ़ाने में समर्थ रहा है।

**(ख) कम कीमत पर बिक्री**

69. घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत) एनआईपी (का निर्धारण किया गया है और इसकी तुलना संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य के साथ की गई है, ताकि कम कीमत पर बिक्री होने का पता लगाया जा सके। विचाराधीन उत्पाद की क्षति

रहित कीमत का निर्धारण, नियमावली के अनुबंध-3 में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर जांच अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपना करके किया गया है। क्षति रहित कीमत का निर्धारण, क्षमता उपयोग के ऐसे अनुकूलतम सूत्र को ध्यान में रख कर किया गया है, जो कि याचिकादाता संयंत्र से प्राप्त कर सकते हैं। विश्लेषण से पता चलता है कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम था, जैसा कि नीचे तालिका से देखा जा सकता है, जो कि कम कीमत पर बिक्री के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाती है।

विवरण	यूनिट	जांच अवधि (वार्षिकीकृत)* (भारतीय रूपए)	जांच अवधि (वार्षिकीकृत)* (अमरीकी डालर)
<b>इंडोनेशिया</b>			
पहुंच कीमत	प्रति मी .टन	49,178	729.10
क्षति रहित कीमत (एनआईपी)	प्रति मी .टन	***	***
कम कीमत पर बिक्री	प्रति मी .टन	***	***
कम कीमत पर बिक्री	%	***	***
कम कीमत पर बिक्री	% सीमा	सकारात्मक	सकारात्मक
<b>थाईलैंड</b>			
पहुंच कीमत	प्रति मी .टन	55,659	825.18
क्षति रहित कीमत (एनआईपी)	प्रति मी .टन	***	***
कम कीमत पर बिक्री	प्रति मी .टन	***	***
कम कीमत पर बिक्री	%	***	***
कम कीमत पर बिक्री	% सीमा	सकारात्मक	सकारात्मक
<b>सिंगापुर</b>			
पहुंच कीमत	प्रति मी .टन	40,217	596.25
क्षति रहित कीमत (एनआईपी)	प्रति मी .टन	***	***
कम कीमत पर बिक्री	प्रति मी .टन	***	***
कम कीमत पर बिक्री	%	***	***
कम कीमत पर बिक्री	% सीमा	सकारात्मक	सकारात्मक

## छ.6 घरेलू उद्योग के आर्थिक प्राचल

70. पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-11 में यह अपेक्षित है कि क्षति के विश्लेषण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। जहां तक ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव का संबंध है, नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन मार्जिन की मात्रा; नकद प्रवाह, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित ऋणात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा।

71. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अपने निवेदनों में दिए गए विभिन्न तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रख कर क्षति के प्राचलों की सार्थक जांच की है।

**(क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियां**

72. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियां नीचे तालिका में दी गई हैं :-

विवरण	मापन का यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच अवधि (वार्षिकीकृत)
कुल क्षमता	मी.टन	10,87,251	11,56,000	11,56,000	11,56,000
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	106	106
कुल उत्पादन	मी.टन	10,08,784	10,69,446	11,36,727	11,20,495
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	113	111
उत्पादन-विचाराधीन उत्पाद	मी.टन	2,91,309	3,34,384	3,70,343	3,59,376
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	127	123
क्षमता उपयोग	%	93%	93%	98%	97%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	106	104
घरेलू बिक्रियां	मी.टन	2,57,973	2,83,712	3,06,872	3,00,878
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	119	117

73. उपरोक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि:-

(क) वर्ष 2014 - 15 से घरेलू उद्योग की क्षमता स्थिर बनी हुई है।

(ख) समस्त क्षति की जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है और जांच अवधि (वार्षिकीकृत) के दौरान यह 97% था।

(ग) वर्ष 2015-16 तक घरेलू उद्योग के उत्पादन और घरेलू बिक्रियों में सुधार हुआ है और जांच अवधि (वार्षिकीकृत) के दौरान इनमें मामूली गिरावट आई है।

**(ख) लाभप्रदता, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी लाभ**

74. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी लाभ नीचे तालिका में दिया गया है:-

विवरण	मापन का यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच अवधि (वार्षिकीकृत)
लाभ/हानि	रूपए/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	44	204	266
लाभ/हानि	लाख रूपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	48	242	311
ब्याज पूर्व लाभ	लाख रूपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	174	192
नकदी लाभ	लाख रूपए	***	***	***	***



प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	72	141	161
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	152	177

75. उपरोक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि:-

- (क) वर्ष 2014-15 में घरेलू उद्योग की उत्पादकता में गिरावट आई है, लेकिन आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि (वार्षिकीकृत) के दौरान उसमें अत्यधिक सुधार हुआ है।
- (ख) इसी प्रकार पीबीआईटी, नकदी लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ भी लाभ के समुत्तरूप है।

**(ग) रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी**

76. क्षति अवधि के दौरान रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी नीचे तालिका में दिया गया है:-

विवरण	मापन का यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच अवधि (वार्षिकीकृत)
रोजगार	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	100	96
वेतन	लाख रूपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	108	121
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.टन/संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	128	128
प्रति दिवस उत्पादकता	मी.टन/दिवस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	127	123

77. यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान उत्पादकता प्रति दिवस और उत्पादकता प्रति कर्मचारी में सुधार हुआ है।

**(घ) माल सूचियां**

78. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास माल सूचियों की स्थिति नीचे तालिका में दर्शाई गई है:-

विवरण	मापन का यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	जांच अवधि (वार्षिकीकृत)
औसत भंडार	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	177	175	238

79. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की माल सूचियों में वृद्धि हुई है।

**(ङ) संवृद्धि**

80. लाभ, निवेशों पर प्रतिलाभ, उत्पादन, क्षमता उपयोग और नकदी प्रवाह के संबंध घरेलू उद्योग की संवृद्धि नकारात्मक रही है।

वृद्धि (वर्ष दर वर्ष)	यू ओ एम	2013-14	2014-15	2015-16	जांच अवधि (वार्षिकीकृत)
संवृद्धि (वर्ष दर वर्ष)					
उत्पादन	%	-	14.79	10.75	(2.96)
घरेलू बिक्रियां	%	-	9.98	8.16	(1.95)
बिक्रियों की लागत	%	-	1.76	(8.03)	0.44
बिक्री कीमत	%	-	(0.87)	(0.55)	3.28
लाभ/हानि प्रति यूनिट	%	-	(56.17)	365.10	30.71
निवेश पर प्रतिलाभ	%	-	16.75	30.55	16.30

### (च) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

81. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उसकी वर्तमान वित्तीय स्थिति उसे नए निवेश के लिए पूंजी जुटाने की अनुमति नहीं देती है। तथापि, प्राधिकारी यह पाते हैं कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की सुधरी हुई वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसकी वित्तीय क्षमता में भी सुधार हुआ है।

### (छ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

82. घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत की सीमा को बनाने में समर्थ है। तथापि, जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत में गिरावट आई है। इसलिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

### ज. आर्थिक क्षति का खतरा

#### ज.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

83. संबद्ध देशों से आयातों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति होने का खतरा है। संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास अत्यधिक बेशी क्षमताएं हैं। संबद्ध देशों से कीमत में कटौती अत्यधिक है और भारतीय बाजार आकर्षक है जिसके कारण आयातों में और वृद्धि होने तथा कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण के प्रभाव पड़ने की संभावना है।

#### ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

84. आर्थिक क्षति होने का कोई खतरा नहीं है क्योंकि आयातों में वृद्धि भारत में एक प्रमुख घरेलू उत्पादक द्वारा वस्तुओं की आपूर्ति नहीं करने के कारण हुई है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि संबद्ध देशों के उत्पादकों के पास अत्यधिक बेशी क्षमताएं विद्यमान हैं।
85. बीआईएलटी से भिन्न घरेलू उत्पादकों के कार्य-निष्पादन ने मुख्य सुधार दर्शाया है।
86. जांच अवधि पश्चात सूचना से पता चलता है कि घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में और सुधार हुआ है।

#### ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

87. आर्थिक क्षति के खतरे से संबंधित प्रावधान निम्नानुसार है:-

"(vi) आर्थिक क्षति के खतरे का निर्धारण तथ्यों के आधार पर होगा और न कि मात्र आरोप, अनुमानों अथवा अप्रत्यक्ष संभावना पर। परिस्थितियों में ऐसे परिवर्तन को, जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें पाटन के कारण क्षति होती है, स्पष्टतया प्रत्याशित और आसन्न माना जाना चाहिए। आर्थिक क्षति के खतरे के विद्यमान होने का निर्धारण करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ निम्नोक्त कारकों पर विचार करेंगे:-

- (क) भारत में पाटित आयातों में अत्यधिक दर से वृद्धि होना, जिससे पर्याप्त रूप से बड़े हुए आयातों की संभावना का पता चले;

- (ख) किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए निर्यातक की पर्याप्त स्वतंत्र रूप से निपटाए जाने वाली अथवा आसन्न क्षमता में वृद्धि होना, जिससे भारतीय बाजारों में पर्याप्त रूप से बड़े हुए पाटित आयातों की संभावना का पता चले;
- (ग) क्या आयात ऐसी कीमतों में प्रवेश कर रहे हैं, जिनका घरेलू कीमतों पर कीमत ह्रास अथवा कीमत न्यूनीकरण का प्रभाव पड़ेगा तथा उससे और अधिक आयातों के लिए मांग में वृद्धि होने की संभावना है, और
- (घ) वस्तु की माल-सूचियों की जांच की जा रही है।"

88. आर्थिक क्षति का खतरा एक ऐसी स्थिति होती है, जिसमें घरेलू उद्योग को क्षति अवधि के दौरान क्षति नहीं हुई है, बल्कि यदि वर्तमान परिस्थितियां विद्यमान रहती हैं, तो घरेलू उद्योग को क्षति आसन्न है। "आर्थिक क्षति का खतरा" का तात्पर्य, क्षति के खतरे के स्पष्ट और आसन्न होने से है। आर्थिक क्षति के खतरे की जांच तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए और न कि आरोप मात्र, अनुमानों, परिकल्पनाओं अथवा अप्रत्यक्ष संभावनाओं पर।
89. आर्थिक क्षति के खतरे के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि-
- (क) भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में और साथ ही समग्र रूप से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं को आयातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तथापि, संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि भारत में एक प्रमुख घरेलू उत्पादक द्वारा वस्तुओं की आपूर्ति नहीं करने के कारण हुई है।
- (ख) घरेलू उद्योग ने निर्यात करने वाले उत्पादकों के पास पर्याप्त रूप से स्वतंत्र रूप से निपटाई जाने वाली अथवा आसन्न बृहत् क्षमताएं होने के बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।
- (ग) इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने सहभागी उत्पादकों की क्षमता की जांच की है और यह नोट किया जाता है कि किसी भी उत्पादक द्वारा कोई पर्याप्त क्षमता का संवर्धन नहीं किया है और किसी भी उत्पादक के पास पर्याप्त बेशी क्षमता नहीं है।
- (घ) जांच अवधि के दौरान आयातों ने घरेलू उद्योग का कोई कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण नहीं किया है।

#### ज.4 क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन

90. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-3 के साथ पठित पाटन-रोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत का निर्धारण, जांच अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपना कर किया गया है। घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत का पूर्वाकलन किया गया है और क्षति मार्जिन का परिकलन करने के प्रयोजनार्थ इस पर प्रत्येक संबद्ध देश से पहुंच कीमत के साथ तुलना करने के लिए विचार किया गया है। क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल के बेहतर उपयोग पर विचार किया गया है। इसी प्रकार का निरूपण प्रयोज्यताओं के लिए भी किया गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन के बेहतर उपयोग पर विचार किया गया है। जांच अवधि में उत्पादन का परिकलन, बेहतर क्षमता उपयोग पर विचार करते हुए किया गया है और प्रति यूनिट नियत लागत प्राप्त करने के लिए भी उसी उत्पादन पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन की लागत में कोई आसाधारण अथवा गैर-आवर्ती व्यय न प्रभारित किए जाएं। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी) अर्थात् औसत निवल अचल परिसम्पत्तियों के साथ औसत कार्यशील पूंजी (पर उचित प्रतिलाभ) कर-पूर्व @ 22%) की कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई है, ताकि अनुबंध-3 में यथा निर्धारित क्षति रहित कीमत प्राप्त की जा सके और उसे अपनाया जा रहा है। क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए इस प्रकार से निर्धारित की गई क्षति रहित कीमत की तुलना, संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमतों के साथ की गई है, जो कि निम्नानुसार है:-

क्रमांक	उत्पादक देश	उत्पादक	पहुंच मूल्य (अमरीकी डालर/ मी.टन)	क्षति रहित कीमत (अमरीकी डालर/ मी.टन)	क्षति मार्जिन (अमरीकी डालर/ मी.टन)	क्षति मार्जिन %	सीमा
1.	इंडोनेशिया	1 .पीटी रिआऊ अंडलान केरतास 2. पीटी अनुग्रह केरतास उटामा	***	***	***	***	10-20

		3. पीटी पीटी एशिया पेसिफिक रेओन					
2.	इंडोनेशिया	सभी अन्य	***	***	***	***	20-30
3.	इंडोनेशिया	सभी निर्यातक	***	***	***	***	0-10

## झ. कारणात्मक संबंध

### झ.1 उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

91. इस संबंध में उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (क) क्षति और आरोपित आयात के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। घरेलू उद्योग को अन्य कारकों से क्षति हो रही है। किसी भी आर्थिक सूचक ने किसी क्षति का कोई संकेत दिया है, कीमत और मात्रा दोनों के क्षेत्रों में कोई आर्थिक क्षति का तो छोड़ ही दो। आर्थिक सूचकों से संबद्ध वस्तुओं के संबंध में संबद्ध वस्तुओं के आयातों और घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन के बीच कोई सह-संबंध होने का पता नहीं चलता है क्योंकि विक्रियों की मात्रा में कोई कमी हुए बिना कीमतें स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ रही हैं।
- (ख) इसलिए मात्र आयातों की मात्रा में वृद्धि होना और कीमत में कटौती होना पर्याप्त नहीं है। यह प्रदर्शित होना आवश्यक है कि आयातों का घरेलू उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
- (ग) घरेलू उद्योग एक उन्नतिशील उद्योग है और यह दुर्बलता या दोष-पूर्णता की स्थिति में नहीं है और उसे कोई क्षति नहीं होती है।
- (घ) आर्थिक कारक दर्शाते हैं कि यह सकारात्मक विकास का अनुभव कर रहा है और सुदृढ़ स्थिति में है।

### झ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

92. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (क) संबद्ध देशों से भिन्न देशों से आयात या तो तुच्छ हैं अथवा आयात कीमतें अधिक हैं तथा इसलिए घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है।
- (ख) जितना संभव था, घरेलू विक्रियों के प्रचालनों के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन की जांच की गई है। इसलिए घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में संभावित गिरावट आना, घरेलू उद्योग की क्षति का संभावित कारण नहीं है।
- (ग) विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए प्रोद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रिया में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रोद्योगिकी में संभावित परिवर्तन घरेलू उद्योग की क्षति का कारण नहीं है।
- (घ) याचिकादाताओं द्वारा उत्पादित और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग की क्षति का संभावित कारण नहीं है। किसी भी स्थिति में याचिकादाताओं का यह विचार है कि वर्तमान प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद से संबंधित सूचना ही प्रासंगिक सूचना है और याचिकादाताओं ने घरेलू उद्योग के रूप में ऐसी सूचना प्रदान की है।
- (ङ) ऐसी कोई व्यापारिक प्रतिबंधित पद्धति नहीं है, जो कि घरेलू उद्योग की क्षति का कारण हो सकती है।
- (च) विचाराधीन उत्पाद के खपत पैटर्न में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है।

### झ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

93. पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी को अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों से भिन्न किसी ज्ञात कारक की जांच करनी आवश्यक होती है, जो कि उस समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हो, ताकि इन कारकों के कारण हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए। इस संबंध में जो कारक प्रासंगिक होते हैं, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापारिक प्रतिबंधित पद्धतियां और प्रतिस्पर्धा, प्रोद्योगिकी में विकास और निर्यात निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल है। इसकी जांच की गई थी कि क्या पाटन-रोधी नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध प्राचलों से भिन्न ज्ञात इन सूचीबद्ध कारक, घरेलू उद्योग की क्षति के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं।

(क) तृतीय देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

94. प्राधिकारी नोट करते हैं कि असंबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा कम थी जो कि तुच्छ है।

(ख) निर्यात निष्पादन

95. प्राधिकारी ने अपने क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू प्रचालनों के आंकड़ों पर विचार किया है।

(ग) प्रोद्योगिकी का विकास

96. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रोद्योगिकी के विकास के संबंध में कोई मुद्दा नहीं उठाया है, जो कि घरेलू उद्योग की क्षति का कारण रहा हो।

(घ) कंपनी के अन्य उत्पादों का कार्य-निष्पादन

97. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि याचिकादाताओं द्वारा उत्पादित किया जा रहा और बेचा जा रहा अन्य उत्पाद, घरेलू उद्योग की क्षति का कोई संभावित कारण रहा हो।

#### **(ड.) विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापारिक प्रतिबंधित पद्धतियां**

98. संबद्ध वस्तुओं के आयात किसी भी तरीके से प्रतिबंधित नहीं हैं और उनका देश में आयात स्वतंत्र रूप से किया जाता है। घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। घरेलू उद्योग की कीमत संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत से पर्याप्त रूप से प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह पता चलता हो कि विदेशी उत्पादकों और घरेलू उद्योग के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ है।

(ड) मांग में संकुचन और खपत के पैटर्न में परिवर्तन

99. यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

झ.4 कारणात्मक संबंध के लिए संबद्ध कारक

100. प्राधिकारी निम्नोक्त अनुसार नोट करते हैं:-

(क) भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में और साथ ही समग्र रूप से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तथापि, संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि मुख्यतया भारत में एक प्रमुख उत्पादक के उत्पादन में गिरावट आने के कारण हुई है।

(ख) जांच अवधि में संबद्ध देशों से कीमत में कटौती और कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक है।

(ग) पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनीकरण का प्रभाव पड़ रहा है।

(घ) समस्त क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है और यह जांच अवधि (वार्षिकीकृत) के दौरान 97% था।

(ड) पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में जांच अवधि (वार्षिकीकृत) के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में अत्यधिक सुधार हुआ है। इसी प्रकार पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में जांच अवधि (वार्षिकीकृत) के दौरान पीबीआईटी, नकदी लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ में भी अत्यधिक सुधार हुआ है।

ज. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

101. प्रकटन पश्चात अनुरोध हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त हुए हैं। उनमें उठाये गये मुद्दों का पहले ही पूर्व की जांच की अवधि के दौरान उठाये गये थे और उनका समाधान उपयुक्त रूप से किया जा चुका है। हालांकि, स्पष्टता के वास्ते, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच नीचे दिए गए अनुसार की जा रही है :

#### **ज. 1. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

102. प्रकटन विवरण में घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में सूचना प्रकट की जानी चाहिए क्योंकि यह सूचना स्वयं घरेलू उद्योग से संबंधित है।

103. संबद्ध देशों के निर्यातकों/उत्पादकों की सत्यापन रिपोर्ट का अगोपनीय पाठ, विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के पास ई-मेल और पत्राचार, घरेलू उद्योग के आंकड़ों के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना घरेलू उद्योग को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
104. बी जी पी पी एल पर विचार अपात्र घरेलू उत्पादक के रूप में नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें जांच की अवधि के अधिकांश हिस्से के दौरान उत्पादन नहीं किया है। इन आंकड़ों का समायोजन क्षति का निर्धारण करने के लिए किया जा सकता है लेकिन बी जी पी पी एल पर विचार एक अपात्र घरेलू उद्योग के रूप में नहीं किया जा सकता है।
105. प्राधिकारी ने ए पी पी समूह द्वारा दायर किए गए उत्तर को अस्वीकार करने के लिए सही रूप में प्रस्ताव किया है। असंबंधित निर्यातक का उत्तर निर्यात की कीमत और पाटन का अलग अलग मार्जिन का निर्धारण करने के लिए आवश्यक है।
106. प्राधिकारी ने ए पी पी ग्रुप द्वारा दायर किए गए उत्तर को अस्वीकार करने के लिए सही रूप में प्रस्ताव किया है। संबंधित पक्षकारों ने इस जांच में सहयोग नहीं किया है और इस कारण से प्राधिकारी घरेलू बिक्री और भारत में किए गए निर्यातों के संबंध में सूचना का सत्यापन नहीं कर सकता है।
107. प्राधिकारी ने फिनिक्स पल्प एंड पेपर पब्लिक कंपनी लिमि., थाईलैण्ड द्वारा दायर किए गए उत्तर को सही रूप में अस्वीकार किया है क्योंकि यह उत्तर घरेलू बिक्री और निर्यातों के लिए जिम्मेदार संबंधित कंपनी द्वारा दायर नहीं किया गया है।
108. प्राधिकारी ने उन मामलों में उत्तरों को अस्वीकार सही रूप में किया है जहां मूल्य श्रृंखला पूर्ण नहीं है। प्राधिकारी ने विगत में निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा दायर किए गए उत्तर को अस्वीकार किया है, जब मूल्य श्रृंखला पूरी नहीं थी।
109. यह स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार से प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सिंगापुर में कोपियर पेपर का कोई उत्पादक नहीं है। प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे सिंगापुर से आयातों के लिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करें।
110. आयातों में वृद्धि बी जी पी पी एल द्वारा उत्पादन को स्थगित करने के कारण हुआ है। भारतीय उद्योग बी जी पी पी एल द्वारा उत्पादन को स्थगित किये जाने की फलस्वरूप सृजित बड़ी हुई मांग को पूरा कर सकता था। याचिकाकर्ता निर्यातों को कम कर सकते थे, उसका उत्पादन कर सकते थे और उसे अपेक्षाकृत अधिक रूप में घरेलू तौर पर बिक्री कर सकते थे। घरेलू उद्योग ने इन वस्तुओं का निर्यात अपेक्षाकृत उस मूल्य पर किया है जो संबद्ध देशों से आयात की कीमत की तुलना में अधिक है।
111. प्राधिकारी से यह अपेक्षित नहीं है कि वह आयातों के कारणों की जांच करे बल्कि उनसे केवल यह अपेक्षित है कि वे आयातों में वृद्धि का निर्धारण करें। प्राधिकारी शुल्क के निर्धारित रूप की सिफारिश कर सकते हैं यदि आयातों को उत्पादन के स्थगन के द्वारा औचित्यपूर्ण बताया गया हो। शुल्क का बैंच मार्क रूप आयातों को उचित कीमत पर किये जाने की अनुमति देगा और घरेलू उद्योग को सामान्य रूप से कार्य करने की अनुमति देगा।
112. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में जांच की अवधि में गिरावट आई है और आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। अन्य भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से में गिरावट को संबद्ध देशों से आयातों के द्वारा दूर किया गया है।
113. संबद्ध देशों से आयात की कीमत में जांच की अवधि में लागतों में सदृश गिरावट के बिना तेजी से गिरावट आई है। आयात की कीमतें बिक्री की कीमत से कम हैं और यह घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कम है। घरेलू उद्योग को उस स्थिति में वित्तीय हानि उठानी पड़ती यदि इसे आयातों के साथ समान कीमतों पर उत्पाद की बिक्री करनी पड़ती।
114. घरेलू उद्योग ने निवेश पर कम आय, बी जी पी पी एल के उत्पादन के स्थगन, उत्पाद और बाजार की प्रकृति पर विचार करते हुए बिक्री की कीमत में कटौती नहीं की है जहां इसने बाजार हिस्से को खोना और घटती हुई कीमतों की बजाय माल भंडार को जमा होने देने का विकल्प अपनाया है।
115. शेष घरेलू उद्योग के उत्पादकों की बिक्री और उत्पादन में गिरावट आई है यद्यपि इसमें उस उत्पादन के स्थगन के कारण वृद्धि होनी चाहिए थी। घरेलू उद्योग के पास माल भंडार में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है। 97 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर भरोसा करना सही नहीं है क्योंकि यह क्षमता विचाराधीन उत्पाद के लिए समर्पित नहीं है और इसका उपयोग अन्य उत्पादों के लिए भी किया जाता है।
116. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के इस अनुरोध पर भी ध्यान नहीं दिया है कि कच्चे माल की कीमत में कमी और घरेलू उद्योग द्वारा किये गये प्रयासों के कारण लाभ में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के और अधिक निवेश के लिए पूंजी उगाहने की क्षमता कमजोर हुई है।

117. प्राधिकारी जांच की अवधि के बाद की अवधि में माल भंडार के आंकड़ों पर नजर डाल सकते हैं जो यह दर्शाता है कि माल भंडार और आयातों में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग आयातों में गिरावट पर माल भंडार को बेचने में सक्षम था। इस प्रकार से आयातों और माल भंडार में वृद्धि के बीच एक कारणात्मक संबंध है।
118. आयातों के कारण क्षति होने का खतरा है। आयातों में 2015-16 की तुलना में जांच की अवधि में लगभग 370 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कम कीमत पर आयात में पर्याप्त रूप से वृद्धि होगी और यह घरेलू उद्योग के वर्तमान कमजोर कार्य निष्पादन पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव डालेगा।
119. संबद्ध देश ने संबद्ध उत्पाद के प्रमुख उत्पादक के पास बहुत अधिक उत्पादन क्षमता है। प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे भारत में निर्यातों के विपथन की संभावना का निर्धारण करने के लिए घरेलू बिक्री, निर्यात बिक्री का अनुपात, तीसरे देशों में कीमतों, भंडार का सूतर आदि का एक विश्लेषण करें। कीमत ह्रास और कीमत पर दबाव का नहीं होना क्षति के खतरे के आकलन के लिए संगत नहीं है। कीमत का संभावित ह्रास और उस पर दबाव पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II (vii) के संबंध में क्षति के खतरे के आकलन के लिए महत्वपूर्ण है।
120. आयात की कीमत में घरेलू उद्योग की लागत का सूतर और बिक्री की कीमत से बहुत अधिक कम है और निर्यातकों के पास उपयोग न की गई क्षमता को देखते हुए आयातों से संभवतः कीमत पर बहुत अधिक दबाव और उसमें ह्रास का प्रभाव हो सकता है। संयुक्त राज्य में कोट न किये गये पेपर पर 21.5 प्रतिशत प्रतिकर शुल्क लगाया है। निर्यातों को 22 प्रतिशत सब्सिडी दी गई है और इस कारण से भारतीय उद्योग को समान अवसर प्राप्त नहीं हो सकता है।
121. भारतीय बाजार कीमतों की मामले में आकर्षक है। विदेशी उत्पादक भारतीय बाजार में अपेक्षाकृत 16 प्रतिशत कम बिक्री कीमत पर प्रवेश करने में सक्षम हैं और वे ऐसा करना जारी रख सकते हैं क्योंकि उन्हें सरकार से सब्सिडी का लाभ मिलता है।
122. आयातों में आशियान देशों के साथ एफ टी ए के कारण वृद्धि हुई है। उचित रूप में यह माना जा सकता है कि विदेशी उत्पादक एक लघु अवधि में उत्पादन बढ़ा सकते हैं। संबद्ध देशों से निर्यातकों का भी बहुत अधिक निर्यात उन्मुखीकरण है और पूरे विश्व में बहुत अधिक अतिरिक्त मात्रा मौजूद है, जिससे ये देश कम कीमतों पर निर्यात करने के लिए बाध्य हैं।
123. घरेलू उद्योग को क्षति का प्राथमिक कारण पाटित किया गया आयात है और न कि बी जी पी पी एल द्वारा उत्पादन का स्थगन है। प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य का आकलन करें जो वास्तविक क्षति के खतरे की स्थिति में कारणात्मक संबंध को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण कारक होगा।
124. क्षति के खतरे के मामले में कारणात्मक संबंध के लिए केवल महत्वपूर्ण मानदंड, कीमत में कटौती, विदेशी उत्पादकों के पास अतिरिक्त क्षमताएं, विदेशी उत्पादकों के पास माल भंडार, घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के साथ आयात की पहुंच कीमत की तुलना है।
125. आयातों में वृद्धि विदेशी उत्पादकों और घरेलू उत्पादकों द्वारा दी जाने वाली कीमतों में बहुत अधिक अंतर, घाटे पर घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात, घरेलू उद्योग के माल भंडार में वृद्धि कारणात्मक संबंध के मौजूद होने को सिद्ध करता है।
126. यदि प्राधिकारी इस बात का निर्धारण करते हैं कि आयातों में वृद्धि बी जी पी पी एल द्वारा उत्पादन स्थगित किये जाने के कारण न्यायोचित है, तब प्राधिकारी शुल्क से बैच मार्क रूप को लगाने पर विचार करना चाहिए। पाटनरोधी शुल्क अमरीकी डालर में लगाया जाना चाहिए क्योंकि रुपए का बहुत अधिक अवमूल्यन हो गया है।

## ब. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

127. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों में से एक पक्षकार ने निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं :
128. इण्डोनेशिया में उत्पादकों द्वारा दायर किये गये उत्तर को स्थिति में भी स्वीकार किया जाना चाहिए यदि इसके असंबंधित निर्यातक द्वारा कोई उत्तर दायर नहीं किया गया है जिसने भारत में संबद्ध वस्तुओं के ऐसे इण्डोनेशियाई उत्पादकों द्वारा दिये गये कुल आयात का लगभग 40 प्रतिशत आयात किया है।
129. जांच करने वाले प्राधिकारी केवल उपलब्ध तथ्यों का सहारा ले सकते हैं, जहां कोई पक्षकार आवश्यक सूचना देने से इनकार करता है अथवा अन्य प्रकार से उचित समय अवधि के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में बहुत अधिक अवरोध उत्पन्न करता है। इण्डोनेशिया के उत्पादकों ने पाटनरोधी महानिदेशालय के साथ सहयोग किया है और उनका सत्यापन विधिवत किया गया है।
130. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पूर्व की जांचों में उत्पादकों के उत्तर को स्वीकार किया है जहां बिक्री गैर सहयोगी असंबंधित उत्पादकों के माध्यम से की गई थी।

131. प्रकटन विवरण में यह निष्कर्ष किया गया है कि निर्यात करने वाले उत्पादकों की क्षमता में स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य अथवा किसी आसन्न वृद्धि के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है, जांच के अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लिए कीमत में कोई ह्रास अथवा उस पर कोई दबाव नहीं पड़ा है और लाभ सहित घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों में जांच की अवधि (ए) के दौरान बहुत अधिक सुधार हुआ है। इस कारण से, कोई वास्तविक क्षति अथवा वास्तविक क्षति का खतरा प्रकटन विवरण में प्रकट किये गये तथ्यों के आधार पर स्थापित नहीं किया जा सकता है।
132. जांच को प्रारंभ करने का अनुरोध करते हुए पत्र तमिलनाडू न्यूज प्रिंट एंड पेपर्स लिमि. द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। शेष घरेलू उत्पादकों का हिस्सा मात्र 44 प्रतिशत है और उसे "बड़े हिस्से" के रूप में नहीं माना जा सकता है।
133. संबद्ध उत्पाद के आयातों में कुल मांग का केवल 8 प्रतिशत होती है और इसे घरेलू उद्योग को किसी वास्तविक क्षति अथवा क्षति के खतरे के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। पेपर के घरेलू उत्पादकों में कड़ी प्रतिस्पर्धा है और यदि घरेलू उद्योग को कोई क्षति हुई है तो यह इसी कारण से हुआ है।
134. घरेलू उद्योग को क्षति कच्चे माल की उपलब्धता की कमी और कच्चे माल की अधिक कीमत के कारण हुई है जो विचाराधीन उत्पाद की कुल उत्पादन लागत का 40 से 50 प्रतिशत के बीच होता है। याचिकाकर्ताओं ने सही रूप में यह उल्लेख नहीं किया है कि संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग द्वारा उठाई जा रही वर्तमान क्षति के लिए एकमात्र कारण है।
135. प्राधिकारी कोट न किये गये पेपर पर अन्य न्यायाधिकारों में जांच करने वाले प्राधिकारियों के जांच परिणाम पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। प्राधिकारी को अपना निर्णय वर्तमान जांच के तथ्यों पर परिस्थितियों के आधार पर करना है।
136. प्राधिकारी को यह नोट करना चाहिए कि बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बंद होने के कारण घरेलू बाजार में मांग और आपूर्ति के बीच एक अंतर उत्पन्न हुआ है, जिसके फलस्वरूप आयातों में वृद्धि हुई है।
137. प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया है। हितबद्ध पक्षकारों के पास इस प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रकटन का उत्तर देने के लिए केवल 5 कार्य दिवस थे।
138. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों को उनसे अपेक्षित सूचना का नोटिस दिया जाना चाहिए। प्राधिकारी ने असंबंधित मध्यवर्तियों की सूचना प्रस्तुत न करने के संबंध में प्रतिवादियों को कोई नोटिस नहीं दिया है। प्राधिकारी इस प्रश्नावली के उत्तर में उत्पादक द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों पर विचार करने में असफल रहा है। प्राधिकारी ने अपेक्षाकृत अधिक सूचना प्राप्त करने के लिए कोई कमी जापन जारी नहीं किया है। प्राधिकारी द्वारा जारी की गई सत्यापन रिपोर्ट यह सिद्ध करती है कि प्रस्तुत किये गये और सत्यापित आंकड़े प्राधिकारी की अपेक्षा के अनुरूप थे। प्राधिकारी को प्रतिवादी के अनुरोधों और आंकड़ों पर विचार करते हुए नया प्रकटन विवरण जारी करना चाहिए।
139. प्राधिकारी ने निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध का समाधान नहीं किया है:
  - क. घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति और बी जी पी पी एल और टी एन पी एल का कार्य निष्पादन।
  - ख. अन्य कारकों जिसके कारण टी एन पी एल को क्षति हुई है के प्रभाव का समायोजन।
  - ग. घरेलू उद्योग से घोषणा और प्रमाणन की कमी सहित जांच शुरू करने के पूर्व साक्ष्य की पर्याप्तता और सटीकता।
  - घ. कारणात्मक संबंध के विश्लेषण से संबंधित अनुरोध।
  - ङ. समान वस्तु, सूचना की गोपनीयता और क्षति के खतरे के संबंध में अनुरोध।
140. घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र बी जी पी पी एल को हटाने का निर्णय एक तरफा है और घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र को बदलने के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है। हितबद्ध पक्षकारों को अपने हित की रक्षा करने के लिए नोटिस नहीं दिया गया था।
141. तीन मिलों नामतः पी टी इन्डहा कियात पल्प एंड पेपर टीबीके() आई के, पी टी पिंडो दिल्ली पल्प एंड पेपर मिल्स) पी डी (एंड पी टी पात्रिक कटार जीवि किमिया टीबीके) टी के (ने सामान्य मूल्य के संबंध में पूर्ण और सही सूचना प्रस्तुत की और इस कारण से उनके सामान्य मूल्य को अस्वीकार करना उपयुक्त नहीं है।
142. प्राधिकारी ने प्रतिवादी के निर्यात कीमत को इस आधार पर एकपक्षीय रूप से अस्वीकार किया है कि असंबंधित व्यापारिक के माध्यम से किया गया निर्यात वास्तविक है। उत्पादकों का असंबंधित व्यापारियों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है और वे उन्हें इस जांच में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। प्राधिकारी ने सूचना का



सत्यापन किया यद्यपि इसे यह मालूम था कि प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं करने का आशय यह होता है कि असंबंधित आयातकों द्वारा कानूनन भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

143. अन्य पाटनरोधी जांचों में प्राधिकारी ने उत्पादकों के उत्तर को स्वीकार किया है यद्यपि असंबंधित व्यापारियों ने भाग नहीं लिया है। प्राधिकारी का निर्णय अन्य देशों की समझ और रिवाज के विरुद्ध है।
144. पहुंच मूल्य को कारखानागत कीमत, सी एफ आर कीमत अथवा एफ ओ बी कीमत के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। अंतिम कीमत जिस पर व्यापारी ने भारत में इन वस्तुओं की फिर से बिक्री की है, को परिशिष्ट 2 में शामिल किया गया था।
145. प्रकटन विवरण में दी गई सूचना से कोई संशय नहीं रह जाता है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं उठानी पड़ रही है। हाल की अनेक जांचों में प्राधिकारी ने इसी पाटनरोधी शुल्कों की सिफारिश इस आधार पर पर्याप्त पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के होने के बावजूद नहीं की थी कि घरेलू उद्योग को पर्याप्त लाभ हुआ है और संबद्ध वस्तुओं के आयातों को घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।
146. आयातों और घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। टी एन पी एल नकारात्मक कार्य निष्पादन के कुछ संकेतों को दर्शाता है परंतु इस तथ्य के कारण की टी एन पी एल को पानी की कमी के कारण बंद कर दिया था। आयात की कीमतों और घरेलू उद्योग के कीमतों के बीच कोई सह-संबंध भी नहीं है।
147. प्राधिकारी को सूचना की गोपनीयता के दावे का अवश्य मूल्यांकन करना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्ट्रलाइट इंडस्ट्रीज के मामले में यह माना है कि गोपनीयता स्वतः नहीं दी जा सकती है और यह जांच के माध्यम से ही आधारित की जानी चाहिए।
148. प्राधिकारी को विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र की पुष्टि करनी चाहिए जैसा कि जांच आरंभन के नोटिस और इसके अंतिम जांच परिणाम में प्रकटन विवरण में प्रकट किया गया है।
149. प्राधिकारी ने बिल्कुल सही तरीके से घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र का आकलन किया है और यह क्षति के निर्धारण के उद्देश्य से घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र के बी जी पी पी एल को बाहर करने में सही है।
150. एपीआरआईएल ग्रुप ने अपने पाटन मार्जिन की गणना के संबंध में निम्नलिखित मुद्दे उठाये हैं :
  - क. एपीआरआईएल ग्रुप का जर्काता कार्यालय घरेलू बिक्री में भी शामिल है और तदनुसार इसके खर्च प्रत्यक्ष रूप से घरेलू बिक्री से संबंधित हैं। इस प्रकार के खर्चों की कटौती सामान्य मूल्य की गणना से की जानी चाहिए। इस प्रकार कटौती को अस्वीकार करना विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करने के बाद अनुचित है कि प्राधिकारी ने भारतीय कार्यालय के जी एंड ए खर्चों तथा सिंगापुर /मेकाऊ निर्यातकों के जी एंड ए खर्चों दोनों के लिए इस आकलन के आधार पर निर्यात कीमत से कटौती की है कि ऐसे खर्च एकमात्र रूप से निर्यात से संबंधित हैं।
  - ख. इसी प्रकार से, विज्ञापन से संबंधित खर्चों को भी घरेलू बाजार में उत्पादकों द्वारा की गई घरेलू बिक्री से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा गया है और प्राधिकारी द्वारा कारखानागत सामान्य मूल्य का निर्धारण करते समय इसकी अनुमति दी जानी चाहिए।
  - ग. एपीआरआईएल ग्रुप के उत्पादक और निर्यातक एकमात्र आर्थिक प्रतिष्ठान के रूप में कार्य कर रहे हैं और विचाराधीन उत्पाद के सभी निर्यात और उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया गया गैर विचाराधीन उत्पाद संबंधित निर्यात कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। संबंधित निर्यातकों का लाभ और अप्रत्यक्ष एस जी ए खर्चों को निबल निर्यात कीमत तय करते समय कटौती नहीं की जानी चाहिए थी क्योंकि सिंगापुर /मेकाऊ में संबंधित निर्यातक उत्पादकों का एक विपणन प्रभाग के रूप में कार्य कर रहा है।
151. प्रकटन विवरण में निहित आर्थिक मानदंडों के विश्लेषण के अनुसार घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। आर्थिक मानदंडों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में क्षति की जांच की अवधि के दौरान सुधार हुआ है।
152. निरमा लिमिटेड बनाम संघ सरकार में विवाद गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, क्षति का मार्जिन केवल पाटनरोधी शुल्क की मात्रा का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्षति मार्जिन का मौजूद रहना इस बात का निर्धारण करते समय महत्वपूर्ण नहीं है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण कोई क्षति हो रही है अथवा नहीं।

153. प्राधिकारी ने सही रूप में इस बात का निर्धारण किया है कि संबद्ध उत्पाद के आयातों के कारण कीमत पर कोई दबाव अथवा उसमें ह्रास नहीं हुआ है। पैरा 100 (ग) में प्राधिकारी ने भूलवश यह नोट किया है कि संबद्ध देशों से आयातों के कारण कीमत पर कोई दबाव नहीं पड़ा है।
154. एक अन्य हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू बिक्री में शामिल संबंधित पक्षकार से उत्तर प्राप्त न होने के कारण अपने प्रश्नावली के उत्तर को अस्वीकार किये जाने के संबंध में टिप्पणी की है:
- क. स्वतंत्र ग्राहकों से संबंधित प्रतिष्ठान की पुनः बिक्री कीमत का सत्यापन किया गया था और संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा बेचे गये सामानों और असंबंधित प्रतिष्ठान को बेचे गये सामानों की कीमतों की तुलना की जा सकती थी। संबंधित प्रतिष्ठान की लेखा परीक्षित लेखाओं का भी सत्यापन किया गया था। प्राधिकारी द्वारा जारी की गई सत्यापन रिपोर्ट में इन तथ्यों को नोट किया गया है।
  - ख. संबंधित प्रतिष्ठान की आय, संबंधित प्रतिष्ठानों और उत्पादों द्वारा स्वतंत्र ग्राहकों को कीमतों की तुलना, संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा की गई बिक्री का लेन देन वार ब्यौरा अब सुलभ संदर्भ के लिए दिया गया है।
  - ग. अधिनियम, नियमावली, अधिसूचना, व्यापार नोटिस अथवा अन्य निवेशों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके लिए किसी संबंधित प्रतिष्ठान को एक पृथक उत्तर दायर करने के लिए निर्यात करने वाले देश में घरेलू बिक्री में शामिल होने की आवश्यकता है।
  - घ. उत्पादक द्वारा दी गई सूचना में पाटनरोधी करार के अनुबंध II के पैरा 3 के अंतर्गत सभी मानदंडों को पूरा किया गया। सूचना को केवल इस कारण से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि यह आदर्श नहीं है।
  - ङ. अपने उत्तर को अस्वीकार किये जाने के बारे में निर्यातक /उत्पादक को सूचित नहीं करना पाटनरोधी करार के अनुबंध II के पैरा 6 में निर्धारित प्रक्रिया संबंधी रक्षोपायों का उल्लंघन है।
  - च. निर्यात कीमत के उपयोग के संबंध में कोई समस्या नहीं थी। निर्यात कीमत से संबंधित सूचना को अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रश्नावली के उत्तर को अस्वीकार करने के लिए पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 6.8 में उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं किया गया है और इस कारण से इस मामले में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

### ब. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

155. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग को क्षति से संबंधित सूचना और अन्य महत्वपूर्ण सूचना प्रकट की है, जो उन्हें सार्थक टिप्पणियां उपलब्ध कराने में सक्षम बनायेगा।
156. सत्यापन रिपोर्ट को प्रकट करने के लिए प्राधिकारी का कोई विगत रिवाज नहीं है। इसके अलावा, यह सभी सूचनाएं गोपनीय प्रकृति की हैं और इसका संक्षिप्त रूप नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को घरेलू उद्योग तथा घरेलू उद्योग का अन्य पक्षकारों को सत्यापन रिपोर्ट प्रकट नहीं करते हैं।
157. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली तथा अपनी सतत रिवाज के अनुसार ही सहयोगी पक्षकारों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है।
158. हितबद्ध पक्षकारों ने एक दावा किया है कि बी जी पी पी एल को क्षति के आकलन के उद्देश्य से घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र से बाहर किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग बी जी पी पी एल के कार्य निष्पादन को बाहर किये जाने के बाद क्षति के आकलन के लिए भी सहमत हुआ। प्राधिकारी ने इस मुद्दे की जांच की है और यह निर्धारित किया कि बी जी पी पी एल को घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र से बाहर किया जाना चाहिए क्योंकि यह अपने निजी अंतर्निहित कारणों से जांच की अवधि के एक बड़े हिस्से के दौरान संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर रहा था।
159. वास्तविक क्षति का आकलन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों और पर्याप्त सत्यापन के बाद घरेलू उद्योग से प्राप्त हुई सूचना के आधार पर थी। प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम को जारी करने से पूर्व विचाराधीन आवश्यक तथ्यों को शामिल करते हुए प्रकटन विवरण को जारी कर जांच कार्यवाहियों में अपने मानक रिवाज का पालन किया है और स्थापित क्रम को बनाये रखा है। इस प्रकार से, यह दावा नहीं किया जा सकता है कि हितबद्ध पक्षकारों को क्षति के ऐसे आकलन के संबंध में प्रकटन विवरण को जारी करने से पूर्व नोटिस नहीं किया गया था। इस संबंध में घरेलू उद्योग अथवा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई नए दावे नहीं किये गये हैं।
160. किसी भी मामले में प्रकटन विवरण में प्रकट किये गये तथ्य प्राधिकारी की अंतिम सिफारिश नहीं है। हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन विवरण का उत्तर देने के लिए अवसर दिया गया है और प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा टिप्पणियों पर विचार करने के बाद अपना अंतिम निर्णय जारी करेंगे। इस प्रकार से, ऐसा नहीं कहा जा सकता है हितबद्ध पक्षकारों को उन्हें अपना बचाव करने में समर्थ बनाने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया है।

161. आयातों में वृद्धि बी जी पी पी एल द्वारा उत्पादन को स्थगित किये जाने के फलस्वरूप हुआ है। यहां यह नोट करना संगत है कि अन्य भारतीय उत्पादक अर्थात् याचिकाकर्ताओं (बी जी पी पी एल सहित) को बाहर करना जांच की अवधि में अपनी बिक्री को बढ़ाने में सक्षम थे। इस प्रकार से, यह कहना सही नहीं है कि घरेलू उद्योग आयातों में वृद्धि के कारण जांच की अवधि में उत्पादन और बिक्री में वृद्धि करने में सक्षम नहीं थे।
162. घरेलू उद्योग ने अपने दावे की पुष्टि करने के लिए कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है कि उच्च क्षमता के उपयोग पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें अन्य उत्पाद ही शामिल हैं जिन्हें वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र के भीतर शामिल नहीं किया गया है।
163. प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में आर्थिक मानदंडों के आकलन के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये दावों की पहले ही जांच की है। कोई नहीं सूचना अथवा टिप्पणियां हितबद्ध पक्षकारों अथवा घरेलू उद्योग द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत नहीं की गई है।
164. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के बाद के आयात आंकड़ों को यह दर्शाने के लिए प्रस्तुत किया है कि संबद्ध देशों से आयातों और माल भंडारों ने जांच की अवधि के बाद की अवधि में कमी आई है। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि बी जी पी पी एल अपने उत्पादन को फिर से शुरू करने में सक्षम हो पाया है यद्यपि यह पूर्ण स्तर पर कार्य नहीं कर रहा है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना प्राधिकारी द्वारा की गई जांच का समर्थन करता है कि घरेलू उद्योग को क्षति का कोई लगातार खतरा नहीं है।
165. इंडोनेशिया की सरकार द्वारा सब्सिडी देना वर्तमान पाटनरोधी जांच के कार्यक्षेत्र से बाहर है और इसकी जांच क्षति के खतरे के संबंध में दावे की पुष्टि करने के लिए नहीं की जा सकती है। घरेलू उद्योग द्वारा क्षति के खतरे के मौजूद होने के संबंध में किये गये सभी अन्य दावों की जांच प्राधिकारी द्वारा प्रकटन विवरण में की गई है।
166. कुल 7 दिनों अर्थात् 5 कार्य दिवस प्राधिकारी द्वारा प्रकटन विवरण का उत्तर देने के लिए दिए गए थे। प्राधिकारी द्वारा प्रकटन विवरण का उत्तर देने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को 5 कार्य दिवस का दिया गया समय पर्याप्त नहीं है और यह विगत जांचों में प्राधिकारी की इसकी सतत् रिवाज के अनुसार है। यह भी नोट किया जाना अपेक्षित है कि पाटनरोधी समयबद्ध है और इस कारण से जांच की प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना अपेक्षित है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।
167. आवेदन में घरेलू उद्योग ने भूलवश टी एन पी एल के प्रमाणन को संलग्न नहीं किया था। इससे जांच आरंभ करने अथवा घरेलू उद्योग की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई नई सूचना अथवा तर्क पर्याप्तता के मुद्दे के संबंध में नहीं किया गया है और साक्ष्य सटीकता को उजागर किया गया था।
168. गोपनीयता के संबंध में दावों की जांच प्राधिकारी द्वारा प्रकटन विवरण के खंड ड में किया गया था। कोई नए दावे अथवा अनुरोध इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों अथवा घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया गया है। प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावे को जहां भी आवश्यक हुआ स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना पर गोपनीय के रूप में स्वीकार किया गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसे प्रकट नहीं किया गया है।
169. प्राधिकारी ने बी जी पी पी एल के कार्य निष्पादन को बाहर करने के बाद घरेलू उद्योग को समग्र क्षति का आकलन किया है। तमिलनाडू में पानी की कमी और अन्य कारक जो पठित रूप से टी एन पी एल को क्षति पहुंचा रहे हैं, घरेलू उद्योग के समग्र कार्य निष्पादन को प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है।
170. असंबंधित व्यापारी की भागीदारी की आवश्यकता के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोई उत्पादक हमेशा ऐसी स्थिति में नहीं हो सकता है जिससे की वह असंबंधित व्यापारियों की भागीदारी सुनिश्चित करे। हालांकि, यदि असंबंधित व्यापारी जो भारत में निर्यात के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार हों, प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं करते हैं तब प्राधिकारी निर्यात किये गये संबद्ध वस्तुओं का भारत में निर्यात कीमत का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। परिणामस्वरूप प्राधिकारी इस प्रकार के उत्पादक/निर्यातक के लिए अलग अलग पाटन का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। इसमें पाटन और क्षति के दावों का उचित रूप से मूल्यांकन करने के लिए प्राधिकारी की क्षमता पर उत्तर न देने वाले और असंबंधित निर्यातकों की भागीदारी नहीं होने का प्रभाव का आकलन किये जाने की आवश्यकता है। इस मामले में असंबंधित व्यापारी द्वारा भारत निर्यात की सीमा 40 प्रतिशत के करीब है जो किसी भी रूप में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि असंबंधित व्यापारी वास्तव में उत्पादक की भारतीय सहायक कंपनी को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात कर रहा है और यह निश्चित रूप से ऐसे व्यापारी पर नियंत्रण की कमी का दावा पर प्रश्न खड़ा करता है।
171. भारत में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री में लगे हुए निर्यातकों का उत्तर क्षति के मार्जिन के आकलन के लिए भी अपेक्षित है। यदि निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं करता है, तब प्राधिकारी उन वस्तुओं जिन्हें भारत में निर्यात के

लिए बेचा जाता है, के लिए वास्तविक रूप में भुगतान की गई कीमत को नहीं जान सकते हैं और संबद्ध वस्तुओं का सही सही मूल्य जो क्षति के मार्जिन के आकलन के लिए आवश्यक है, का निर्धारण नहीं कर सकते हैं।

172. प्राधिकारी अंतिम कीमत जिस पर व्यापारी ने भारत में उन वस्तुओं को फिर से बेचा है, के संबंध में उत्पादक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। यदि व्यापारी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं करता है और जांच की प्रक्रिया में भाग लेता है तब इस प्रकार की सूचना की सत्यता का सत्यापन नहीं किया जा सकता है। यह विशेषकर उत्पादकों से संबंधित व्यापारियों के लिए है और जिन पर इसका उचित रूप में अनुमान लगाया जा सकता है, उत्पादकता उस पर नियंत्रण है और इस जांच में पूर्ण रूप से भाग लेना सुनिश्चित कर सकता है।

## ट. उच्च न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप अनुरोध

### ट.1 याचिकाकर्ता (निर्यातक) द्वारा अनुरोध

173. मैसर्स पीटी इंडिया क्लियरिंग एंड पेपर टीबीके; पीटी पिंडो दिल्ली पल्प एंड पेपर मिल्स (पीडी); और पीटी पात्रिक कर्टास जीबी किमिया टीबीके ("याचिकाकर्ताओं") से प्रकटन पश्चात टिप्पणियां प्राप्त हुईं।
174. प्राधिकारी द्वारा नए सिरे से सुनवाई की जानी चाहिए क्योंकि नए तथ्य सामने लाए गए हैं और प्रकटन विवरण में नए मुद्दे उठाए गए हैं।
175. असंबद्ध व्यापारी द्वारा प्रश्नावली का उत्तर दायर न किए जाने के कारण अवशेष शुल्क लगाने का कानून में किसी भी प्रावधान द्वारा समर्थन नहीं है। असंबद्ध व्यापारी से प्रतिभागिता प्राप्त करना उनके नियंत्रण से बाहर है।
176. प्राधिकारी ने असंबद्ध व्यापारियों से सूचना का अनुरोध करते हुए कोई कमी का ज्ञापन अथवा पूरक प्रश्नावली नहीं उठाई है।
177. यह तथ्य कि सत्यापन प्रश्नावली का उत्तर दायर न किए जाने के बावजूद किया गया था, इस तथ्य का प्रमाण है कि यह आवश्यकता न तो संगत है और न कानून द्वारा अपेक्षित है।
178. असंबद्ध व्यापारियों के माध्यम से भारत को की गई बिक्री के संबंध में सूचना प्राधिकारी को प्रश्नावली के उत्तर में दी गई थी। इस प्रकार, समस्त आवश्यक सूचना प्राधिकारी को अवगत कराई गई थी।
179. असंबद्ध व्यापारी का दायित्व प्रश्नावली के उत्तर दायर करने का नहीं है। किसी भी दशा में असंबद्ध व्यापारी को प्रश्नावली का उत्तर दायर करने की सूचना कभी नहीं दी गई थी। इसके अतिरिक्त, प्रश्नगत असंबद्ध व्यापारी सिंगापुर से संबद्ध सामानों का वास्तविक रूप में निर्यात नहीं कर रहा है, परंतु सामानों का लदान भारत के लिए इंडोनेशिया से किया जाता है। असंबद्ध व्यापारी केवल बीजक जारी करने में शामिल है।
180. प्राधिकारी ने विगत में उस समय भी अन्य मामलों में अलग-अलग पाटन मार्जिन की सिफारिश की है जब असंबद्ध व्यापारियों से कोई सहयोग नहीं था। यह निर्णय लेने के लिए कि क्या सहयोगी निर्यातकों के उत्तर स्वीकार किए जाएं अथवा रद्द किए जाएं, "असंबद्ध व्यापारी" के माध्यम से बिक्री की मात्रा के संबंध में कोई मात्रात्मक निर्धारण करना पूर्णतः गैर-कानूनी होगा। इसके अतिरिक्त, इस मामले में भारत में जिस निर्यात के लिए उत्तर दायर किए गए हैं, वे काफी हैं अर्थात् 60 प्रतिशत से अधिक हैं।
181. न्यायालय ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि भारत को लगभग 60 प्रतिशत निर्यात के संबंध में रिकार्ड में उपलब्ध सूचना की जांच की जानी चाहिए जिसका स्पष्ट रूप से यह अभिप्राय है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी का पूरे समूह को असहयोगी मानने का निर्णय सही नहीं था।
182. उत्तरदाताओं की भारत में कोई संबद्ध आयातक कंपनी नहीं है। एपीपी (इंडिया) पेपर प्रा. लि. शेयरहोल्डिंग अथवा डायरेक्टरशिप द्वारा उत्तरदाताओं से संबद्ध कंपनी नहीं है।
183. सामान्य मूल्य को अस्वीकार करना सही नहीं है क्योंकि उत्तरदाताओं की तीनों मिलों ने पूरी सूचना दी और उस सूचना का जांच की कार्यवाहियों के दौरान सत्यापन भी किया गया था।
184. निर्यात कीमतों के संबंध में सूचना स्वीकार की जानी चाहिए क्योंकि कारखानागत निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए पूर्ण आवश्यक सूचना उपलब्ध है। धारा 9क(1)(ख) के अनुसार कारखानागत निर्यात कीमत प्राधिकारी को मालूम है अर्थात् असंबद्ध मध्यवर्ती के उत्तरदाताओं की निर्यात कीमत प्राधिकारी को उनकी प्रश्नावली के उत्तर के माध्यम से ज्ञात है और इसीलिए निर्यात कीमत का निर्माण करने का प्रश्न नहीं उठता। असंबद्ध मध्यवर्ती और उत्तरदाताओं या यहां तक कि भारत में आयातक के बीच किसी प्रतिपूरक व्यवस्था के संबंध में कोई प्रकथन नहीं है।
185. यहां तक कि यदि निर्यात कीमत को रद्द किया जाता है तो एपीपी ग्रुप को असहयोगी नहीं माना जा सकता क्योंकि पूरे आंकड़े और सूचना उपलब्ध कराई गई थी और प्राधिकारी द्वारा उसका सत्यापन भी किया गया था।

186. यदि उत्पादक पहली बिक्री के समय यह जानता है कि उत्पाद भारतीय बाजार के लिए ही बनाया गया है, तो पहली बिक्री वह कीमत संबंधी सूचना निर्यात कीमत का परिकलन करने के लिए संगत है। निर्यात बिक्री की परिभाषा का यह निर्वचन यूरोपीय आयोग, यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया द्वारा अपनाया जाता है।
187. पहुँच मूल्य इस मामले में तथ्यों और परिस्थितियों में आसानी से निर्धारणीय है। भारत को मैसर्स लीकोनफील्ड्स की बिक्री की सीआईएफ कीमतें प्रश्नावली के उत्तर के परिशिष्ट-II में विधिवत शामिल की गई थी। प्राधिकारी को पहुँच मूल्य निकालने के लिए पत्तन सार-संभाल प्रभार, उप कर और आधारभूत सीमा शुल्क शामिल करने की अपेक्षा है। इस सूचना का सत्यापन, सत्यापन दौरे के दौरान किया गया था। इसके अतिरिक्त, एपीपी (इंडिया) प्रा. लि. की आयातक प्रश्नावली के उत्तर में वास्तविक सीआईएफ कीमतों के साथ आयातों के पूरे ब्यौरे हैं। सीआईएफ कीमतें लेन-देन वार डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों से भी सत्यापित की जा सकती हैं। जहाँ लेन-देन सीएफआर कीमतों पर आधारित होती हैं, वहाँ निर्दिष्ट प्राधिकारी की यह सतत परिपाटी रही है कि वे इसे राष्ट्रीय बीमा के घटक में शामिल करें।

## ट.2 उत्तरदाता (घरेलू उद्योग) द्वारा अनुरोध

188. संबंधित निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर वर्तमान मामले में निर्यात कीमत स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है और संबंधित निर्यातक सहयोग करने में विफल रहा। जिस कीमत पर भारतीय आयातक को सामानों की बिक्री की गई है, जो कि निर्यात कीमत स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है, वह निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर के बिना सिद्ध नहीं की जा सकती।
189. उत्पादक और निर्यातक के बीच लेन-देन निर्यात कीमत को निर्धारित करने के लिए अपर्याप्त हैं। ये केवल दो पक्षकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय बिक्री के लेन-देन हैं और निर्यात कीमत स्थापित करने के लिए अपर्याप्त हैं। निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए उस कीमत के संबंध में सूचना और साक्ष्य की आवश्यकता होती है जिस पर भारतीय आयातक की ओर सामानों के बीजक बनाए गए हैं।
190. ऐसी स्थिति में जहाँ उत्पादक की संबद्ध कंपनी उत्पाद का एक आयातक है और अन्य आयातकों के लिए आयातों की व्यवस्था की है, वहाँ उत्पादक विरोध नहीं कर सकता कि उसे वह सहयोग प्राप्त नहीं कर पाया।
191. संबंधित निर्यातक द्वारा असहयोग के मामले में प्रश्नावली के उत्तर को रद्द करना प्राधिकारी की एक स्थापित परिपाटी है, जैसा कि यूएसबी फ्लैश ड्राइव, एसिटोन, हॉट रोलड फ्लैट प्रोडक्ट्स – 304, सोलर सेल्स, पीटीए, एमडीएफ आदि के मामलों में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणामों में स्थापित किया गया है। ये केवल विवरणात्मक हैं। वस्तुतः इस आधार पर निर्णीत कई मामले हैं।
192. वर्तमान मामले में भी एपीपी समूह, इंडोनेशिया की एक समूह कंपनी पीटी इंदहा ने प्रश्नावली के पूर्ण उत्तर दायर नहीं किए हैं क्योंकि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री में लगी मैसर्स लीकोनफील्ड्स, सिंगापुर जैसे संबद्ध पक्षकार की मौजूदगी के बावजूद वे आगे नहीं आए हैं।
193. पीटी इंदहा और लीकोनफील्ड्स के काफी व्यापारिक लेन-देन हैं और प्रति वर्ष 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का व्यापार है तथा उस सीमा तक भी हैं जिस सीमा तक भारत में उत्पादक का संबद्ध पक्षकार लीकोनफील्ड्स को ऑर्डर देता है न कि अपने निजी इंडोनेशियाई उत्पादक के साथ सीधे ही ऑर्डर देता है। यह अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाता है। किसी भी दशा में इन परिस्थितियों के तहत उत्पादक प्रश्नावली के उत्तर की मांग करने के लिए असमर्थता का तर्क नहीं दे सकता।
194. लीकोनफील्ड्स से प्रश्नावली का उत्तर न आना कंपनी की असमर्थता के कारण नहीं है बल्कि निर्दिष्ट प्राधिकारी से महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने के लिए प्रश्नावली के उत्तर दायर न करने का पक्षकारों के जान-बूझकर लिए गए निर्णय के कारण है। जैसा कि, जिस कीमत पर उत्पादक ने उत्पाद बेचा और जिस कीमत पर भारतीय ग्राहकों के लिए सामानों के बीजक बनाए गए के बीच काफी अंतर से पूर्णतः सिद्ध है।
195. उत्पादक द्वारा दायर प्रश्नावली का उत्तर अतिरिक्त रूप से इस आधार पर अपूर्ण है कि संबंधित निर्यातकों ने केवल प्रतिभागी उत्पादक द्वारा उत्पादित सामानों का निर्यात नहीं किया है बल्कि संबद्ध देशों से गैर-प्रतिभागी असंबद्ध उत्पादकों द्वारा भी किया है। यह निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर को छिपाने का एक कारण है।
196. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली का अवलोकन यह दर्शाता है कि उसमें यह परिकल्पना की गई है कि पाटन मार्जिन उन (क) निर्यातक उत्पादकों के लिए और (ख) निर्यातकों के लिए हैं जो संबद्ध सामानों के उत्पादक नहीं हैं। बाद की स्थिति में निर्यातकों को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए संबंधित उत्पादक का सहयोग लेना अपेक्षित होता है। पूर्व स्थिति में निर्यातक का सहयोग और उत्तर इस तथ्य के मद्देनजर महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह अंतिम कीमत जिस पर भारत को सामानों का निर्यात किया गया है, उस निर्यातक की कीमत से है।

197. वेबसाइट के उद्धरणों के रूप में घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए साक्ष्य इन तथ्यों को सिद्ध करते हैं कि (क) मैसर्स लीकोनफील्ड्स पीटी इंडिया के साथ काफी व्यापार करता है (क्योंकि वह पीटी इंडिया से सामान खरीदता है) और (ख) लीकोनफील्ड्स कैपिटल एक एक्जैम्प्ट प्राइवेट कंपनी लिमिटेड है जो पेपर और पेपर उत्पादों की थोक बिक्री में लगा हुआ है और जिसका नियमित आधार पर 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का व्यापार है। ऐसी स्थिति में यह किसी भी उपयुक्त अवधारणा से परे है कि वह उत्पादक अपने उत्पादों के ऐसे भारी निर्यात करने वाले किसी निर्यातक से सहयोग और उसकी प्रश्रवावली के उत्तर लेने की स्थिति में न हो।
198. उत्पादक यह दावा नहीं कर सकता कि उसने निर्दिष्ट प्राधिकारी के साथ पूरा सहयोग किया है, जब उस कंपनी ने जो काफी 40 प्रतिशत लदान के लिए उत्तरदायी हो, प्रश्रवावली का उत्तर दायर न किया हो। यह इस तथ्य की अनदेखी स्थिति नहीं हो सकती कि निर्यातक कंपनी उत्पादक और भारतीय आयातकों के बीच बिचौलिया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं उत्पादकों की अपनी संबद्ध कंपनी (एपीपी इंडिया पेपर प्राइवेट लिमिटेड)।
199. यह वह मामला है जिसमें जान-बूझकर असहयोग किया गया है और तथ्यों को महत्वपूर्ण ढंग से छिपाया गया है तथा इस कारण प्रश्रवावली के उत्तर दायर नहीं किए गए हैं कि वह उत्पादक के लिए "कोई पाटन नहीं" सिद्ध करने में अत्यधिक असुविधाजनक है।
200. निर्यात कीमत के सत्यापन के प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को बिक्री बीजक, बिक्री बीजक के विरुद्ध प्राप्त भुगतान का प्रमाण दिए गए बैंक प्रभारों का प्रमाण, खरीद आदेश, समुद्री भाड़ा, बिल तथा भुगतान का प्रमाण तथा बीमा, खरीद कीमत के आलोक में निर्यात कीमत की उपयुक्तता जैसे दस्तावेजों की यह दर्शाने के लिए आवश्यकता होती है कि इन बिक्रियों, पक्षकार के खाते के विवरण में कोई हानि नहीं है – ये निर्यातक के पास हैं और उत्पादक इन दस्तावेजों में गुप्त नहीं है।
201. निर्यातक की प्रश्रवावली से यह सिद्ध है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी पहले से यह मानते हैं कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को उत्तर देने वाला पक्षकार एक व्यापारिक/निर्यातक कंपनी हो सकता है और वह उत्पादक कंपनी नहीं हो सकता, यदि उत्तर उस उत्पादक द्वारा दायर नहीं किया जा रहा है जो कि निर्यातक है, जैसा कि उसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर विशेष रूप से मांगे गए हैं।
202. सिंगापुर से वास्तविक रूप से उस कीमत से कम कीमत पर बहुत अधिक आयात हैं, जिस पर इंडोनेशिया से आयात किए गए हैं। निम्नलिखित तालिका में इसका सार है। कीमत अंतर की मात्रा काफी सजग करने वाली है और वस्तुतः वर्तमान जांच में निर्यातक द्वारा भाग न लिए जाने का एक कारण है।

क्रम सं.	देश	मात्रा (मी. टन)	दर (रु./मी. टन)	शेयर %
1	संबद्ध देश	73,897	47,461	98%
2	इंडोनेशिया	48,522	49,670	64%
3	थाइलैंड	4,259	56,215	6%
4	सिंगापुर	21,116	40,619	28%
5	अन्य देश	1,438	54,237	2%
6	सकल जोड़	75,335	47,590	100%

203. कमियों के अवसर का उपयोग प्रश्रवालियों के उत्तर दायर करने के लिए नहीं किया जा सकता जिसके लिए स्पष्ट एवं कठोर समय सीमाएं हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रश्रवावली के उत्तर में कमियां बताने के लिए ही जिम्मेदार हैं। यदि कोई पक्षकार प्रश्रवावली के उत्तर से पूर्णतः गायब है तो यह प्रश्रवावली के अपने उत्तर का मामला, उत्तर को जान-बूझकर रोकने का मामला है।
204. एनसीवी के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि एपीपी द्वारा रिकार्ड में लाए गए तथ्य और उनकी एनसीवी प्रश्रवावली के उत्तर में कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। इसमें यह भी दर्शाया गया है कि एपीपी ने एनसीवी की प्रश्रवावली के उत्तर में जान-बूझकर तथ्य को महत्वपूर्ण रूप से छिपाने का सहारा लिया है जिससे वस्तुतः घरेलू उद्योग वर्तमान जांच में प्रभावी रूप से भाग नहीं ले पाया।

205. उत्पादक ने अब एक मुद्दा उठाया है कि प्राधिकारी ने जो सत्यापन किया है, उसमें असंबद्ध निर्यातकों द्वारा असहयोग का मुद्दा नहीं उठाया गया है जिसमें इस संबंध में यह नोट करना व्यावहारिक है कि उत्पादक जांच के दौरान समुचित रूप से सभी तथ्यों को रिकार्ड में नहीं लाए और तथ्यों को महत्वपूर्ण रूप से छिपाने का सहारा लिया है। चूंकि, उत्पादक ने तथ्यों को काफी छिपाने का सहारा लिया है, अतः, वह उत्तर को रद्द करने के लिए प्राधिकारी को दोष नहीं दे सकता।
206. प्राधिकारी ने विगत कई मामलों में प्रश्नावली के उत्तर रद्द किए हैं जब कभी उत्पादक का उत्तर अपूर्ण था। यदि शुल्क किसी चैनल के लिए दिया गया है जब किसी निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है, तो यह केवल उन स्थितियों में है जहां गायब उत्तर महत्वपूर्ण अनुपात में नहीं है। वर्तमान मामले में गायब उत्तर कंपनी द्वारा किए गए कुल निर्यात में बहुत अधिक अनुपात बनाता है।
207. उत्पादक द्वारा उल्लिखित मामलों के संबंध में याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि निम्नलिखित कारणों से विश्वास करना पूर्णतः गलत है।
208. पॉलीप्रोपीलीन के मामले में शुल्क उस श्रृंखला के लिए निर्धारित किए गए थे जिसने सहयोग किया था, जिसका स्पष्ट अर्थ यह है कि निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यहां तक कि यदि उस निर्यातक का निर्यात 40 प्रतिशत तक अधिक हिस्सा है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी फिर भी ऐसे उत्पादक के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए बाध्य हैं।
209. पीएसएफ मामले में उत्पादक द्वारा संबद्ध सामानों का निर्यात सीधे ही और पांच (5) असंबद्ध व्यापारियों के माध्यम किया गया था जिसमें से एक संबंधित निर्यातक ने उत्तर नहीं दिया था और चूंकि, अधिकतर उत्तर दायर कर दिए गए थे, अतः प्राधिकारी ने उत्तर को स्वीकार किया। यह एक ऐसा मामला है जिसमें असहयोगी निर्यातक का निर्यात काफी कम था।
210. स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लेट उत्पादों के मामले में संबंधित आयातकों ने जांच में उत्तर नहीं दिया। प्राधिकारी ने पाया कि निर्यात कीमत संबंध से प्रभावित नहीं हुई थी और इस प्रकार निर्यात कीमत का निर्धारण ऐसे असंबद्ध निर्यातक से प्रश्नावली के उत्तर के बिना प्रभावित नहीं हुई थी।
211. निर्यातक का उत्तर इस कारण संगत है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को भारतीय सीमा शुल्क में सूचित कीमत के साथ निर्यातक – उत्पादक द्वारा किए गए दावों का सत्यापन करना अपेक्षित है। संबंधित निर्यातक के सहयोग के बिना निर्दिष्ट प्राधिकारी दावा की गई कीमत की सत्यता का सत्यापन नहीं कर सकते। उत्पादक उस कीमत को सिद्ध नहीं कर सकते जिस पर सामान भारतीय सीमा शुल्क को सूचित किए गए हैं। केवल संबंधित निर्यातक ही वह दे सकता है।
212. हाइड्रोजन पैराक्साइड के मामले के संदर्भ के संबंध में इस कारण से विश्वास पूर्णतः गलत किया गया है कि उसमें शामिल मुद्दा घरेलू उद्योग के क्षेत्र और तथाकथित संबंध के कारण उसकी पात्रता का था। उस मामले में जांच ने यह दर्शाया कि विदेशी उत्पादक ने घरेलू उद्योग के व्यापारिक क्रियाकलाप में भाग नहीं लिया। वर्तमान मामले में, उत्पादक और आयातक नियमित रूप से काफी व्यापार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, दोनों के बीच संबंध इस तथ्य से सिद्ध है कि बीना सिनार एमिटी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, सिंगापुर पीटीई लि., एपीपी इंडिया का 100 प्रतिशत शेयरधारक है जो कि सिना मैस ग्रुप का एक भाग है जो कि एपीपी की मूल कंपनी है।

### ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

213. सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9क(1)(ख) में यह प्रावधान है कि किसी वस्तु के संबंध में "निर्यात कीमत" का अर्थ वस्तु की उस कीमत से है जिस पर वह किसी निर्यातक देश या क्षेत्र से निर्यात की जाती है। उत्पादक द्वारा यह तर्क दिया जा सकता है कि उत्पादक ने व्यापारी को सामान जिस कीमत पर बेचा है वह कारखानागत निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए आधार हो सकती है। तथापि, यह तर्क गलत है क्योंकि कारखानागत निर्यात कीमत उस कीमत के आधार पर निकाली जानी होती है जिस पर व्यापारी/निर्यातक द्वारा भारत को सामानों की बिक्री की गई। प्राधिकारी को कारखानागत निर्यात कीमत का परिकलन करने के लिए उत्पादक तथा व्यापारी द्वारा किए गए बिक्री व्ययों को घटाना अपेक्षित है। निर्यातक से उत्तर प्राप्त न होने के कारण निर्यातक द्वारा किए गए बिक्री संबंधी व्यय प्राधिकारी द्वारा जांच और सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं हैं। परिणामस्वरूप, अलग-अलग पाटन मार्जिन उत्पादक के उत्तर के आधार पर ही निर्धारित नहीं किया जा सकता। साथ ही, प्राधिकारी यह नहीं जान पाएंगे कि क्या संबद्ध सामान हानियां खाकर कम कीमत पर अथवा उच्च कीमत पर निर्यात किए गए थे। उदाहरण के लिए, यदि उत्पादक ने व्यापारी को सामान 10 अमेरिकी डॉलर/मी.टन पर बेचा तो व्यापारी ने घाटा उठाकर भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात 9 अमेरिकी डॉलर/मी.टन पर और पाटन की मात्रा बढ़ाकर किया हो सकता है।
214. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी निर्यातकों ने उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए पाटनरोधी जांच में निर्यात कीमत का निर्धारण एक नाजुक कदम है। प्राधिकारी यह व्यापार के उसी स्तर पर निर्यात कीमत और

सामान्य मूल्य पर विचार करके यह कार्य करते हैं। प्राधिकारी की कारखानागत स्तर पर निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य की तुलना करने की स्थापित परिपाटी है। तुलनीय निर्यात कीमत निकालने के लिए इस आधार पर कि वह सीआईएफ/एफओबी/एफओआर आदि में कैसे दिखाई गई है, निर्यात कीमत में उपयुक्त समायोजन किए जाने की आवश्यकता है।

215. चूंकि, पाटन मार्जिन का निर्धारण प्रत्येक सहयोगी उत्पादक के लिए किया जाता है, अतः अभिज्ञात निर्यातों के प्रत्येक चैनल और उससे प्राप्त भारित औसत के लिए निबल निर्यात कीमत का निर्धारण करने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक चैनल सामान्यतः बराबर महत्वपूर्ण होता है जो निम्नलिखित है:

क. असंबद्ध भारतीय आयातकों को सीधे ही निर्यात;

ख. एक संबंधित भारतीय आयातक को निर्यात जो उसके बाद असंबद्ध भारतीय ग्राहकों को पुनः बिक्री करता है;

ग. एक असंबद्ध निर्यातक (किसी भी देश में) के माध्यम से असंबद्ध भारतीय आयातक को निर्यात; और

घ. एक संबद्ध निर्यातक (किसी भी देश में) के माध्यम से असंबद्ध भारतीय आयातक को निर्यातक।

216. इस प्रकार, उत्तरदाता उत्पादकों के लिए भारत में अपने सभी व्यापारिक चैनलों के संबंध में पूर्ण उत्तर दायर करना अनिवार्य है। जिन मामलों में निर्यात असंबद्ध निर्यातक/व्यापारी के माध्यम से हैं, उनमें असंबद्ध कंपनियों से भी उत्तर अपेक्षित हैं। यह विशेष रूप से उन मामलों में होगा, जहां जांच में भाग न ले रहे असंबद्ध निर्यातकों का भारत को निर्यात का हिस्सा संबंधित उत्पादक के निर्यात का काफी अनुपात है। ऐसे मामलों में उत्तरदाता उत्पादक को सामान्य रूप में असहयोगी माना जाएगा और पूरा उत्तर रद्द किए जाने योग्य होता है।

217. वर्तमान मामले में जिसमें असंबद्ध निर्यातक मैसर्स लीकोनफील्ड्स, सिंगापुर है, भारत को लगभग 40 प्रतिशत उत्पादक का निर्यात निर्यातित कर रहा है जिसे वह भारत में संबंधित पक्षकार अर्थात् एपीपी (इंडिया) पेपर प्रा. लि. (जिसके संपर्क व्यौरे एपीपी समूह की अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं) को आपूर्ति कर रहा है। प्राधिकारी के लिए यह स्वीकार करना कठिन है कि उत्पादक असंबद्ध निर्यातक का सहयोग लेने के लिए अपेक्षित नियंत्रण के स्तर पर कार्रवाई करने में और उसके उन निर्यातों जो भारत में संबंधित कंपनी प्रतीत होती है, से संबंधित लेन-देनों के आंकड़े/व्यौरे देने में सक्षम नहीं हैं।

#### ठ. भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दे

218. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन सामान्य रूप में पाटन की अनुचित व्यापारिक परिपाटियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में एक खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके जो कि देश के सामान्य हित में है।

#### ड. निष्कर्ष

219. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उसमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने के बाद तथा रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध देशों से भारत को उनके सामान्य मूल्य से कम पर विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया गया है और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों से वास्तविक क्षति हुई है।

#### ढ. सिफारिश

220. थाइलैंड, इंडोनेशिया और सिंगापुर से पाटित आयातों के कारण पाटन और क्षति के सकारात्मक निर्धारण को देखते हुए प्राधिकारी का यह मत है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों पर पाटनरोधी उपाय लगाए जाने की आवश्यकता है। प्राधिकारी यह आवश्यक मानते हैं और नीचे वर्णित स्वरूप तथा तरीके से संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

221. प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए "पाटन मार्जिन" और "क्षति मार्जिन" के कमतर के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं जो नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 8 में दर्शाई गई राशि तथा संबद्ध सामानों के पहुँच मूल्य के बीच का अंतर हो, बशर्ते कि पहुँच मूल्य कॉलम 8 में दर्शाए गए मूल्य से कम हो।



## शुल्क तालिका

क्रम सं.	शीर्ष/उप-शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि (अमेरिकी डॉलर/मी. टन)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	4802*	अनुमेय सीमाओं में निम्नलिखित आकारों के आयातकार शीट में कोट न किया गया पेपर (क) 210 मि.मी. x 297 मि.मी. जिसे ए 4आकार के रूप में भी जाना जाता है; (ख) 297 मि.मी. x 420 मि.मी. ए 3आकार के रूप में भी जाना जाता है; (ग) 215 मि.मी. x 345 मि.मी.	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया/सिंगापुर	क) पीटी रियाऊ अंदालन कर्टास ख) पीटी अनुग्रह कर्टास उटामा ग) पीटी एशिया पसिफिक रेयॉन	क) अप्रैल फाइन पेपर ट्रेडिंग पीटीई लि. ख) अप्रैल इंटरनेशनल इंटरप्राइज पीटीई लि. ग) अप्रैल फाइन पेपर मकाओ कामर्शियल ऑफशोर लिमिटेड	855.01
2.	- वही -	- वही -	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया/सिंगापुर	उपरोक्त क्रम सं .1 को छोड़कर कोई अन्य संयोजन		855.01
3.	- वही -	- वही -	इंडोनेशिया	कोई अन्य देश	कोई अन्य	कोई अन्य	855.01
4.	- वही -	- वही -	उनको छोड़कर जो पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन है	इंडोनेशिया/सिंगापुर	कोई अन्य	कोई अन्य	855.01
5.	- वही -	- वही -	थाइलैंड	कोई अन्य देश	कोई अन्य	कोई अन्य	855.01
6.	- वही -	- वही -	उनको छोड़कर जो भी देश जो पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन है	थाइलैंड	कोई अन्य	कोई अन्य	855.01

\* सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है तथा शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जाएगा।

222. इस प्रयोजन के लिए आयातों का पहुँच मूल्य मूल्यांकन योग्य मूल्य होगा, जैसा कि सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित किया गया है तथा उपर्युक्त की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के तहत शुल्कों को छोड़कर सभी सीमा शुल्क शामिल होंगे।
223. इस जांच परिणाम के कारण उत्पन्न होने वाली केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर अपील अधिकरण के समक्ष दायर की जाएगी।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION****New Delhi, 30th October, 2018****FINAL FINDINGS****(Case No.: OL.36/2017)**

**Subject : Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of “Uncoated Copier Paper” originating in or exported from Indonesia, Thailand and Singapore.**

**No. 6/32/2017 –DGAD.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as the Rules) thereof:

1. Whereas, M/s JK Paper Limited, The West Coast Paper Mills Limited, Tamil Nadu Newsprint and Papers Limited and Ballarpur Industries Limited/ BILT Graphic Paper Products Ltd. (hereinafter also referred to as the “Petitioners” or “Applicants”) have filed a petition before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for imposition of Anti-dumping duty on imports of “Uncoated Copier Paper” originating in or exported from Indonesia, Thailand and Singapore (hereinafter also referred to as the subject countries).
2. And, whereas, the Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the Petitioners, issued a Public Notice vide Notification No. 6/32/2017 -DGAD dated 2<sup>nd</sup> November, 2017, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with the Rule 5 of the above Rules to determine existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the DI.

**A. PROCEDURE**

3. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:
  - a) The Authority notified the Embassies of the Subject Countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.
  - b) The Authority issued a public notice dated 2<sup>nd</sup> November, 2017 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods.
  - c) The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassies of the Subject Countries in India, known producers/exporters from the subject Countries, known importers/users and the DI as well as other domestic producers as per the addresses made available by the applicants and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification.
  - d) The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassy of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.
  - e) The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.

f) The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

**Thailand**

- (i) Double A (Formerly Advance Agro)
- (ii) Panjapol Pulp Industry
- (iii) Phoenix Pulp and Paper
- (iv) SCG Paper
- (v) Oji Paper Thailand
- (vi) Environment Pulp and Paper

**Singapore**

- (vii) Ahf Industries
- (viii) Andoman Trading and Shipping Company Pte Ltd
- (ix) Cellmark Asia Pte Ltd
- (x) Asia Pulp and Paper Co Ltd
- (xi) Alliance Paper and Board Products Pte Ltd
- (xii) APPA (Singapore) Pte Ltd
- (xiii) Chuan Ann Paper Products

**Indonesia**

- (xiv) P.T. Pindo-Deli Pulp and Paper Mills ("PD")
- (xv) Indah Kiat Pulp and Paper PT
- (xvi) PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.
- (xvii) PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk.
- (xviii) PT. Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry ("Lontar")
- (xix) PT. Purinusa Ekapersada ("Purinusa")
- (xx) PT. Riau Andalan Pulp and Paper

g) In response, the following exporters/ producers from the subject countries filed exporter's questionnaire response in the prescribed format:

- (i) PT Riau Andalan Kertas, Indonesia
- (ii) PT Anugrah Kertas Utama, Indonesia
- (iii) PT Sateri Viscose International
- (iv) April Fine Paper Trading Pte Ltd, Singapore
- (v) April International Enterprise Pte Ltd, Singapore
- (vi) April Fine Paper Macao Commercial Offshore Limited, Macau
- (vii) PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Indonesia
- (viii) PT Pindo Delhi Pulp and Paper Mills, Indonesia and
- (ix) PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, Indonesia
- (x) Double A Double A (1991) Public Co Ltd, Thailand
- (xi) Advance Paper Mill 3 Co Ltd., Thailand
- (xii) Phoenix Pulp and Paper Public Co., LTD, Thailand

- h) The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers/ users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
- (i) Allied Speciality Papers (India) Pvt. Ltd.
  - (ii) Bhagwati Enterprises
  - (iii) Excel Enterprise
  - (iv) K.C. Exim (P) Ltd.
  - (v) Narsingh Dass and Co (P) Ltd.
  - (vi) Nutech Print Services- India
  - (vii) Paras Papers
  - (viii) Plus Marketing
  - (ix) Shah Devji Shivji and Co
  - (x) Sheth Brothers
  - (xi) Shree Balaji Udyog
  - (xii) Shree Chamunda Enterprises
  - (xiii) Standard Paper and Board India Pvt. Ltd.
  - (xiv) Synchem
  - (xv) Tenny Jose and Associates Ltd.
  - (xvi) Unique Sales Corporation
  - (xvii) White Arrow Group of Companies
- i) In response, none of the importers/users have responded and filed importer's questionnaire response.
- j) Apart from the respondent exporters and importers mentioned above, some legal submissions have been received on behalf of the following parties during the course of this investigation. However, no importer/exporter's questionnaire have been filed by the following parties:
- (i) All India Federation of Master Printers
  - (ii) Madan Papers Product, Bangalore
  - (iii) Everest Marketing, Madurai
  - (iv) Veera Printers, Chennai
  - (v) Globinet Computers, Harur
  - (vi) Kobster E-shop Pvt. Ltd., Chennai
  - (vii) O-Clock Software Pvt. Ltd., Chennai
  - (viii) Ananda Vikatan Publishers Pvt. Ltd., Chennai
  - (ix) Taj Paper Mart, Chennai
  - (x) B.S.L. & Co., Bangalore
  - (xi) M/s Roshan Enterprises, Salam
  - (xii) Reshma Agencies, Hanamkonda
  - (xiii) Hamster Global, Thrissur
  - (xiv) M/s RK Enterprises, Salem
  - (xv) Diya Distributors, Chalakudy
  - (xvi) Uday International, Hyderabad

- (xvii) Buizcard Print, Madurai
- (xviii) Palaniappa Cottage Industries, Chennai
- (xix) Swastik Paper Company, Chennai
- (xx) Sathya Traders, Chennai
- (xxi) Ketaki Engineering Pvt. Ltd., Chennai
- (xxii) Bhawar Paper Agency, Bangalore
- (xxiii) Hindustan Agencies, Gandhinagar
- (xxiv) Kamalsri Papers, Vijaywada
- (xxv) Kaveri International, Bangalore
- (xxvi) Eswari Papers, Vidhurunagar
- (xxvii) Sai Sakthi, Chennai
- (xxviii) Jaain Impex, Hyderabad
- (xxix) Shri Durga Paper Stores, Trichy
- (xxx) Meenu Paper Mart, Sivakasi
- (xxxi) Shri Balaji Paper and Stationery, Bangalore
- (xxxii) Sri Venkatesh Overseas, Hyderabad
- (xxxiii) United Paper Mart, Karur
- (xxxiv) Dhanalakshmi Paper Traders, Kovilpatti
- (xxxv) Golden Paper Mart, Pathanamthitta
- (xxxvi) J.M. Exim, Hyderabad
- (xxxvii) Vardhaman Paper Products, Vijaywada
- (xxxviii) Paris Papers and Stationeries, Chennai
- (xxxix) Sanjay Paper Company, Chennai
- (xl) AS Papers, Hyderabad
- (xli) Century Trading Company, Calicut
- (xlii) Shivgiri Papers and Stationery, Bangalore
- (xliii) Vijay Traders, Villupuram
- (xliv) AK Traders, Chennai
- (xlv) Micro Paper Products, Bangalore
- (xlvi) Ganesh Paper Agencies, Bangalore
- (xlvii) BS and Company, Guntur
- (xlviii) Shalima Paper Mart, Kannur
- (xlix) Maharashtra Paper Company, Pune
- (l) Ramani Paper Stores, Mumbai
- (li) DMS Corporation, Mumbai
- (lii) Roopam Paper Mart, Mumbai
- (liii) Eclat Papers, Thane
- (liv) Pro Media, Chennai
- (lv) Bimal Papers, Delhi

- (lvi) Tulsi Enterprises, Ahmedabad
- (lvii) Sudarshan Paper and Board Pvt. Ltd., Kolkata
- (lviii) Shah Devji Shivji and Co., Mumbai
- (lix) Shree Chamunda Multimax, Ahmedabad
- k) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- l) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCIS) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigations, which was received by the Authority. The Authority has, relied upon the DGCIS data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.
- m) The Non-Injurious Price (NIP) based on the cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry (DI) on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-Dumping Rules has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the DI.
- n) Physical inspection through on-spot verification of the information provided by the applicant domestic industries, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purposes of the present Notification.
- o) The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present anti-dumping investigation is from 1st April, 2016 to 31<sup>st</sup> June, 2017 (15 Months). The injury investigation period has however, been considered as the period from 2013-14, 2014-15, 2015-16 and the POI.
- p) In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 23<sup>rd</sup> March, 2018. All the parties who had attended the oral hearing were advised to file written submissions of the views expressed orally. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and were advised to offer their rebuttals.
- q) The arguments made in the written submissions/ rejoinders received from the interested parties have been considered in the present Notification.
- r) The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this Notification.
- s) Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- t) Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.
- u) All the comments received on the Disclosure Statement issued by the Authority, have also been appropriately addressed in this Finding.
- v) The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US\$1=₹67.45.
- w) One of the exporters filed a Writ Petition in the High Court of Delhi on 20.07.2018, regarding certain facts presented in the Disclosure Statement of the Authority. In its Order dated 23.10.2018, the Hon'ble High Court addressed the grievance by affording the petitioner another opportunity to make, what it considered, relevant submissions in writing particularly regarding

paragraph 40 of the Disclosure Statement. In providing this opportunity to the petitioner, the Hon'ble High Court also allowed the respondent - complainants to make its submissions in response to those of the petitioner. The Hon'ble High Court has directed that this entire process should be completed as fast as possible within five days and the final findings should be rendered by the DA.

## **B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**

### **B.1. Submissions by Domestic Industry**

4. The submissions made by the domestic industry with regard to product under consideration and like article and considered relevant by the Authority are as follows:
  - a) The product under consideration in the present investigation is “Uncoated paper in rectangular sheet of the following sizes with permissible limits (a) 210 mm x 297 mm also known as A4 size; (b) 297mm x 420mm also known as A3 size (c) 215mm x 345mm also known as FS or legal size; classifiable under 4802 of the Customs Tariff Act”. The four-digit HS code has been used for the purpose of identifying the imports of the product under consideration and in no way implies that the Petitioners have sought levy of duty on all the products falling under four-digit HS Code.
  - b) All kinds of coated paper and uncoated paper of a kind used for writing, printing, or other graphic purposes in reels or in large sized sheet are excluded from the scope of product under consideration.

### **B.2. Submissions by Other Interested Parties**

5. The submissions made by the exporters, importers, users and other interested parties with regard to product under consideration and like article, and considered relevant by the Authority, are as follows:
  - a) Product under consideration is very broad. Reference to 4-digit HS code is abnormal. It is required to be clarified if all production under HS code 4802 are included as part of the PUC or only specified products.
  - b) The interested parties have requested for a clarification whether uncoated copier paper imported in the form of Jumbo Rolls/Reels is part of PUC or not.
  - c) Coated paper is not part of the PUC. However, transaction wise import data provided by the Petitioners shows that the Petitioners have included these products as well while assessing total imports of the PUC.

### **B.3. Examination by the Authority**

6. The Authority has noted submissions made by various interested parties with regard to scope of the product under consideration and like article offered by the DI. With respect to the product under consideration, the Authority notes:
  - a) The product under consideration for the purpose of present investigation is “uncoated paper in rectangular sheet of following sizes, with permissible limits (a) 210mm x 297 mm also known as A4 size; (b) 297mm x 420mm also known as A3 size; (c) 215mm x 345mm also known as FS or legal size.” The product under consideration practically implies cut to size “uncoated copier paper”.
  - b) The product under consideration is generally (but not exclusively) used as a photocopy or copy paper and therefore is popularly known as “copy paper”, “copier paper”, “photocopy paper”, “multipurpose paper”, “uncoated copier paper”, “A4 Size Paper”, “A3 Size Paper” or “FS Size Paper”. It is in the form of finished sheets; weighing in different gsm. It can be a white paper or a punched paper and in different smoothness of the surface.
  - c) Regarding the PUC, the Authority examined the scope of possible circumvention of any anti-dumping duty, if imposed, by import of copier paper in rolls, reels and large sized sheet and cutting it to size in India. The DI as well as the exporters informed that this was not feasible as copier paper was traded in cut to size and packed sheets. The cost differential between copier paper sold in cut and sized packs and paper imported in rolls was very small, making any cutting

and packing operation commercially unviable. Thus, specifically excluded from the scope of the product under consideration are uncoated paper of a kind used for writing, printing, photocopying/copying, other graphic purposes etc. in rolls, reels and large sized sheet (i.e., other than sizes specified above) forms.

- d) Product under consideration is classified under customs heading 4802. The customs classification is indicative only and in no way, it is binding upon the product scope.

### **C. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING**

#### **C.1. Submissions by Domestic Industry**

7. The submissions made by the DI during the course of the investigation with regard to scope of DI & standing are as follows:
- a) Application was filed by M/s JK Paper Ltd., M/s West Coast Paper Mills Ltd., M/s Tamil Nadu Newsprint and Papers Ltd. and M/s Ballarpur industries Ltd. who produces subject goods in its subsidiary BGPPL.
  - b) Petitioners have not imported the product under consideration and are not related to any importer in India or exporter from subject countries and have not imported the product under consideration.
  - c) Indian Paper Manufacturer's Association (IPMA) maintains records of production by IPMA members as well as non-members. Production figures of other Indian producers have been determined based on data maintained by IPMA.
  - d) Petitioners have inadvertently missed enclosing of authorisation letter of TNPL along with the petition. Even in absence of TNPL, share of DI will be 44%, which should be considered as major proportion.
  - e) Even if the Authority ignores BILT, DI will have standing and it will be seen that DI is suffering injury.

#### **C.2. Submission of Other Interested Parties**

8. Other interested parties have made the following submissions:
- a) Constituents of the DI are not the same in the updated information. Updated petition provides name of BILT Graphic Paper Products Ltd ("BGPPL") (subsidiary of Ballarpur Industries Limited) instead of Ballarpur Industries Limited as the name of Petitioners company
  - b) There are many other producers of uncoated paper in India in addition to the producers listed in the petition. Names of these producers are available in public domain. DI has not identified these producers by name and it is not clear if production of these producers is accounted for while determining total production of like product.
  - c) Petition contained authorization and declaration from West Coast Paper Mills Ltd. & JK Paper Ltd. There was no authorisation letter from Tamil Nadu Newsprint and Paper Ltd. and Ballarpur Industries Ltd. There was no certification regarding absence of imports, absence of related importer of the PUC in India, absence of related exporter of the PUC in the subject countries from TNPL and BILT either.
  - d) There is no certification from any of the constituents of DI regarding the absence of imports for the updated POI i.e. for last quarter of the POI - April 2017 to June 2017.
  - e) Investigation should be terminated owing to non-disclosure of names of other producers.

#### **C.3. Examination by the Authority**

9. Rule 2(b) provides as follows:

*"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves*



*importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers”*

10. The present application was filed by M/s JK Paper Ltd., M/s West Coast Paper Mills Ltd., M/s Tamil Nadu Newsprint and Papers Ltd. and BILT Graphic Paper Products Ltd (“BGPPL”) (subsidiary of Ballarpur Industries Limited).
11. The Authority notes that BGPPL was not producing the subject goods for a major part of the POI due to its own internal reasons. Therefore, it would not be appropriate to consider BGPPL as a part of the DI for assessment in the present investigation. Accordingly, the Authority considers M/s JK Paper Ltd., M/s West Coast Paper Mills Ltd. and M/s Tamil Nadu Newsprint and Papers Ltd. as the constituents of DI for the present investigation. None of them have imported the subject goods from the subject countries during the POI and they are also not related to any exporter or importer of the product concerned.
12. The Authority has verified the information submitted by the DI regarding total production in India and total production of the DI. DI accounts for 53% share in total production of the like product. None of the other Domestic Producers in India have opposed the application filed by the DI.
13. Therefore, the Authority holds that the Petitioners command a major proportion of the production of the subject goods in India. For the purpose of this investigation the Petitioners satisfy the standing requirement in terms of Rule 5(3) and constitute the DI in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

#### **D. ISSUES RELATING TO CONFIDENTIALITY**

##### **D.1. Submissions by Domestic Industry**

14. The following submissions have been made by the DI for confidentiality issues:
  - a) Responding exporters/producers have claimed excessive confidentiality by not providing meaningful information in the public version of their questionnaire responses.
  - b) The Petitioners have claimed only such information as confidential, the confidentiality of which has been permitted under the rules and as per consistent practice of the Authority.
  - c) The Petitioners have provided non-confidential version of the application in sufficient detail. None of the interested party has been able to bring any specific instance of information which has been claimed as confidential and confidentiality of which is not justified as per AD Rules.

##### **D.2. Submissions by Other Interested Parties**

15. The following submissions have been made by other interested parties for confidentiality issues:
  - a) Production figures of each of the constituent of the DI has been claimed as confidential.
  - b) Petition has also not provided actual figures for total demand and market share. These figures are aggregate and therefore cannot be considered as confidential. Actual figures for demand and market share are disclosed in all the final findings issued by the Designated Authority.
  - c) Non-confidential summary of costing information should also be disclosed wherever possible. Claim for confidentiality has been granted automatically without a thorough evaluation of the information.

##### **D.3. Examination by the Authority**

16. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:

*Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*

*(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*

*(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.*

17. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties through the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection as per Rule 6(7).
18. Submissions made by the DI and other opposing interested parties with regard to confidentiality to the extent considered relevant were examined by the Authority and addressed accordingly. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

#### **E. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS**

##### **E.1. Submissions by Domestic Industry**

19. The following miscellaneous submissions have been made by the DI:
  - a) US authorities have found that subsidies are maintained in Indonesia. Petitioners requests the Authority to kindly consider these subsidies in the context of determination of cost of production and whether cost claims reasonably reflect cost associated with production and sale of the article under consideration.
  - b) Authority should investigate reasons for exports made by DI at adverse profitability. The DI has exported the product under consideration only because of its inability to sell the goods in the domestic market.

##### **E.2. Submissions by Other Interested Parties**

20. The following miscellaneous submissions have been made by other interested parties:
  - a) DI has stated that IPMA maintains production data of paper producers but DI has not disclosed source of sales data of other producers.
  - b) There is no information at all in the petition regarding cash flow, productivity, wages, profit before interest and tax (PBIT), depreciation cost and interest cost. Productivity, cash flow, wages are mandatory injury parameters specified in para (iv) of Annexure II of the Anti-Dumping Rules.
  - c) Capacity of DI has remained constant throughout the injury investigation period. The reason for such stagnation in capacity despite increase in demand is that there is scarcity of primary raw material wood pulp in India. Gap between demand and supply was created and augmented by ouster of BILT, one of the constituents of DI. This led to increase in imports from subject countries. Gap between demand and supply was not met fully by the other domestic producers because they were already operating at optimum capacity and there was no possibility of further expansion of capacity.
  - d) Imposition of anti-dumping duty will not be in public interest. It will be against the Government of India's initiative to promote education and allow easy access to notebooks and other education materials. This will result in increase in price of paper. This will adversely affect Government of India's "Sarva shiksha abhiyaan" (Education for all initiative), which seeks to ensure easy

availability of educational materials, books etc. Imposition of anti-dumping on subject product will affect livelihood of small scale photocopiers who are dependent on affordable prices of copier paper.

- e) User industry will face inverted duty structure if anti-dumping duty is imposed. Downstream products such as books, brochure do not attract import duty.
- f) Product under consideration constitutes 60% of the cost for the downstream product. As a result, anti-dumping duty will have a direct trickledown effect, not just on the margins of the users but also the prices for the final consumer.

### **E.3. Examination by the Authority**

- 21. Various submissions made by the interested parties with regard to miscellaneous issues and considered relevant by the Authority are examined and addressed as follows:
  - a) As regards the issue of subsidies provided by the Government of Indonesia, it is noted that the present investigation is an anti-dumping investigation and therefore, investigation is not conducted regarding subsidies provided by Government of Indonesia.
  - b) As regards the argument that Authority should investigate reasons for loss making exports, it is noted that the Authority need not investigate the issue as it cannot speculate regarding business decision taken by the DI. It is also noted that reasons for making exports at losses is not a relevant parameter for assessment of injury or causal link suffered by the DI.

### **F. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE & DUMPING MARGIN**

- 22. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:
  - (i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
  - (ii) *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either*
    - (a) *Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
    - (b) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);*

*Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.*

### **F.1. Submissions by Domestic Industry**

- 23. The following submissions have been made by the DI:
  - a) Petitioners have determined normal value in the subject countries on the basis of best estimates of cost of production in the subject countries. Consumption norms and raw material prices, conversion cost and SGA have been determined in the petition on the basis of best information available.
  - b) Questionnaire response filed by producers/exporters are grossly deficient and they have misrepresented various facts and have claimed excessive confidentiality.
  - c) The producers in Indonesia are receiving various subsidies from Govt. of Indonesia. The Authority should duly consider such subsidies and revise the cost of production of the Indonesian producers upwards while determining the normal value.

- d) Petitioners have relied upon import data provided by DGCIS for determining export price. Petitioners have adjusted export price for ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses and bank charges to arrive at ex-factory export price.

## **F.2. Submissions by Other Interested Parties**

- 24. The following submissions have been made by other interested parties:
  - a) Determination of normal value and dumping margin should be based on the information provided by the exporters/producers from subject countries.
  - b) Petitioners have constructed the normal value of Indonesian producers by estimating the production cost, consumption norms and raw material prices of DI due to its inability to obtain information or evidence of price in the subject countries.
  - c) Assumptions made by the Petitioners regarding normal value are not acceptable as such assumption would not be representative due to factual conditions in Indonesia. Companies in Indonesia's are public companies and their financials are available publicly.

## **F.3. Examination by the Authority**

- 25. Under section 9A (1) (c) normal value in relation to an article means:
  - a) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or
  - b) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:
    - (i) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
    - (ii) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);*
  - c) The Authority sent questionnaires to the known exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed. However, barring the following producers and exporters, none of the other producers/ exporters from subject countries co-operated in this investigation by filing the prescribed questionnaire responses:
    - (i) PT Riau Andalan Kertas, Indonesia
    - (ii) PT Anugrah Kertas Utama, Indonesia
    - (iii) PT Asia Pacific Rayon (Formerly known as Sateri Viscose International) Indonesia
    - (iv) April Fine Paper Trading Pte Ltd, Singapore
    - (v) April International Enterprise Pte Ltd, Singapore
    - (vi) April Fine Paper Macao Commercial Offshore Limited, Macau
    - (vii) PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Indonesia
    - (viii) PT Pindo Delhi Pulp and Paper Mills, Indonesia and
    - (ix) PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, Indonesia
    - (x) Double A Double A (1991) Public Co Ltd
    - (xi) Advance Paper Mill 3 Co Ltd.
    - (xii) Phoenix Pulp & Paper Public Co. Ltd

#### **F.4. Determination of Dumping Margin for Producers and Exporters in Indonesia, Singapore and Thailand**

##### **General Methodology for Working-out Normal Value**

26. It was first determined by the Authority whether the total domestic sales of the subject goods by the producers/exporters in these subject countries were representative when compared to exports of the subject goods to India.
27. Thereafter, it was examined whether their sales are under ordinary course of trade in terms of Para 2 of the Annexure I to the Anti-dumping Rules. Wherever the producers/exporters have provided required transaction wise details of sales made in home market and same has been accepted by the Authority, the said information has been relied upon to determine the normal value of the subject goods sold in their home market.
28. For conducting ordinary course of trade test, the cost of production of the product concerned was examined with reference to the information provided by the producers/exporters and compared with domestic selling price to determine whether the domestic sales were in the ordinary course of trade or not. The Authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of normal value for the cooperating producers/exporters where profit making transactions are more than 80% and in cases, where profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales have been taken into consideration for the determination of the normal value.
29. Wherever there were no domestic sales or no profitable domestic sales of subject goods, then normal value was constructed based on the cost of production along with reasonable addition for administrative, selling & general costs and for profits.
30. Since the above-mentioned producers/exporters have filed the questionnaire response, the Authority proposes to determine individual dumping margin in respect of these companies where the responses are accepted. In the case of non-cooperating exporters in the subject countries, the Authority proposes to determine the normal value on the basis of facts available in terms of Rule 6 (8) of AD Rules read with Article 6.8 of the Agreement.

#### **Indonesia**

##### **Normal Value for PT Riau Andalan Kertas, PT Anugrah Kertas Utama and PT Asia Pacific Rayon, Indonesia, ("Producers") ("APRIL Group")**

31. From the response filed by producers in APRIL Group i.e. PT Riau Andalan Kertas ("RAK"), PT Anugrah Kertas Utama ("AKU") and PT Asia Pacific Rayon ("APR"), Authority notes that all companies have made sales of product under consideration in domestic market during the POI. However, product under consideration manufactured by only RAK & AKU has been exported to India during the POI. APR started its commercial production after POI. The product under consideration sold by APR in the domestic market during POI was out of the trial production. Since, APR started commercial production after POI, Authority has not considered the domestic sales of APR for the purpose of Normal Value determination.
32. It is noted that RAK has sold \*\*\* MT having value of USD \*\*\* and AKU has sold \*\*\* MT having value of USD \*\*\* in the domestic market. The Authority examined the domestic sales made by RAK & AKU and noted that the sales in the domestic market are representative when compared to exports of the product under consideration to India.
33. The Authority has, therefore, decided to determine the normal value based on domestic sales of RAK & AKU. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of product under consideration. If profit making transactions are more than 80% then the Authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value and in case, profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value.
34. In this case, based on the ordinary course of trade test, all domestic sales have been taken for determination of normal value, since the profitable sales were more than 80%. RAK & AKU have claimed adjustments for inland transportation, handling and other expenses, ocean freight (one island to

another), insurance, credit cost, advertisement, FOC Paper/Rebate/Discount and Jakarta Office expenses and the same have been allowed by the Authority. However, the adjustment for advertisement expenses and Jakarta Office expenses being not directly related to domestic sales, are not accepted by the Authority. Accordingly, normal value at ex-factory level for the participating producers has been determined as USD \*\*\*per MT for RAK & USD \*\*\*Per MT for AKU. The weighted average normal value is USD \*\*\*per MT for APRIL Group.

**Export price for PT Riau Andalan Kertas, PT Anugrah Kertas Utama and PT Asia Pacific Rayon, Indonesia, (“Producers”) and their related exporters April Fine Paper Trading Pte Ltd, Singapore, April International Enterprise Pte Ltd, Singapore, April Fine Paper Macao Commercial Offshore Limited, Macau (“Exporters”)**

35. From the response filed by producers and exporters in APRIL Group, Authority notes that April Fine Paper Trading Pte Ltd (AFPT) & April International Enterprise Pte Ltd (AIE) have exported the product under consideration manufactured by PT Riau Andalan Kertas (RAK) to India during POI. April Fine Paper Macao Commercial Offshore Limited, Macau (AFPM) has exported the product under consideration manufactured by PT Anugrah Kertas Utama (AKU) to India during POI. All exports to India have been made to unrelated customers.
36. It was noted that RAK & AKU are exporting the product under consideration and all other products manufactured by them through the above-mentioned exporters. It was also noted that in some cases, product under consideration is exported to Singapore on barges and then it is unloaded & loaded in Singapore for exports to India and other countries.
37. Accordingly, the Authority has worked out the ex-factory export price taking price to unrelated Indian customers and made adjustment on account of inland freight, port handling charges in Indonesia, credit cost, rebate, ocean freight, barging cost, handling expenses in Singapore, SGA expenses & profit of related exporters, bank charges, & G&A expenses of Indian office. The export price has been determined as USD \*\*\*per MT for RAK and USD \*\*\* per MT for AKU. The weighted average Ex-factory export for APRIL Group is determined at USD \*\*\* per MT

**Normal value for M/s PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Indonesia, PT Pindo Delhi Pulp and Paper Mills, Indonesia and PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, Indonesia (“Producers”) (“APP Group”)**

38. From the response filed by producers in APP Group, i.e., M/s PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT Pindo Delhi Pulp and Paper Mills and PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, Indonesia, Authority notes that all companies have made sales of product under consideration in domestic market during the POI.
39. However, due to the reasons mentioned in the export price determination related paragraph below, the Authority has decided not to accept the response filed by APP Group and determine the normal value on the basis of facts available.

**Export price for M/s PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Indonesia, PT Pindo Delhi Pulp and Paper Mills, Indonesia and PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, Indonesia (“APP Group”)**

40. From the response filed by producers/exporters in APP Group i.e. M/s PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk(IK) PT Pindo Delhi Pulp and Paper Mills (PD) and PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk(TK) Indonesia, Authority notes that all companies have exported the product under consideration to India directly as well through unrelated exporters during the POI. IK has exported \*\*\* MT having value of USD \*\*\* either directly or through unrelated exporters in China, Hong Kong and Singapore. Similarly, PD had exported \*\*\* MT having value USD \*\*\* and TK has exported \*\*\* MT having value USD \*\*\* respectively. As informed by the producer, the exporters in China and Hong Kong have sold the goods to M/s Leaconfield, Singapore, which is an unrelated exporter. The exports to India through these exporters is approximately 39% for IK, 43% for PD and 32% for TK. None of these unrelated exporters have filed the exporter questionnaire response and have not cooperated with the Authority. Considering that the exports through these unrelated exporters is quite substantial, the Authority has decided to reject the response filed by APP Group and instead determine the export price on the basis of facts available.

**Export price and Normal Value for Non-Cooperating Producers and Exporters from Indonesia**

41. The Authority notes that since no other producers/exporters from Indonesia have responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative producers/ exporters in Indonesia, the Authority has determined the net export price as \*\*\* US\$/MT while the corresponding normal value has been determined to be \*\*\* US\$/MT.

**Thailand****Normal value for Double A**

42. From the response filed by producers in Double A Group i.e. Double A (1991) Public Company Limited ('Double A') and Advance Paper Mill 3 Co.('APM3') Thailand, Authority notes that APM3 is the manufacturer of PUC only and sold all of its products to Double A for sales in domestic market and exports market in the name of Double A. The cost of production of the producer APM3 has been considered for calculating weighted average cost of Double A Group for the purpose of "ordinary course of trade (OCT)" test. It is observed that M/s. Double A has sold \*\*\*MT in domestic market during the POI having value of THB \*\*\*. However, it is further noted that Double A has sold \*\*\* MT (around 11%) having value of THB \*\*\*through its related traders and \*\*\*MT having value of THB \*\*\*to unrelated customers. However, the resale prices to first independent customer for these related party sales is not provided by the exporter. Therefore, in the absence of above information the Authority is unable to determine the normal value for the Group.
43. Accordingly, the Authority has decided not to accept the response filed by Double A Group and has determined the normal value on the basis of facts available.

**Export price for Double A Group**

44. Due to the aforesaid reasons, the Authority has determined the export price for Double A Group on the basis of facts available.

**Normal Value for Phoenix Pulp and Paper Public Co., Ltd, Thailand**

45. From the response filed by producer M/s. Phoenix Pulp and Paper Public Co. Ltd ("PPPPC") Thailand, Authority notes that PPPPC is the manufacturer of PUC only and all the sales were made to its related company Thai Paper Co., Ltd (TPC). TPC sells the PUC in domestic and exports market. It is also noted that response filed by PPPPC is incomplete and Appendix-4, 5, 6, 7 & 9 is not submitted. Further, no response has been filed by TPC. Further, some supporting documents requested by the Authority for the verification have been claimed to have been sent to the Authority, but they never reached. Accordingly, the Authority has decided not to accept the response filed by PPPPC and has determined the normal value on the basis of facts available.

**Export price for Phoenix Pulp and Paper Public Co., Ltd, Thailand**

46. Due to the aforesaid reasons, the Authority has determined the export price for PPPPC on the basis of facts available.

**Export price and Normal Value for Non-Cooperating Producers and Exporters from Thailand**

47. The Authority notes that since no other producers/ exporters from Thailand have responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative producers/exporters in Thailand, the Authority has determined that the normal value as \*\*\* US\$/MT and the corresponding the net export price as \*\*\* US\$/MT.

**Singapore**

48. From the information available on record, the Authority notes that there is no producer of product under consideration in Singapore. The product under consideration manufactured in Indonesia is sometimes unloaded in Singapore and then exported to India from Singapore. The exporters in Singapore have responded in this investigation and a separate dumping margin has already been determined for these exporters from Singapore along with the producers from Indonesia. Therefore, the Authority is not determining any separate dumping margin for the exporters from Singapore.

**F.5. Dumping Margin Table**

49. The dumping margin during the POI for all exporters/producers from the respective subject countries have been determined as provided in the table below:

S. No.	Producer Country	Producer	Normal Value US\$/MT	Export Price US\$/MT	Dumping Margin US\$/MT	Dumping Margin %	Dumping Margin Range %
1.	Indonesia	4. PT Riau Andalan Kertas, 5. PT Anugrah Kertas Utama 6. PT Asia Pacific Rayon	***	***	***	***	25-35
2.	Indonesia	All Others	***	***	***	***	50-60
3.	Thailand	All Exporters	***	***	***	***	0-10

**G. INJURY ASSESSMENT AND CAUSAL LINK****G.1. Submission by Domestic Industry**

50. The submissions made by DI are as follows:

- i. BILT/ BGPPL is suffering injury on account of other facts but dumped imports have intensified the injury to the company and also threatens further injury.
- ii. Performance of the DI even without BILT/ BGPPL shows that the DI has suffered injury as could be seen from the injury information of the DI excluding BILT/ BGPPL. The Designated Authority can examine performance of the DI after excluding BILT/ BGPPL to establish whether the performance of DI shows deterioration even without BILT/ BGPPL.
- iii. Cumulative assessment of the effect of dumped imports is appropriate as exporters from more than one country are dumping the subject product in accordance with Annexure II (iii) of the Anti-Dumping Rules.
- iv. Demand for the subject goods has increased over the injury period. Imports from subject countries have increased in absolute terms and in relative terms and significantly high during the POI.
- v. Market vacated by BILT/ BGPPL has been taken up by imports. Imports increased by 748 basis points in the POI as compared to previous year whereas other sales of domestic producers increased by only 14 basis points during the corresponding period.
- vi. Import price from subject countries declined sharply in the POI without corresponding decline in costs. Demand-supply gap should have been filled by imports at fair prices. Imports are likely to have suppressing and depressing effect on sales price of DI in near future.
- vii. Imports are undercutting prices of DI. Landed price of imports from the subject countries have been below net sales realisation of the DI throughout the injury period, except in 2014-15. Landed price of imports is also below cost of sales of the DI.
- viii. DI is forced to export at financial losses in spite of adequate demand in the domestic market.
- ix. Capacity, production, market share and sales of the DI increased till the year 2015-16 and then declined in the POI. Capacity utilization of the DI has decreased from the base year in 2014-15, then increased in 2015-16 and then once again declined in POI.



- x. Market share of imports from the subject countries which was merely 1.19% in the base year increased to 10.53% in the POI.
- xi. DI was suffering financial losses in the base year and 2014-15. DI started earning profits since 2015-16. Cash flow has followed the same trend. Increase in profits earned by the DI is because of reduction in raw material cost and efforts put in by the DI to invest in Agro farming. Profits made by the DI are still very nominal. ROI is much below average bank rates in the country. Level of profits earned by foreign producers, which is significantly higher could be considered as a benchmark.
- xii. Inventories with the DI has increased significantly in the POI. Ability to raise capital has weakened due to absence of reasonable profit. Number of employers have declined marginally and wages paid have increased.
- xiii. Only factors responsible for DI prices are import prices and cost of production of the DI. Dumping margin from the subject countries is substantial.
- xiv. There is threat of injury to the DI. Imports have increased by almost 370% in the POI as compared to 2015-16. Major producers of subject goods in subject countries have significantly high production capacity. US has imposed countervailing duty on imports from China PR, which suggest increase in imports into India in near future. Producers from exporting country are finding the Indian market quite attractive in terms of prices.
- xv. Free Trade Agreement signed with ASEAN countries has resulted in increase in imports. It is also reasonable to assume that producers in the subject countries have significant capacity available with them. Producers in the subject countries are export oriented. “*Global Outlook for Cut-Size Uncoated Freesheet Paper Markets 2015*” study shows high export orientation of Indonesian producers. Producers from Thailand also have severe export orientation as almost one-third of the total uncoated wood-free production is meant for exports. There is significant surplus across the globe forcing these countries to export at low prices.
- xvi. Causal link between imports and injury to the DI is clearly established. There are no other factors such as material change in the pattern of consumption of the product under consideration, trade restrictive practice, performance of other domestic producers etc. Increase in imports at lower prices, which are below cost of sales of the DI establish causal link between imports and injury.
- xvii. The increase in profit is a result of the massive efforts undertaken by the DI to bring down its cost by investing in agricultural infrastructure.
- xviii. Responding exporters constitute 45% of the Asian demand and are capable of deciding the price of the subject goods.

## **G.2. Submission by Other Interested Parties**

51. The submissions made by other interested parties are as follows:

- i. The subject goods imported from Thailand do not compete with the subject goods imported from the other subject countries on account of better quality product sold by producers in Thailand.
- ii. Increase in imports from subject countries is required to be analysed in the appropriate context. Increase in volume of imports *per se* does not imply or support the determination of material injury.
- iii. Any claim regarding imports is required to be supported by corresponding transaction by transaction import data. Transaction by transaction data provided by the DI is not reliable as it also includes non-PUC.
- iv. Price undercutting calculation provided in Proforma IV-B of the updated petition is inaccurate. Landed value for imports from subject countries is lower than the assessable price. In no case, landed value can be lower than the assessable value.
- v. Price undercutting computed after doing the right calculation would either be negative or miniscule.

- vi. Claim concerning price under-cutting is irrelevant as imports occupied only 8% of total demand in the POI and cannot exert any price pressure on the like domestic product of the domestic producers holding 92% of the total demand.
- vii. DI has admitted in the petition that imports are not suppressing or depressing the prices of the DI. DI has been able to increase its selling price from 100 in the year 2013-14 to 103 in the POI even though the cost of sales has marginally reduced from 100 to 99 during the same period. This clearly shows that there is no price depression or suppression of any kind.
- viii. Imports are made at distributor level whereas domestic sales are made at dealer level. Therefore, determination of price undercutting is made at different levels of trade.
- ix. Provisions relating to assessment of injury specifically requires that the sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity should show "a decline".
- x. There is no injury to the DI based on assessment of relevant economic parameters. There is no decline in market share, sales, production and capacity utilization of the DI after excluding BILT's/BGPPL's performance. There is overall increase in profit and capacity during the injury investigation period.
- xi. Cash flow, growth and ability to raise capital investment has also shown improvement. Figures relating to employment and wages also do not show any adverse impact of dumping.
- xii. Performance of all the other constituents of DI have improved except BILT/ BGPPL. Sales revenue, Profit before tax, sales quantity of JK Paper Limited, The West Coast Paper Mills Ltd., Tamil Nadu Newsprint and Papers Limited Ltd have increased during the injury investigation period. Sales revenue and profit of other paper producers such as Orient Paper & Industries Limited, Century textiles & Industries Limited, Satia Industries Ltd., Kuantum Papers Ltd., Ruchira Papers Ltd. have also increased during the injury investigation period.
- xiii. Anti-dumping duty is not an instrument to increase the profits, ROI etc. to the "desired level" of the domestic producers.
- xiv. There is no causal link between imports and injury caused to the DI. Decline in production, market share, capacity utilisation, sales in the POI is entirely due to decline in production by BILT/ BGPPL. There would have been no decline in these economic parameters, if BILT/ BGPPL would not have curtailed production. Performance of these parameters actually shows increase after excluding BILT/ BGPPL. Increase in the production of the other producers coincides with the decline in DI production. If imports were causing injury to the DI, then the effect of such injurious import would also have been visible in the performance of other Indian producers.
- xv. BILT/ BGPPL's decline in performance is clearly attributable to financial constraints, raw material constraints, & losses suffered by its overseas entity SFI, Malaysia. Annual report of BILT/ BGPPL clearly acknowledges these other causes of injury.
- xvi. Raw material contributed between 40-50% of the cost. High prices of raw material and fierce competition between Indian producers has affected the Petitioners.
- xvii. Injury margin is not relevant for determining whether the Petitioners are injured or not. The injury margin is only relevant to determine the quantum of duty which would be sufficient to remove injury.
- xviii. There is no correlation between the increase in imports and the performance of the DI. The profits of the DI improved when there was an increase in imports. At the same time, the DI was in deep losses when the imports were almost negligible. There is also no co-relation between import price and selling price of the DI. DI has shown a completely opposite trend than the landed price of imports, which clearly means that there is absence of causal link.
- xix. There is no threat of injury to the DI. For assessment of threat of injury, Paragraph 3 (vii) of Annexure II to the AD Rules, provides for evidence regarding freely disposable capacity or

increase in capacity and that such capacity is “imminent” and “substantial”. However, no such claim has been made by the DI.

- xx. Petitioners have assumed the existence of accumulated inventories in the subject countries. Authority can verify that there is no increase in inventories by the exporters.
- xxi. Latest financial report of domestic producers for the financial year 2017-18 shows further increase in profit. This shows that there is absence of threat of injury to the DI.
- xxii. Production to sales ratio of DI has remained nearly 100%. DI is able to sale its entire production. Thus, if DI could produce more, it could also sell more.
- xxiii. There has been a decline in the imports from subject countries during the period January-June 2018.
- xxiv. The production of TNPPL has suffered during the POI due to water shortage in the Tamil Nadu region.

### **G.3. Examination by the Authority**

52. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties and has examined the various parameters in accordance with the Anti-Dumping Rules after duly considering the submissions made by the interested parties.

### **Cumulative Assessment**

53. Para (iii) of Annexure II of the Anti-Dumping Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigation, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
- a) the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article; and
  - b) Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in the light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
54. The Authority notes that:
- a) The subject goods are being dumped into India from subject countries. The margins of dumping from each of the subject countries are more than the *de minimus* limits prescribed under the Rules.
  - b) The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of total volume of imports.
  - c) Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete inter se but also with the like articles offered by the DI in the Indian market.
55. In view of the above, the Authority considers that it would be appropriate to assess injury to the DI cumulatively from exports of the subject goods from the subject countries.
56. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the DI, “.... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....*”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the DI in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales

realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.

57. The submissions made by the DI and other interested parties during the course of investigations with regard to injury and causal link and considered relevant by the Authority are examined and addressed as below.
58. The Authority notes that BGPPL was not producing the subject goods for a major part of the POI due to its own intrinsic reasons. Therefore, it would not be appropriate to consider BGPPL as a part of the DI for injury assessment in the present investigation. Accordingly, the Authority considers M/s JK Paper Ltd., M/s West Coast Paper Mills Ltd. and M/s Tamil Nadu Newsprint and Papers Ltd. as the constituents of DI for the injury assessment in the present investigation.

#### **G.4. Volume Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry**

##### **(a) Assessment of Demand/Apparent Consumption**

59. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian Producers and imports from all sources. The demand so assessed shows that it has increased during the injury investigation period. Demand slightly declined in the year 2014-15 as compared to the base year but increased in 2015-16 and the POI (A).

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI(A)
DI sales	MT	2,57,973	2,83,712	3,06,872	3,00,878
Other producers' sales including BILT/ BGPPL	MT	3,93,294	3,55,264	3,62,171	3,24,977
<b>Subject imports</b>	MT	7,785	15,604	15,692	73,897
Other imports	MT	1,288	109	757	1438
<b>Demand/consumption</b>	MT	6,60,341	6,54,690	6,85,491	7,01,191

##### **(b) Import Volumes from Subject Countries**

60. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports from subject countries, either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI (A)
Indonesia	MT	7,470	12,288	13,091	48,522
Singapore	MT	298	2,997	2,369	4,259
Thailand	MT	17	320	232	21,116
<b>Subject countries</b>	MT	7,785	15,604	15,692	73,897
Other Countries	MT	1,288	109	757	1438
<b>Total Imports</b>	MT	9,073	15,713	16,449	75,335

61. It is seen that dumped imports of the subject goods from the subject countries have increased significantly in absolute terms during the POI (A). However, interested parties have submitted that increase in imports during the POI (A) was on account of gap created by BGPPL's decline in production. The Authority agrees with this contention of the interested parties that increase in imports during POI (A) was necessitated due to decline in BGPPL's production. However, the Authority observes that there is consistent increase in volume of imports during the POI.

**(c) Subject Country Imports in Relative Terms**

Particular	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI (A)
Subject Country Import in relation to Production	%	1.14%	2.26%	2.14%	10.80%
Subject Country Import in relation to Demand	%	1.18%	2.38%	2.29%	10.54%

62. It is seen that the subject imports in relation to production and demand increased in the POI as compared to the base year and previous year. There was a slight decline in imports in relation to production and demand in the year 2015-16 as compared to previous year.

**(d) Market Share in Demand**

63. Considering imports from various sources and sales of the DI, market share of subject imports in demand in India was examined. The Authority notes that the market share of the subject imports increased significantly in the POI. Market share of the DI has declined during the POI. The market share of other Indian producers has fallen significantly during the POI (A). This is mainly due to fall in production/ sales of BGPPL. The fall in the market share of other Indian producers has been taken over by the imports from subject countries.

Particular	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI (A)
Domestic Industry	%	39%	43%	45%	43%
Other Indian Producers	%	60%	54%	53%	46%
Total Market Share of all Domestic Producers	%	99%	98%	98%	89%
Subject Imports	%	1.18%	2.38%	2.29%	10.54%
Other Imports	%	0.20%	0.02%	0.11%	0.21%
Total	%	100 %	100 %	100 %	100 %

**G.5. Price Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry**

64. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the DI on account of the dumped imports from subject countries has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the DI have been compared with weighted average landed price of imports of the subject goods from the subject countries.

**a) Price Undercutting**

65. For the purpose of price undercutting analysis, the net selling price of the DI has been compared with the landed value of imports from the subject countries. While computing the net selling price of the DI all taxes, rebates, discounts and commissions have been deducted and sales realization at ex works level is determined for comparison with the landed value of the dumped imports. Accordingly, the undercutting effects of the dumped imports from the subject countries work out as follows:

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI-A
<b>Indonesia</b>					
Landed Price of Imports	Rs/MT	50,807	52,185	48,816	49,178
Net Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
Range		0-10%	0-10%	10-20%	10-20%
<b>Thailand</b>					
Landed Price of Imports	Rs/MT	55,131	61,389	55,919	55,659
Net Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
Range		(10)-0%	(15)-(5)%	(10)-0%	0-10%
<b>Singapore</b>					
Landed Price of Imports	Rs/MT	57,700	46,372	53,947	40,217
Net Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
Range		(10)-0%	10-20%	(10)-0%	30-40%
<b>Subject Countries</b>					
Landed Price of Imports	Rs/MT	50,988	53,834	49,964	46,991
Net Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
Range		0-10%	0-10%	10-20%	10-20%

66. From the aforesaid tables, it can be seen that the price undercutting from the subject countries during the injury period as well as in POI is positive.

**b) Price Suppression and Depression**

67. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, were compared as below:

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI (A)
Cost of Production	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	102	94	94
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***

<i>Trend</i>		<i>100</i>	<i>99</i>	<i>99</i>	<i>102</i>
Landed Value	Rs./MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>		<i>100</i>	<i>106</i>	<i>98</i>	<i>92</i>

68. From the above table, it can be seen that the dumped imports are neither depressing the prices of the DI nor causing any suppression effect on the prices of the DI. The DI has been able to increase its selling price much more than the increase in the cost of the DI during the POI.

**c) Price Underselling**

69. The non-injurious price (NIP) of the DI has been determined and compared with the landed value of the subject goods to arrive at the extent of price underselling. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation on the basis of principles mentioned in Annexure III of the Rules. The NIP has been determined considering optimum level of capacity utilisation that the Petitioners can achieve in the plant. The analysis shows that during the period of investigation, the landed value of subject imports was below the non-injurious price of the DI, as can be seen from the table below, demonstrating positive price underselling effect:

Particulars	Unit	POI (A) *(INR)	POI (A) * (USD)
<b><u>Indonesia</u></b>			
Landed Price	Per MT	49,178	729.10
Non-Injurious Price (Nip)	Per MT	***	***
Price Underselling	Per MT	***	***
Price Underselling	%	***	***
Price Underselling	% Range	Positive	Positive
<b><u>Thailand</u></b>			
Landed Price	Per MT	55,659	825.18
Non-Injurious Price (Nip)	Per MT	***	***
Price Underselling	Per MT	***	***
Price Underselling	%	***	***
Price Underselling	% Range	Positive	Positive
<b><u>Singapore</u></b>			
Landed Price	Per MT	40,217	596.25
Non-Injurious Price (Nip)	Per MT	***	***
Price Underselling	Per MT	***	***
Price Underselling	%	***	***
Price Underselling	% Range	Positive	Positive

**G.6. Economic Parameters of the Domestic Industry**

70. Annexure II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such

products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Anti-dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

71. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions.

**(a) Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales**

72. Capacity, production, capacity utilization and sales of the DI over the injury period is given in the following table: —

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI-A
Capacity Total	MT	10,87,251	11,56,000	11,56,000	11,56,000
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>106</i>	<i>106</i>	<i>106</i>
Production- Total	MT	10,08,784	10,69,446	11,36,727	11,20,495
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>106</i>	<i>113</i>	<i>111</i>
Production-PUC	MT	2,91,309	3,34,384	3,70,343	3,59,376
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>115</i>	<i>127</i>	<i>123</i>
Capacity Utilization	%	93%	93%	98%	97%
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>106</i>	<i>104</i>
Sales Domestic	MT	2,57,973	2,83,712	3,06,872	3,00,878
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>110</i>	<i>119</i>	<i>117</i>

73. From the above table, it is noted that:

- Capacity of the DI has remained constant since 2014-15.
- Capacity utilisation of DI has improved throughout the injury investigation period and was at 97% during the POI (A).
- Production & domestic sales of the DI have improved till 2015-16 and have marginally declined during the POI (A).

**(b) Profitability, Return on Investment and Cash Profits**

74. Profitability, return on investment and cash profits of the DI over the injury period is given in the table below: —

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI-A
Profit/ Loss	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>44</i>	<i>204</i>	<i>266</i>
Profit/ Loss	Rs.Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>48</i>	<i>242</i>	<i>311</i>
Profit before Interest	Rs.Lacs	***	***	***	***



<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>104</i>	<i>174</i>	<i>192</i>
Cash Profit	Rs.Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>72</i>	<i>141</i>	<i>161</i>
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>117</i>	<i>152</i>	<i>177</i>

75. From the above table, it is noted that:

- Profitability of DI declined in 2014-15 but has improved significantly during the POI (A) as compared to the base year.
- Similarly, PBIT, cash profits and ROCE is in similar line as profit.

**(c) Employment, productivity and wages**

76. Employment, productivity and wages over the injury period is given in the table below.

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI-A
Employment	Nos	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>99</i>	<i>100</i>	<i>96</i>
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>98</i>	<i>108</i>	<i>121</i>
Productivity per Employee	MT/Nos	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>116</i>	<i>128</i>	<i>128</i>
Productivity per Day	Mt/Day	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>115</i>	<i>127</i>	<i>123</i>

77. It is noted that the Productivity per day and productivity per employee has improved during the POI.

**(d) Inventories**

78. Inventory position with the DI over the injury period is given in the table below:

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI-A
Average Stock	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>177</i>	<i>175</i>	<i>238</i>

79. It is noted that the inventories with the DI has increased.

**(e) Growth**

80. Growth of the DI with regard to profits, return on investments, production, capacity utilisation and cash flow has been negative.

Growth (year on year)	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI-A
Production	%	-	14.79	10.75	(2.96)
Domestic Sales	%	-	9.98	8.16	(1.95)

Cost of Sales	%	-	1.76	(8.03)	0.44
Selling Price	%	-	(0.87)	(0.55)	3.28
Profit/ Loss per Unit	%	-	(56.17)	365.10	30.71
Return on Investment	%	-	16.75	30.55	16.30

**(f) Ability to Raise Capital Investments**

81. DI claimed that the current state of its financial position does not allow them to raise capital for fresh investment. However, the Authority finds that in view of improved financial position of the DI during POI, their financial strength has also improved.

**(g) Factors affecting domestic prices**

82. The DI is able to maintain its selling price in a range. However, the cost of production of DI has declined during the injury period. Therefore, there is no impact on sales prices of DI.

**H. THREAT OF MATERIAL INJURY**

**H.1. Submissions by Domestic Industry**

83. There is threat of material injury to the DI due to significant increase in imports from the subject countries. The producers in subject countries have huge surplus capacities. The price undercutting from subject countries is significant and the Indian market is attractive which is likely to further increase in imports and cause suppressing or depressing effects.

**H.2. Submissions of Other Interested Parties**

84. There is no threat of material injury as the imports have increased due to non-supply of goods by one of the major domestic producers in India. Further, there is no evidence that the producers in subject countries have huge surplus capacities.
85. The performance of domestic producers' other than BILT has shown major improvement.
86. The post POI information reveals that the performance of the DI has further improved.

**H.3. Examination by the Authority**

87. The provisions relating to threat of material injury are as under:

(vi) *A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances which would create a situation in which the dumping would cause injury must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the designated Authority shall consider, inter alia, such factors as:*

- (a) *a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;*
- (b) *sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;*
- (c) *whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and*
- (d) *inventories of the article being investigated.*

88. A threat of material injury is a situation where the DI has not suffered over the injury period but injury to the DI is imminent if the present circumstances continue. A 'threat of material injury' means clear

and imminent danger of injury. The determination of threat of material injury should be based on facts, and not merely on allegation, conjectures, imagination, or remote possibilities.

89. With respect to threat of material injury, the Authority notes as under:

- a) There is substantial increase in imports of subject goods from subject countries in absolute terms as well as in relation to production & consumption in India. However, the increase in imports from subject countries was necessitated due to decline in production of one of the major producer in India.
- b) No evidence has been provided by the DI with regard to sufficiently freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporting producers.
- c) Further, Authority has examined the capacity of the participating producers and it is noted that no substantial capacity has been added by any of the producers and none of them have significant surplus capacity.
- d) The imports have not caused any price depression or suppression for the DI during the POI.

#### **H.4. Magnitude of Injury and Injury Margin**

90. The Authority has determined Non-Injurious Price for the DI on the basis of principles laid down in anti-dumping Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The NIP of the DI has been worked out and it has been considered for comparing the landed price from each of the subject countries for calculating injury margin. For determining NIP, the best utilisation of the raw materials by the DI over the injury period has been considered. The same treatment has been done with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. The production in POI has been calculated considering the best capacity utilisation and the same production has been considered for arriving per unit fixed cost. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. Average Net Fixed Assets plus Average Working Capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure-III and being followed. The non-injurious price so determined has been compared with the landed prices of imports from the subject countries to determine the injury margin as follows;

S. No	Producer Country	Producer	Landed Value (USD/MT)	NIP (USD/MT)	Injury Margin (USD/MT)	Injury Margin %	Range
1.	Indonesia	1. PT Riau Andalan Kertas, 2. PT Anugrah Kertas Utama 3. PT Asia Pacific Rayon	***	***	***	***	10-20
2.	Indonesia	All Others	***	***	***	***	20-30
3.	Thailand	All Exporters	***	***	***	***	0-10

#### **I. CAUSAL LINK**

##### **I.1. Submissions by Producers/ Exporters/ Other Interested Parties**

91. Submissions made by the producers/exporters/other interested parties in this regard are as follows:

- a) There is no causal link between the injury and the alleged import. The DI is suffering injury due to

other factors. None of the economic indicators shows sign of any injury leave aside any material injury both on the price front and volume front. The economic indicators suggest no correlation between imports of subject goods and performance of DI in respect subject goods as the prices have moved independently without any drop in sales volume.

- b) Mere increase in the volume of imports and existence of price undercutting is therefore not sufficient. It is necessary to demonstrate that the imports have a negative impact on the DI.
- c) The DI is a thriving industry, not in a situation of fragility or vulnerability and does not suffer any injury.
- d) The economic factors demonstrate that it is experiencing positive developments and is in a situation of strength.

### **1.2. Submissions by Domestic Industry**

92. Submissions made DI in this regard are as follows:

- a) Imports from countries other than the subject counties are either negligible or the import prices are higher, and are hence not causing injury to the DI.
- b) The performance of the DI and injury thereto has been examined with respect to the domestic sales operations to the extent possible. Possible deterioration in the export performance of the DI is, therefore, not a possible cause of injury to the DI.
- c) The technology and production process for producing product under consideration has not undergone any significant development. Possible development in technology is not a cause of injury to the DI.
- d) Performance of other products being produced and sold by the Petitioners is not a possible cause of injury to the DI. In any event, the Petitioners considers that information relating to the product under consideration is the only relevant information for the present purpose and the Petitioners has provided this information as the DI.
- e) There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the DI.
- f) There has been no material change in the pattern of consumption of the product under consideration.

### **1.3. Examination by the Authority**

93. As per the AD Rules, the Authority, *inter alia*, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the DI, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, *inter alia*, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the DI. It was examined whether these listed known other factors other than parameters listed under the AD Rules could have contributed to injury to the DI.

#### **a) Volume and Price of Imports from Third Countries**

94. The Authority notes that there was low volume of imports of the product under consideration from non-subject countries is negligible.

#### **b) Export Performance**

95. The Authority has considered the data for domestic operations for its injury analysis.

#### **c) Development of Technology**

96. None of the interested party has raised any issue with regard to developments in technology as being the cause of injury to the DI.

#### **d) Performance of Other Products of the Company**

97. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the Petitioners does not appear to be a possible cause of injury to the DI.

**e) Trade Restrictive Practices and Competition Between the Foreign and Domestic Producers**

98. The import of the subject goods is not restricted in any manner and the same are freely importable in the country. The domestic producers compete with the landed prices of the subject goods. The price of the DI is influenced substantially by the landed price of subject goods. Moreover, no evidence has been submitted by any interested party to suggest that the conditions of competition between the foreign and the domestic producers have undergone any change.

**f) Contraction in Demand and Changes in Pattern of Consumption**

99. It is noted that the demand of the subject goods has increased significantly in the period of investigation as compared to the base year.

**1.4. Factors Relevant for Causal Link:**

100. The Authority notes as under:

- a) There is substantial increase in imports of subject goods from subject countries in absolute terms as well as in relation to production & consumption in India. However, the increase in imports from subject countries was necessitated due to decline in production of one of the major producer in India.
- b) The price undercutting and underselling from the subject countries in POI is positive.
- c) The dumped imports are not depressing the prices of the DI but causing suppression effect on the prices of the DI.
- d) Capacity utilisation of DI has improved throughout the injury investigation period and was at 97% during the POI (A).
- e) Profitability of DI has improved significantly during the POI (A) as compared to the earlier years. Similarly, PBIT, cash profits and ROCE has also improved significantly during the POI (A) as compared to the earlier years.

**J. POST-DISCLOSURE COMMENTS BY INTERESTED PARTIES**

101. The post disclosure submissions have been received from the interested parties. The issues raised therein have already been raised earlier during the investigation and also addressed appropriately. However, for the sake of clarity, the submissions by the interested parties are being examined as below

**J.1. Submissions by Domestic Industry**

102. Disclosure Statement should disclose injury information to the DI because the information pertains to the DI itself.
103. Non-confidential version of the verification report of the exporters/producers from the subject countries, e-mails and communications with the opposing interested parties, calculation of normal value based on DI data should be provided to the DI.
104. BGPPL cannot be considered as ineligible domestic producer because it has not produced during substantial part of POI. The data can be adjusted for determining injury but BGPPL cannot be considered as an ineligible DI.
105. The Authority has correctly proposed to reject the response file by APP group. Response of unrelated exporter is essential for determining export price and individual margin of dumping.
106. The Authority has rightfully proposed to reject the response filed by Double A Group. Related parties have not cooperated in this investigation and therefore the Authority cannot verify the information regarding domestic sales and exports made to India.
107. The Authority has rightly rejected the response filed by Phoenix Pulp and Paper Public Co. Ltd., Thailand because response is not filed by related company responsible for domestic sales and exports.
108. The Authority is right in rejecting responses in cases where the value chain is not complete. The Authority has rejected the response filed by the exporters/producers in the past when value chain was incomplete.

109. It is not clear how the Authority has come to the conclusion that there is no producer of copier paper in Singapore. The Authority is requested to recommend anti-dumping duty based on facts available for imports from Singapore.
110. Increase in imports is not due to suspension of production by BGPPL. Indian industry could have met the increased demand created as a result of suspension of production by BGPPL. Petitioners could have reduced exports, produced and sold more domestically. DI has exported the goods at a price higher than import price from the subject countries.
111. The Authority is not required to examine the cause of imports but merely required to determine increase in imports. The Authority may recommend benchmark form of duty if imports were justified by suspension of production. Benchmark form of duty would allow the imports at fair price and would also allow DI to breathe normally.
112. Market share of DI has decreased in the POI and market share of imports has increased. Fall in the market share of other Indian producers has been taken over by the imports from subject countries.
113. Import price from subject countries declined sharply in the POI without corresponding decline in costs. Import prices are below selling price and below cost of sales of the DI. The DI would suffer financial losses if were to sell the product matching prices with imports.
114. DI has not reduced selling price considering low return on investment, suspension of production of BGPPL, nature of product and market where it has opted to lose market share and accumulate inventories instead of decreasing prices.
115. Sales and production of the remaining DI producers have declined though it should have increased due to the suspension of production. Inventories with the DI has also increased significantly. Reliance on 97% capacity utilization is incorrect because the capacity is not dedicated for the product under consideration and is utilized for other products as well.
116. The Authority has ignored the submission of the DI that profits have increased due to reduction in raw material cost and the efforts put in by the DI. Ability of DI to raise capital for further investment has weakened.
117. The Authority can look at the data of inventories in the post POI period, which shows that inventories and imports have declined. DI was able to liquidate inventory upon decline in imports. Thus, there is a causal link between imports and rise in the inventory.
118. There is a threat of injury due to imports. Imports have increased by almost 370% in the POI as compared to 2015-16. Low priced imports will increase significantly and adversely affect present fragile performance of the DI.
119. Major producers of the subject product in the subject country have very high production capacity. The Authority is requested to undertake an analysis of the domestic sales - export sales ratio, prices to third countries, level of stock etc. to determine likelihood of diversion of exports to India. Absence of actual price suppression and depression is not relevant for the assessment of threat of injury. Likely price suppression and depression are relevant for assessment of threat of injury in terms of Annexure II (vii) of the Anti-dumping Rules.
120. Import price is significantly below the level of cost and selling price of the DI and given the unutilized capacity with the exporters, imports are likely to have significant price depressing and suppressing effect. The United States has imposed 21.5% countervailing duty on uncoated paper. Exports are blessed with 22% subsidies and therefore Indian industry cannot have level playing field.
121. Indian market is attractive in terms of prices. Foreign producers are able to enter the Indian market at 16% lower selling price, and can continue to do so because they have advantage of subsidy from the Government.
122. Imports have increased due to the FTAs with ASEAN countries. It can be fairly assumed that foreign producers can scale up production in a short period. Exporters from subject countries also have high export orientation and there is significant surplus across the globe forcing these countries to export at low prices.

123. Primary cause of injury to the DI is dumped imports and not suspension of production by BGPPL. Authority is required to assess what shall be relevant factors for establishing causal link in case of threat of material injury.
124. Only relevant parameters for causal link in threat of injury case are price undercutting, surplus capacities with the foreign producers, inventories with the foreign producers, comparison of landed price of import with cost of production of the DI.
125. Increase in imports, significant difference between prices offered by foreign producers and DI, exports by DI at losses, increase in inventories of DI establishes existence of causal link.
126. If the Authority determines that increase in imports is justified due to suspension of production by BGPPL, the Authority should consider imposition of benchmark form of duty. Anti-dumping duty should be imposed in US\$ because rupee has depreciated significantly.

## **J.2. Submissions by Other Interested Parties**

127. One of the opposing interested parties made the following observations:
128. Response filed by producers in Indonesia should be accepted even if there is no response filed by its unrelated exporter, who has exported around 40% of the total exports made by such Indonesian producers of the subject goods to India.
129. Investigating Authority may resort to facts available only where a party refuses access to necessary information or otherwise fails to provide necessary information within reasonable period or significantly impedes the investigation. Indonesia producers have co-operated with the DGAD and they have been duly verified.
130. Designated Authority has accepted response of producers in previous investigations where sales were made through non-co-operative unrelated producers.
131. Disclosure Statement concludes that there is no evidence regarding freely disposable or an imminent increase in capacity of the exporting producers, there is no price depression or suppression for the DI during the POI and economic parameters of the DI including profit has improved significantly during the POI(A). Therefore, no material injury or threat of material injury can be established based on the facts disclosed in the Disclosure Statement.
132. Letter requesting initiation of investigation was not submitted by Tamil Nadu Newsprint & Papers Ltd. The share of remaining domestic producers is only 44% and cannot be considered as "major proportion".
133. Imports of the subject product occupy only 8% of total demand and cannot be responsible for any material injury or threat of injury to the DI. There is fierce competition among the domestic producers of paper and if there is any injury to the DI, it is because of this reason.
134. Injury to the DI is caused by lack of availability of raw material and high price of raw material, which contributes between 40 to 50% of the total production cost of the PUC. Petitioners have incorrectly stated that imports from the subject country is the sole reason for the present injury suffered by DI.
135. The Authority cannot rely on findings of investigating authorities in other jurisdictions on uncoated paper. The Authority has to base its decision on the facts and circumstance of the present investigation.
136. The Authority should note that shutdown of the Ballarpur Industries Limited has created a gap between demand and supply in the domestic market, which led to the increase in imports.
137. The Authority has not provided sufficient time for responding to the Disclosure Statement. Interested parties only had only 5 working days to respond to the Disclosure Statement issued by the Authority.
138. According to Article 6 of the Anti-dumping Agreement, interested parties should be put to notice of the information required from them. Authority has not provided any notice to the respondents regarding non-submission of information of unrelated intermediaries. The Authority has failed to take into account the difficulties faced by the producer in responding to the questionnaire. The Authority has not issued any deficiency memo requesting for more information. Verification report issued by the Authority establishes that the data submitted and verified was in line with the requirements of the

Authority. The Authority should issue fresh Disclosure Statement considering the submissions and data of the respondent.

139. The Authority has not addressed the submission of interested parties concerning the following issues:
  - a. Injury suffered by the DI and performance of BGPPL and TNPL.
  - b. Adjustment of the impact of other factors causing injury to TNPL.
  - c. Adequacy and accuracy of evidence before initiating the investigation including lack of certification and declaration from the DI
  - d. Submission relating to causal link analysis
  - e. Submission relating to like article, confidentiality of information and threat of injury
140. Decision to remove BGPPL from the scope of the DI is arbitrary and no reason has been given for changing the scope of DI. Interested parties were not put to notice for defending their interest.
141. The three mills namely PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk (IK), PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills (PD) and PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TK) filed complete and correct information in relation to normal value and therefore rejection of their normal value is not appropriate.
142. The Authority has arbitrarily rejected the export price of the respondents on the ground that exports made through unrelated trader are substantial. Producers have no control over unrelated traders and cannot force them to participate in the investigation. The Authority carried out verification of information even though it knew of non-filing of questionnaire response implies that there is no requirement of participation by unrelated importers in law.
143. In other anti-dumping investigations, the Authority has accepted the response of the producers even though unrelated traders have not participated. Decision of the Authority is against the understanding and practice of other countries.
144. Landed value can be constructed based on ex-factory price, CFR price or FOB price. Final price at which the trader resold goods to India was included in Appendix 2.
145. Information provided in the Disclosure Statement does not leave any doubt that DI is not suffering any injury. In several recent investigations, the Authority had not recommended any anti-dumping duties despite finding significant dumping margin and injury margin on the ground that DI earned significant profit and there is no injury to the DI from the imports of subject goods.
146. There is no causal link between imports and performance of the DI. TNPL shows some signs of negative performance but due to the fact that TNPL was shut down due to water shortage. There is also no correlation between import prices and the prices of the DI.
147. The Authority must evaluate the claims of confidentiality of information. Hon'ble Supreme Court has held in the case of Sterlite Industries that Confidentiality cannot be granted automatically and should be based on thorough scrutiny.
148. The Authority should confirm the scope of product under consideration as disclosed in the notice of initiation and Disclosure Statement in its final findings.
149. The Authority has correctly assessed the scope of DI and is right in excluding BGPPL from the scope of DI for the purpose of injury determination.
150. APRIL Group has raised the following issues with respect to their dumping margin calculation:
  - a. Jakarta office of April group is only involved in domestic sales and accordingly its expenses are directly relatable to domestic sales. Such expenses should be deducted from calculation of normal value. Such rejection of deductions is especially unfair given the fact that Authority has made a deduction from the export price for both G&A expenses of the Indian office as well as G&A expenses of the Singapore/Macau exporters on the premise that such expenses solely relate to exports.



- b. Similarly, advertisement expenses are also directly linked with domestic sales made by the producers in the domestic market and should be allowed by the Authority while determining the ex-factory normal value.
  - c. Producers and exporters of April Group are acting as single economic entity and all the exports of PUC and non-PUC produced by the producers are being undertaken by the related export companies. Profit & indirect SGA expenses of related exporters should not have been reduced while arriving at the net export price as related exporters in Singapore/Macao are acting as a marketing arm of the producers.
151. There is no injury to the DI as per the analysis of economic parameters contained in the Disclosure Statement. Analysis of economic parameters shows that performance of the DI has improved during the injury investigation period.
152. As per the Judgment of Gujarat High Court in Nirma Ltd. Vs. Union of India, Injury margin is relevant only to determine the quantum of anti-dumping duty. Existence of injury margin is irrelevant while determining whether the DI is suffering any injury or not because of dumped imports.
153. The Authority has correctly determined that there is no price suppression and price depression due to imports of subject product. In paragraph 100(c), the Authority has inadvertently noted that there is price suppression due to imports from subject countries.
154. Another interested party has observed with regard to rejection of its questionnaire response due to absence of response from the related party involved in the domestic sales:
- a. Resale price of related entity to independent customers were verified and prices of goods sold by related entity and goods sold to unrelated entity were comparable. Audited accounts of related entity were also verified. Verification report issued by the Authority noted these facts.
  - b. Income of related entity, comparison of prices to independent customers by related entities and by the producers, transaction by transaction details of sales made by the related entity is now provided for the ready reference.
  - c. There are no provisions in Act, Rules, Notifications, Trade Notices or other instructions that require a related entity involved in domestic sales in the exporting country to file a separate response.
  - d. Information provided by the producer fulfilled all the criteria under Paragraph 3 of Annex II of the Anti-dumping Agreement. Information cannot be rejected merely because it is not ideal.
  - e. Not informing the exporter/ producer about rejection of its response is in violation of procedural safeguards prescribed in para 6 of the Annex II of the Anti-dumping Agreement.
  - f. There was no problem with regard to the use of export price. Export price information must be accepted. Conditions specified in Article 6.8 of the Anti-dumping Agreement for rejection of questionnaire response are not met and therefore there cannot be rejection of normal value and export price in this case.

### **J.3. Examination by the Authority**

155. The Authority has disclosed injury information and other relevant information to the interested parties and the DI which would enable them to provide meaningful comments.
156. There is no past practice of the Authority to disclose verification report. Further, this information is confidential in nature and not amenable to summarization. The Authority does not disclose the verification reports of DI to other interested parties and *vice-versa*.
157. The Authority has determined the dumping margin for the co-operating parties as per the Anti-Dumping Rules and also in accordance with its consistent practice.
158. Interested parties raised a claim that BGPPL should be excluded from the scope of DI for the purpose of injury assessment. DI also agreed for assessment of injury after excluding the performance of BGPPL. The Authority examined the issue and determined that BGPPL should be excluded from the scope of DI

because it was not producing the subject goods for a major part of the POI due to its own intrinsic reasons.

159. Assessment of material injury was based on submissions made by interested parties, and information received from the DI after sufficient verification. The Authority has followed its standard practice and maintained the established sequence in the investigation proceedings by issuing the Disclosure Statement containing essential facts under consideration before the issuance of final findings. Thus, it cannot be claimed that interested parties were not put to notice before the issuance of Disclosure Statement regarding such assessment of injury. No new claims have been raised by the DI or interested parties in this regard.
160. In any case, facts disclosed in the Disclosure Statement are not the final recommendation of the Authority. Opportunity has been provided to interested parties to respond to the Disclosure Statement and the Authority will issue its final decision after considering the comments made by all the interested parties. Thus, it cannot be said that the interested parties have not been put to notice to enable them to defend.
161. Increase in imports took place as a result of suspension of production by BGPPL. It is pertinent to note that other Indian producers i.e. excluding the petitioners (including BGPPL) were able to increase their sales in the POI. Thus, it is incorrect to state that DI was not able to increase production and sale in the POI due to increase in imports.
162. DI has not provided any information to substantiate its claim that high capacity utilization should not be relied on because it also includes other products which are not covered within the scope of the present investigation.
163. The Authority has already examined the claims made by interested parties regarding assessment of economic parameters in the Disclosure Statement. No new information and comments are submitted by the interested parties or the DI in this regard.
164. DI has submitted post POI import data to show that imports from subject countries and inventories have reduced in the post POI period. DI has also submitted that BGPPL has been able to restart its production even though it is not operating at full scale. The information submitted by the DI corroborates the examination made by the Authority that there is no continuing threat of injury to the DI.
165. Subsidization by the Government of Indonesia is outside the scope of the present anti-dumping investigation and cannot be investigated to substantiate the claim regarding threat of injury. All the other claims made by the DI regarding the existence of threat of injury are examined by the Authority in the Disclosure Statement.
166. A total of 7 days i.e., 5 working days, were provided by the Authority to respond to the Disclosure Statement. The 5 working days' time provided to the interested parties by the Authority to respond to the Disclosure Statement is adequate and is in accordance with its consistent practice of the Authority in past investigations. It is also required to be noted that Anti-dumping investigations are time-bound and therefore the investigation process is required to be completed within the prescribed time frame. There is no violation of principles of natural justice.
167. In the application, the DI had inadvertently missed to enclose the certification of TNPL. This does not affect the initiation of investigation or standing of the DI. No new information or argument has been made regarding the issue of adequacy and accuracy of evidence was highlighted.
168. Claims regarding confidentiality were examined by the Authority in Section E of the Disclosure Statement. No new claims or submissions has been made in this regard by the interested parties or the DI. The Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties.
169. The Authority has assessed overall injury to the DI after excluding the performance of BGPPL. Water shortage in Tamil Nadu and other factors allegedly causing injury to TNPL does not appear to affect the overall performance of the DI.

170. As regards the requirement of participation of unrelated trader, the Authority notes that a producer may not always be in a position to ensure participation of the unrelated traders. However, the Authority cannot determine export price to India of subject goods exported, if unrelated traders who are responsible for a significant portion of the exports to India do not file questionnaire response. Consequently, the Authority cannot determine individual dumping for such producer/ exporter. This requires an assessment of the impact of the non-participation of the unresponsive and unrelated exporters on the Authority's ability to fairly evaluate the dumping and injury claims. In this case the extent of exports to India by the unrelated trader is close to 40%, which by any measure is a significant portion. Further, it is noted that the unrelated trader is actually exporting the subject goods to the Indian subsidiary of the producer, this certainly calls into question the claim of lack of control over such a trader.
171. Response of exporters involved in the sale of subject goods to India is required for assessment of injury margin also. If the exporter does not file questionnaire response, the Authority cannot know the price actually paid for the goods when sold for exports to India and cannot determine the correct landed value of the subject goods, which is required for assessment of injury margin.
172. Authority cannot rely on the information provided by the producer regarding the final price at which the trader resold the goods to India. Correctness of such information cannot be verified if the trader does not file the questionnaire response and participates in the investigation process. This is particularly so, for traders related to the producers and on whom, it can be reasonably inferred, the producer has control and can ensure full participation in the investigation.

#### **K. SUBMISSIONS CONSEQUENT TO THE HIGH COURT ORDERS**

##### **K.1. Submission by Petitioner (Exporter)**

173. Post-Disclosure comments received from M/s PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk; PT Pindo Delhi Pulp & Paper Mills (PD); and PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk ("Petitioners")
174. Fresh hearing should be granted by the Authority because new facts have been introduced and new issues are raised in the Disclosure Statement.
175. Imposition of residual duty due to non-filing of questionnaire response by the unrelated trader is not supported by any provision in law. Getting participation from unrelated trader is beyond their control.
176. Authority has not raised any deficiency memo or supplemental questionnaire requesting information from unrelated traders.
177. The fact that verification was carried out despite non-filing of questionnaire response is a testimony to the fact that this requirement is neither relevant nor required by law.
178. Information regarding sales made to India through unrelated traders was provided to the Authority in the questionnaire response. Thus, all necessary information was made known to the Authority.
179. Unrelated trader has no obligation to file questionnaire response. In any case, unrelated trader was never put to notice to file the questionnaire response. Moreover, the unrelated trader in question is not physically exporting the subject goods from Singapore but the goods are shipped to India from Indonesia. The unrelated trader is only involved in issuance of invoices.
180. The Authority has recommended individual dumping margin in other cases in the past even when there was no cooperation from the unrelated traders. It would be completely illegal to introduce any quantitative yardstick in relation to the quantum of sales through "unrelated trader" for deciding whether the response of the cooperating exporters has to be accepted or rejected. Moreover, in this case, the export to India for which the responses have been filed are very significant i.e. more than 60%.
181. Court has clearly expressed that the information available on record with regard to about 60% of the exports to India, must be looked into which clearly implies that the decision of the Designated Authority to treat the entire group as non-cooperative was not correct.
182. There is no affiliated importer entity in India of the Respondents. APP(India) Paper Private Ltd. is not a company affiliated with respondents either by shareholding or by directorship.

183. Rejection of the normal value is incorrect since all three mills of the Respondents provided complete information and the information was also verified during the investigation proceedings.
184. Information regarding export prices should be accepted because complete information necessary for determination of ex-factory export price is available. Ex-factory export price in accordance with Section 9A(1)(b) is known to the authority i.e. export price of the respondents to unrelated intermediary is known to the Authority through their questionnaire response and therefore question of constructing the export price does not arise. There is no averment about any compensatory arrangement between the unrelated intermediary and the respondents or even the importer in India.
185. Even if export price is rejected APP group cannot be treated as non-cooperative as full data and information was made available and was verified by the Authority.
186. If producer knows at the time of the first sale that the product is eventually destined for the Indian market, that price information of first sale is relevant for calculating export price. This interpretation of definition of export sale is followed by the European Commission, the United States and Australia.
187. Landed value is easily determinable in the facts and circumstances of this case. CIF prices of M/s Leaconfield's sales to India were duly included in the Appendix 2 of the questionnaire response. Authority is required to add port handling charges, cess and basic customs duties to arrive at the landed value. This information was verified during the verification visit. Moreover, importers questionnaire response of APP (India) Pvt. Ltd. has complete details of Imports with actual CIF prices. The CIF prices are also verifiable from transaction wise DGCI&S import data. Where transactions are based on CFR prices, it has been consistent practice of the Designated Authority to add element of notional insurance.

## **K.2. Submissions by Respondent (Domestic Industry)**

188. Questionnaire response of the exporter concerned is vital for establishment of export price in the present case and the exporter concerned has failed to cooperate. The price at which the goods have been sold to Indian importer, which is vital to establish the export price, cannot be established without questionnaire response of the exporter.
189. The transactions between the producer and exporter per se are insufficient to determine export price. These merely constitute international sales transactions between two parties and per se are insufficient to establish export price. Export price determination requires information and evidence with regard to the price at which the goods have been invoiced onto the Indian importer.
190. In a situation where an affiliate of the producer is one of the importers of the product and has arranged imports for other importers, the producer cannot contend that it could not have sought cooperation.
191. Rejection of a questionnaire response in case of non-cooperation by the exporter concerned is an established practice of the Authority, as established by the final findings notified by the Designated Authority in the matters of USB Flash Drive, Acetone, Hot Rolled Flat Products-304, Solar Cells, PTA, MDF etc. These are only illustrative. There are in fact several cases decided on this basis.
192. Even in the present investigation PT Indah, a group company of the APP group, Indonesia has not filed a complete questionnaire response as despite the existence of related parties, namely M/s Leaconfield, Singapore, engaged in the production/sale of the PUC the same have not come forward.
193. PT Indah and Leaconfield have significant business transactions and business in excess of US\$ 15 million per annum and to the extent that even related party of the producer in India places orders with Leaconfield and not directly with its own Indonesian producer. This is done for some other purpose. In any case, under these circumstances, the producer cannot plead inability to seek questionnaire response.
194. The absence of questionnaire response from Leaconfield is not due to inability of the company but due to wilful decision of the parties not to file questionnaire response, in order to suppress vital facts from the Designated Authority, as is readily established by significant difference between the price at which the producer sold the product and the price at which goods were invoiced onto the Indian consumers.
195. Questionnaire response filed by the producer is incomplete additionally on the ground that the exporters concerned have exported goods produced by not only participating producer but also by non-participating unrelated producers from subject countries. This is one of the reasons for suppression of questionnaire response of the exporter.
196. Perusal of the exporters' questionnaire prescribed by the Authority shows that it is envisaged therein that the dumping margins are (a) for exporting producers and (b) exporters who are not producers of the

subject goods. In later situation, the exporters are required to seek cooperation of the producer concerned for determination of normal value. In former situation, exporter's cooperation and response becomes important in view of the fact that the ultimate price at which the goods have been exported to India are by that of the exporter.

197. Evidences provided by the domestic industry in the form of website extracts establish the facts that (a) M/s Leaconfield does significant business with PT Indah (as it procures the goods from PT Indah) and (b) Leaconfield Capital PTE. Ltd. is an Exempt Private Company Limited, engaged in wholesale of paper and paper products, having business in excess of US\$ 15 million on a regular basis. In such a situation, it is beyond any reasonable comprehension that such a producer is not in a position to seek cooperation and questionnaire response of an exporter undertaking such significant exports of its products.
198. The producer cannot claim that it has fully cooperated with the DA, when the company who is responsible for significant 40% of the shipments has not filed questionnaire response. It cannot be lost sight of the fact that the exporting company is middle man between the producer and Indian importers, which inter-alia includes the producers own affiliated company (APP India Paper Pvt. Ltd.).
199. It is a case where there is a wilful non-cooperation and vital suppression of facts and non-filing of questionnaire response for the reason that the same is highly inconvenient to the producer in establishing "no dumping".
200. For the purpose of export price verification, Designated Authority requires documents such as sales invoice, proof of payment received against sale invoice, proof of bank charges paid, Purchases order, ocean freight - bill and payment proof, Insurance, appropriateness of the export price in the light of purchase price to show that there was no loss on these sales, party account statement – these are with exporter and producer is not privy to such documents.
201. It is evident from the exporter's questionnaire that the Designated Authority presupposes that the party responding to the Designated Authority may be a trading/exporting company and not producing company as it specifically seeks reply to certain questions in case the response is not being filed by a producer who is an exporter.
202. There are very significant imports from Singapore at a price materially below the price at which imports have occurred from Indonesia. Table below summaries. The extent of price difference is quite alarming and is in fact a reason for non-participation by the exporter in the present investigation.

SN	Country	Volume (MT)	Rate (Rs/MT)	Share %
1	Subject Countries	73,897	47,461	98%
2	Indonesia	48,522	49,670	64%
3	Thailand	4,259	56,215	6%
4	Singapore	21,116	40,619	28%
5	Other Countries	1,438	54,237	2%
6	Grand Total	75,335	47,590	100%

203. The opportunity for deficiencies cannot be utilised for filing a questionnaire response, for which there are clear and strict time limits. The DA is responsible only for raising deficiencies in the questionnaire response. If a party is completely missing from questionnaire response, it is a case of incomplete questionnaire response, wilful withholding of response.
204. A perusal of NCV clearly shows that the facts now brought on record by APP are nowhere to be found in their NCV questionnaire response. This further shows that APP had resorted to significant suppression of fact wilfully in the NCV of questionnaire response which in fact prevented the domestic industry from effectively participating in the present investigation.
205. The producer has now raised an issue that Authority has conducted verification did not raise the issue of non-cooperation by the unrelated exporters wherein it pertinent to note in this regard that the producer himself did not bring all facts on records appropriately during the course of the investigations and resorted to significant suppression of facts. Since the producer resorted to significant suppression of facts, it cannot blame the authority for rejecting the response.

206. The Authority has in the past several cases rejected questionnaire response whenever the response of the producer was incomplete. If duty has been given for a channel when some exporter has not filed questionnaire response, it is only in those situations where the missing response did not constitute significant proportion. In the instant case, however, the missing response constituted very significant proportion in total exports made by the company.
207. With regard to cases referred by the producer, petitioner domestic industry submits that the reliance is totally misplaced for the following reasons:
208. In the Polypropelene case, the duties were determined for the chain which cooperated, which clearly means that the questionnaire response of the exporter is important. It does not mean that even if such exporter commands as high as 40% of the exports, the Designated Authority is nevertheless bound to determine dumping margin for such producer.
209. In the PSF case, the subject goods were exported by the producer directly and through five (5) unrelated traders. Out of which one related exporter did not respond and since majority of the response has been filed, the Authority accepted response. It is a case where non cooperative exporter exports were quite low.
210. In the Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel case the related importers did not respond in the investigation. The Authority found that the export price was not impacted by the relationship and thus export price determination was not affected without questionnaire response from such unrelated exporter
211. The response of the exporter is relevant for the reason that the Designated Authority is required to cross verify the claims made by the exporter-producer with the price reported in Indian customs. Without cooperation of the exporter concerned, the Designated Authority cannot verify the correctness of the price claimed. The producer cannot establish the price at which the goods have been reported to Indian customs. Only the exporter concerned can provide the same.
212. With regard to reference to hydrogen peroxides case, the reliance is totally misplaced for the reason that the issue involved therein was scope of domestic industry and its eligibility due to alleged relationship. The investigation in that case showed that the foreign producer did not participate in the business activity of the Indian industry. In the instant case, the producer and importer are having regular significant business. Further, the relationship between the two is established by the fact that Bina Sinar Amity Transportation Services Singapore Pte Ltd is the 100% shareholder of APP India which is a part of Sina Mas Group which in turn is the parent company of APP.

### **K.3. Examination by the Authority**

213. Section 9A(1)(b) of the Customs Tariff Act provides that export price in relation to an article, means the price of the article at which it is exported from the exporting country or territory. It can be argued by a producer that the price at which the producer has sold the goods to the trader can be the basis for determining ex-factory export price. However, the argument is incorrect because ex-factory export price is to be worked out based on the price at which the goods were sold by the trader/ exporter to India. Authority is required to deduct selling expenses incurred by the producer as well as the trader to calculate ex-factory export price. Due to absence of response from the exporter, selling expenses incurred by the exporter are not available for examination and verification by the Authority. Consequently, individual margin of dumping cannot be determined based only on the response of the producer. Also, the Authority will not know whether the subject goods were exported at higher price or at lower price by suffering losses. For example, if the producer sold the goods to trader at 10 USD/MT, the trader may have exported the subject goods to India at 9 USD/MT by incurring losses and aggravating the extent of dumping.
214. Further, the Authority notes that determination of export price is a crucial step in anti-dumping investigations to ensure fair comparison amongst all the exporters. The Authority does this by considering the export price and normal value at the same level of trade. It is the established practice of the Authority, to compare the export price and normal value at the ex-factory level. To arrive at a comparable export price, appropriate adjustments are required to be made in export price, depending upon how it is quoted - CIF/FOB/FOR etc.

215. Since determination of dumping margin is made for each co-operating producer, this requires determination of net export price for each of the channels of exports identified and a weighted average obtained thereof. The channels, each of which are equally important, normally are:
- Exports directly to unrelated Indian importers;
  - Exports to a related Indian importer who in turn re-sells to unrelated Indian customers;
  - Exports through an unrelated exporter (in any country) to unrelated Indian importer; and
  - Exports through a related exporter (in any country) to unrelated Indian importer.
216. Thus, it is mandatory for responding producers to file a complete response in respect of all its trade channels to India. In cases where the exports are through unrelated exporter/ trader, the response from the unrelated entities are also required. This will be particularly so, in cases where the share of exports to India of unrelated exporters not participating in the investigation constitutes a significant proportion of the exports of the concerned producer. In such cases the responding producer would be considered non-cooperative in general and the entire response is liable to be rejected.
217. In the instant case where the unrelated exporter, M/s Leaconfield, Singapore, is exporting about 40% of the producer's exports to India. Which it is supplying to a seemingly related party in India, namely APP (India) Paper Private Limited (the contact details of who are available on APP Groups own website). It is difficult for the Authority to accept that the producer is unable to exercise the bare level of control required to have the unrelated exporter cooperate and provide data/ details of the transactions relating to its exports to what appears to be a related entity in India.

#### **L. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES**

218. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the DI by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the Country.

#### **M. CONCLUSION**

219. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that the product under consideration has been exported to India from subject countries below their normal values and consequently, the DI has suffered material injury. Material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject countries during the POI.

#### **N. RECOMMENDATION**

220. In view of positive determination of dumping and injury on account of dumped imports from Thailand, Indonesia and Singapore, the Authority is of the opinion that anti-dumping measures need to be imposed on dumped imports from the subject countries. The Authority considers it necessary and recommends anti-dumping duty on imports of subject goods from subject countries in the form and manner described hereunder.
221. The Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of the 'margin of dumping' and 'margin of injury', on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, for a period of three (3) years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, as the difference between the landed value of the subject goods and the amount indicated in Col. 8 of the duty table appended below, provided the landed value is less than the value indicated in Col 8.

**Duty Table**

SN	Heading/ Sub heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount (US\$/MT)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	4802*	Uncoated paper in rectangular sheet of following sizes,	Indonesia	Indonesia/ Singapore	क) PT Riau Andalan Kertas	क) April Fine Paper Trading Pte Ltd	855.01

		with permissible limits (a) 210mm x 297 mm also known as A4 size; (b) 297mm x 420mm also known as A3 size; (c) 215mm x 345mm			३) PT Anugrah Kertas Utama ४) PT Asia Pacific Rayon	३) April International Enterprise Pte Ltd ४) April Fine Paper Macao Commercial Offshore Limited	
2.	- do -	- do -	Indonesia	Indonesia/Singapore	Any combination other than S. No. 1		855.01
3.	- do -	- do -	Indonesia	Any country	Any	Any	855.01
4.	- do -	- do -	Any country other than those subject to anti-dumping duty	Indonesia/Singapore	Any	Any	855.01
5.	- do -	- do -	Thailand	Any country	Any	Any	855.01
6.	- do -	- do -	Any country other than those subject to anti-dumping duty	Thailand	Any	Any	855.01

*\* Custom classification is only indicative and the determination of the duty shall be made as per the description of PUC*

222. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.
223. An appeal against the order of the Central Government arising out of this finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority